



# कुरुक्षेत्र



वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 8 ★ पृष्ठ : 56 ★ ज्येष्ठ-आषाढ़ 1940 ★ जून 2018

प्रधान संपादक  
दीपिका कच्छल  
वरिष्ठ संपादक  
ललिता शुराना  
संपादकीय पत्र—व्यवहार  
संपादक  
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003  
दूरभाष : 011-24365925  
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in  
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

विनोद कुमार शीर्मा

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453  
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण

आशा सक्सेना

सज्जा

मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये



## इस अंक में

	प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण भारत	डॉ. विनीता सिंघल	5
	नए उभरते भारत की परिकल्पना	प्रो. सुमन पांडेचा, मीनाक्षी अहीर	11
	कृषि विकास पर टिका ग्रामीण विकास	डॉ. के.एन. तिवारी	15
	कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां	नरेश सिरोही	21
	गांवों में शिक्षा की अलग जगता सर्व शिक्षा अभियान	सुरभि जैन और पूरबी पटनायक	25
	भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बढ़ावा दायरा	---	29
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	---	30
	ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन	ए. सूजा	31
	स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास	आशुतोष कुमार सिंह	37
	महिलाओं की उन्नति के खुलते नए द्वार	सिद्धार्थ झा	42
	लोगों की मानसिकता बदलता स्वच्छ भारत अभियान	संजय श्रीवास्तव	47
	जैव ईधन पर राष्ट्रीय नीति-2018	---	51
	ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट	---	53
	स्वच्छता सर्वेक्षण 2018	---	54

**कुरुक्षेत्र** की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011-24367453

**कुरुक्षेत्र** में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

# संपादकीय

देश की 70 प्रतिशत आबादी चूंकि आज भी गांवों में रहती है, ऐसे में भारत की समृद्धि गांवों के विकास पर ही टिकी है। सरकार भी इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। वैसे तो आजादी के बाद से देश की प्रगति के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं किंतु उन प्रयासों की गति इतनी धीमी रही कि गांवों तक विकास के लाभ बेहद कम पहुंच पाए।

निसंदेह पिछले कुछ सालों में हालात काफी बदले हैं। वर्तमान सरकार देश के गांवों, किसानों, गरीबों और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प होकर हर मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। साथ ही, किसानों की आय दोगुनी करना, सभी को शिक्षा, आवास, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश को 2 अक्टूबर, 2019 तक शौचमुक्त और स्वच्छ—सुंदर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के हर गरीब व्यक्ति के पास अपना घर हो और हर घर में बिजली, पानी, शौचालय जलनिकासी की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो; हर गांव सड़क मार्ग से शहरों से जुड़ा हो; हर व्यक्ति के पास रोजगार हो और किसानों को न केवल उनकी फसलों की संपूर्ण सुरक्षा दी जाए बल्कि उनकी आमदनी को भी 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि में तकनीकी सहयोग से उत्पादन बढ़ाने और किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में देश में 11 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ—साथ खाद पर भी खर्च कम हो रही है। यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग से भी खाद की खपत कम हुई है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है।

किसानों के हित में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और बड़े पैमाने पर बजट भी उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बेहद कम प्रीमियम पर उन्हें पूर्ण बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विज़न पर काम हो रहा है; प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए खेत से लेकर बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। बजट 2018–19 में ऑपरेशन ग्रीन की भी घोषणा की गई है जिससे फल, सब्जी पैदा करने वाले और खासतौर से टमाटर, प्याज, आलू उगाने वाले किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसी वर्ष के बजट में सरकार ने अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का कम से कम डेढ़ गुना दिया जाना तय किया है। यही नहीं, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सके, इसके लिए देश भर में राष्ट्रीय कृषि बाजार भी स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों और स्वयंसहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने हेतु देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड कर एपीएमपी और ई—नाम प्लेटफार्म के साथ जोड़े जाने की भी योजना है। किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे बेच सकेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने सहित रोजगार और कृषि—आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र बनेंगे। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार एफपीओ को भी बढ़ावा दे रही है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चलते गांवों में रोजगार के अवसर काफी बढ़े हैं जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण बहुत तेजी से औसतन 134 किमी./दिन की रफ्तार से हो रहा है। मनरेगा में प्रत्येक परिसंपत्ति की जियो टेगिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पूरी पारदर्शिता आई है।

2022 तक 'सबसे लिए आवास' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई—जी के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ तथा 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों से आवास निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। इन जानकारियों में धनराशि की अंतिम किस्त, भूटैगिंग फोटो आदि शामिल हैं। 40.25 लाख आवासों की जानकारियां अपलोड की जा चुकी हैं। लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का तेजी से निर्माण संभव हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से कार्यक्रम का पारदर्शितापूर्ण और निर्बाध तथा बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। पीएमएवाई—जी के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति आदि सुविधाओं से ग्रामीण भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीबों को सक्षम तथा सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। यूएनडीपी—आईआईटी दिल्ली ने आवासों के 168 डिजाइन तैयार किए हैं। इन आवास डिजाइनों में लागत कम आती है तथा ये आपदा प्रतिरोधी भी हैं। इससे ग्रामीण परिदृश्य में सुखद बदलाव हो रहा है। गरीब लोगों को रहने के लिए सुरक्षित आवास प्राप्त हो रहे हैं जहां वे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकते हैं।

गांवों में तीव्र गति से विकास कार्य चल रहे हैं, हर व्यक्ति विकास प्रक्रिया में भागीदार बनने को तत्पर लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में "आज हर भारतीय न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें; जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकें, उन्हें पूरा कर सकें।" निसंदेह भारत का नवनिर्माण हो रहा है जहां गरीबों के स्वप्नों को आकार मिल रहा है; और किसानों के लिए भी आशा की नई किरण जागी है।

# प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण भारत

—डॉ विनीता सिंघल

हमारे गांव बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती, साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता सहित आज हर गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के तहत हर राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ा जा रहा है जिससे उनको हर बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सकें। साथ ही हर गरीब एवं वंचित को आवास और हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है।

**9** अगस्त 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने तक गरीबी उन्मूलन की बात कही थी। 'मिशन अंत्योदय' का कार्यान्वयन इसी का परिणाम है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य केवल लोगों के आर्थिक विकास से नहीं बल्कि विशाल सामाजिक परिवर्तन से है। भारत के आर्थिक विकास के लिए भी ग्रामीण विकास सबसे जरूरी है। किसानों की समृद्धि और पंचायती राज को मजबूत बनाने और गरीबों एवं वंचितों के कल्याण, युवाओं को रोजगार और सभी को शिक्षा के उद्देश्य के साथ ही गांवों का विकास संभव है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना, गांव के कमज़ोर वर्गों के लिए घर बनवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, पानी की निकासी की सही व्यवस्था करना, गांवों में बिजली उपलब्ध कराना एवं लोगों को जागरूक करना ग्रामीण विकास के ही पहलू हैं।

भारत मूल रूप से एक कृषि निर्भर देश है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत

में ग्रामीण क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और लागू करवाने वाला शीर्ष निकाय है। जिस देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी मिट्टी से जुड़ी हो, उस देश का विकास निश्चित रूप से मिट्टी से जुड़ कर ही होगा। ग्रामीण भारत में कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां आजीविका का प्रमुख साधन हैं। भारत सरकार के इस दिशा में किए जा रहे किसान हितकारी प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। लेकिन आज पानी की कमी के चलते सूखी धरती खेती के लिए समस्या बनी हुई है। हाल ही में सरकार ने खेती से जुड़ी अनेक कृषि विकास योजनाओं की घोषणा की है जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा परीक्षण कार्ड, पशुपालन और मछली पालन, बूंद-बूंद सिंचाई के महत्व, नीम कोटेड यूरिया आदि। इतना ही नहीं किसानों की आमदनी 2022 तक दो गुनी कैसे हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सूखे की समस्या से निजात मिल जाएगी। 'हर खेत को पानी' पहुंचाने



के लिए यह योजना शुरू की गई है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों और कुंओं की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जाना है और ज्यादा से ज्यादा खेतों को सिंचित क्षेत्र में लाया जाएगा। सिर्फ सिंचाई ही नहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ऐसी स्कीमें हैं जिन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी की जांच कराके, उसकी जरूरत के हिसाब से खाद डाली जाए तो खर्च भी कम होगा और फसल भी अच्छी होगी। सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इससे जैविक कचरे का उपयोग खाद की तरह करने से खाद का खर्च भी बचेगा और जमीन भी ज्यादा उपजाऊ बनेगी और उपज ज्यादा पौष्टिक होगी।

सरकार ने अनेक किसान सेंटर खोले हैं, जहां से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। वहां बहुत—सी फसलों के अच्छी किस्मों के बीज भी मिलते हैं। नई—नई किस्मों को महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में उगाकर फसलों की अधिक पैदावार ले रहे हैं। जो किसान केवल खेती करते हैं, वो फसल खराब हो जाने पर या फिर मुनाफा कम होने पर टूट जाते हैं लेकिन अगर वो खेती के साथ पशुपालन भी करें तो पोषण का, आमदनी का साधन बना रहता है। भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। केवल खेती पर निर्भर न रह कर साथ में मछली पालन, मवेशी पालन जैसे खेती संबंध कार्य करने चाहिए। सरकार ऐसे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने हेतु व्यापक कदम उठा रही है। गोपशुओं की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना भी शुरू की गई है।

पशुपालन करने वालों के लिए भी बहुत—सी योजनाएं हैं जैसेकि पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई—पशुधन हाट। स्वास्थ्य—पत्र से किसानों को अपने पशुओं के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। इसकी मदद ये वो रिकॉर्ड रख पाएंगे कि उन्हें कब किस गाय या भैंस को टीका लगवाना है। इस पत्र में पशुओं की बीमारियों की भी जानकारी होगी।

### प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह योजना इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फसल बीमा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। अब सबको सब जगह एक—सी मदद। अब जिलेवार और फसलवार अलग—अलग बीमा नहीं होगा। अगर कोई किसान 30,000 की फसल उगाता है तो उसकी फसल का बीमा भी 30,000 का होगा। और अगर कल को उसकी फसल खराब हो जाए तो उसे बीमे का पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। सरकार अपना हिस्सा उसमें से काट लेती थी। अब फसल खराब होते ही बीमे की रकम का 25 फीसदी तो तुरंत मिल जाएगा और बाकी का नुकसान का

ठीक—ठीक पता लगाने के बाद मिलेगा। अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, बारिश से फसल को होने वाले नुकसान का पता ड्झोन और उपग्रहों के जरिए लगाया जाएगा। इससे बीमा योजना में मौजूद भ्रष्टाचार भी दूर होगा। उससे फसल को होने वाले नुकसान का बिल्कुल सही—सही पता चलेगा और बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह नहीं कर पाएंगी और किसानों को सही—सही मुआवजा मिलेगा।

### राष्ट्रीय कृषि बाजार

किसानों की एक बड़ी समस्या यह है कि किसानों द्वारा उत्पादित काफी मात्रा में फलों एवं सब्जियों का या तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता या फिर वे बाजार में नहीं पहुंचते। इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ई—नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। इस पोर्टल पर सारी मंडियां आएंगी। ई—नाम के इस पोर्टल को एक अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार के रूप में डिजाइन किया गया, 14 अप्रैल, 2016 को 8 राज्यों की 21 मंडियां ई—नाम से जुड़ गई। 1 फरवरी, 2018 तक यह संख्या 479 मंडियों तक पहुंच गई जो कि 14 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में है। ई—नाम वेबसाइट अब 8 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। जबकि ऑनलाइन व्यापार की सुविधा 6 भाषाओं में उपलब्ध है। अब किसान मोल—भाव कर सकता है। सीधी—सी बात है — उत्तम फसल उत्तम ईनाम। किसानों की सुविधा के लिए कई मोबाइल एप भी उपलब्ध हैं। किसान सुविधा, पूसा कृषि, एग्री मार्केट और फसल बीमा कुछ प्रमुख एप हैं।

### अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 9 मई, 2015 से शुरू इस योजना के 3 साल पूरे होने पर इस स्कीम के सदस्यों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। वर्तमान में इस योजना के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1.10 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटिड पेंशन वाली इस स्कीम अर्थात् अटल पेंशन योजना के तहत किसानों सहित असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्सेदारी कुल श्रमबल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000 रुपये/2000 रुपये/3000 रुपये/4000 रुपये अथवा 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी जो सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करेगी। संबंधित सदस्य की पत्नी/पति भी पेंशन पाने के हकदार हैं और नामित व्यक्ति को संचित पेंशन राशि दी जाएगी।

एपीवाई के तहत ग्राहक आधार कई गुना बढ़कर वर्तमान—स्तर पर पहुंचा है और एपीवाई की पेशकश सभी बैंकों और डाकघरों द्वारा की जाती है। अब तक अटल पेंशन योजना के तहत 3950 करोड़ रुपये का अंशदान एकत्र हुआ है। इस योजना ने अपने

## ગાંવો કે અંધેરે કો દૂર કરતી સૌર ઊર્જા

વર્ષ 2019 તક ઘર-ઘર મેં બિજલી પહુંચાને કે પ્રધાનમંત્રી કે સંકલ્પ કો પૂરા કરના એક ચુનાતી હૈ જિસે પૂરા કરને કે લિએ નવીકરણીય ઊર્જા સબસે મહત્વપૂર્ણ વિકલ્પ હૈ। ભારત કી વિદ્યુતીકરણ યોજના કા મુખ્ય સાધન હૈ સૌર ઊર્જા ઔર ઇસમે 10 સે 500 કિલોવાટ કી ક્ષમતા વાળી મિની ગ્રિડ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભા રહી હુંદી હૈ। મિની ગ્રિડ નવીકરણીય ઊર્જા કી સંભાવનાઓં કા ઉપયોગ કરતી હૈ ઔર બિજલી કી માંગ કો પૂરા કરતી હૈનું। ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં મેં ઇનકી કાફી માંગ હૈ।

આજ ભી ગ્રામીણ ભારત કે લગભગ 30 કરોડ લોગ ઊર્જા કે લિએ સદિયોં પુરાને તરીકોં જૈસે કિ મિટ્ટી કા તેલ, ડીજલ યા લકડી સે જલાએ જાને વાલે ચૂલ્હોં આદિ કા પ્રયોગ કર રહે હુંદી હૈનું। સૌર ઊર્જા ન કેવલ ઇસ વૃહદ અવસરચનાત્મક કમી કો પૂરા કરને કા એક અવસર પ્રદાન કરતી હૈ બલ્કિ સામાજિક, આર્થિક, પર્યાવરણ ઔર સ્વાસ્થ્ય કો બેહતર બનાને કા ભી સાધન હૈ। પિછલે ચાર વર્ષોં મેં સૌર-સંયંત્રોં કી સ્થાપના કી કીમતોં મેં આઈ 70 પ્રતિશત તક કમી ને નિજી કંપનીઓં ઔર ઉદ્યમિયોં કો આકર્ષિત કિયા હૈ ઔર યહ વાસ્તવ મેં અંધેરે મેં જી રહે લાખોં લોગોં કે જીવન મેં રોશની કી કિરણ લેકર આઈ હૈ।

સૌર ઊર્જા કી વિકંદ્રિત એવં મુદ્યૂલ પ્રકૃતિ કા હોને કે કારણ, ઇસે વિભિન્ન ગ્રામીણ ઉપયોગોં કે લિએ સ્થાપિત કરના સરલ હૈ જિસકા પ્રભાવ ગ્રામીણ લોગોં કી ઉત્પાદકતા, સુરક્ષા, સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા, પેયજલ ઉપલબ્ધતા ઔર જીવનશૈલી પર હોગા। સૌર ઊર્જા કા એક મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગ હૈ- એગ્રી પંપ જિસમેં ભારતીય કિસાનોં કી ઉત્પાદકતા કાફી બઢાને કી સંભાવનાએં હુંદી હૈનું। ભારત મેં લગે લગભગ 2.6 કરોડ એગ્રી પંપ મેં સે લગભગ એક કરોડ પંપ ડીજલ સે ચલતે હું જબકિ સૌર એગ્રી પંપ સંસ્તે ઔર પર્યાવરણ મિત્ર હોતે હું। ભારત કે ગાંવોં મેં સ્વચ્છ પેયજલ કી ઉપલબ્ધતા ભી એક ચુનાતી હૈ। જલ કો ઉપચારિત કરને કે લિએ ભી બિજલી કી જરૂરત હોતી હૈ। સૌર ઊર્જા કા ઉપયોગ ઇસ ક્ષેત્ર મેં ભી મહત્વપૂર્ણ હૈ। જૈસેકિ કોહિમા કે નિકટ એક-એક ગાંવ મેં સૌર ઊર્જાચાલિત જલ ઉપચાર સંયોગ લગાયા ગયા હૈ જો ઉન્નત મેમ્બ્રેન ફિલ્ટરેશન પદ્ધતિ પર કામ કરતા હૈ ઔર પીને કે લિએ શુદ્ધ પાની ઉપલબ્ધ કરાતા હૈ।

સૌર ઊર્જા કે ઉપયોગ સે ન કેવલ ગ્રામીણ રોજગાર કે અવસર બઢાએ જા સકતે હું બલ્કિ ઇંટરનેટ ઔર ટેલીવિઝન કે જરિએ સૌર-ઊર્જા આધારિત સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા કેંદ્રોં, સૌરચાલિત ટેબલેટ; જૈસેકિ એડજિલા દ્વારા વિકસિત ટેબલેટ જિસને કર્નાટક મેં શિક્ષા કે પરિદૃશ્ય કો હી બદલ દિયા; ઔર સૌર ટેલીકોમ ટોવર્સ તક પહુંચ બનાઈ જા સકતી હૈ ઔર ઊર્જા કી આપૂર્તિ કી કમી કે કારણ બંદ પડે 150,000 ટેલીકામ ટાવર્સ કો ચાલુ કરના ભી સંભવ હોગા। દૂસરી ઓર, સૌર સંયંત્રોં કો લગાને ઔર ઉસકે બાદ ઉનકી દેખરેખ કે લિએ બડી સંખ્યા મેં યુવાઓં કી આવશ્યકતા હોગી। ઇસ પ્રકાર યહ કહના અતિશયોક્તિ નહીં હોગા કિ ઊર્જા કા યહ વૈકલ્પિક સ્નોત, સામાજિક ઔર આર્થિક રૂપ સે ગાંવોં કે નક્શો કો હી બદલ દેગા। કેંદ્ર કે દિશા-નિર્દેશોં પર રાજ્યોં દ્વારા કી ગર્ઝ ઇસ પહલ મેં નિજી ક્ષેત્રોં કો ભી ભાગીદારી નિભાની હોગી। જૈન ઇરીગેશન, ટાટા સોલર, ગ્રીનલાઇટ પ્લેનેટ જૈસી કંપનીઓં ગાંવોં મેં સૌર ઊર્જા કે વિકાસ કે લિએ આગે આઈ હુંદી હૈનું।

શુભારંભ સે લેકર માર્ચ 2018 તક લગભગ 9.10 પ્રતિશત કા સીએજીઆર સૃજિત કિયા હૈ।

### પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના

ગાંવોં મેં સમસ્યા સિર્ફ ખેતી કી હી નહીં હૈ બલ્કિ આવાસ કી ભી હૈ જહાં લોગોં કે પાસ આજ ભી રહને કો પક્કે ઘર નહીં હુંદી હૈનું। ઇસી બાત કો ધ્યાન મેં રહ્યે હું ભારત સરકાર ને 1985 મેં ગાંવોં મેં ગરીબોં કો આવાસ પ્રદાન કરને કે ઉદ્દેશ્ય સે ઇંદ્રિયા આવાસ યોજના કા આરંભ કિયા થા। ઇસ આવાસ યોજના કે અંતર્ગત શૌચાલય, એલપીજી કનેક્શન, બિજલી કે કનેક્શન ઔર પીને કે પાની કી સુવિધાઓં સે યુક્ત ઘરોં કે સાથ-સાથ મૈદાની ભાગોં મેં રહને વાલોં કો 70,000 રૂપયે ઔર પહાડી ક્ષેત્રોં મેં રહને વાલોં કો 75,000 રૂપયે કી વિત્તીય સહાયતા દેને કા ભી પ્રાવધાન થા। એનડીએ સરકાર ને 1 જૂન, 2015 મેં ઇસ યોજના કો વિસ્તાર પ્રધાનમંત્રી આવાસ



યોજના કે રૂપ મેં કિયા। ઇસ આવાસ યોજના કે અંતર્ગત ગ્રામીણ એવં શહરી સભી બેઘર ગરીબોં કો 2022 તક ઘર પ્રદાન કરને કી યોજના હૈ। ઇસકે અંતર્ગત તીન પ્રકાર કે આવાસોં કી વ્યવસ્થા હૈ: આર્થિક રૂપ સે પિછડા અર્થાત ઈડલ્યુએસ વર્ગ, નિમ્ન આય વર્ગ અર્થાત એલઆઈજી ઔર મધ્ય આય વર્ગ યાની એમઆઈજી કે લિએ આવાસ। ઇસ યોજના કા મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્લ્યુમ મેં રહને વાલે ગરીબ લોગોં કે લિએ પર્યાવરણ-સહ્ય તકનીકોં કો પ્રયોગ કર સસ્તે ઘર બનાના હૈ। ઘરોં કે આવંટન કે સમય વરિષ્ઠ નાગરિકોં ઔર દિવ્યાંગોં કો વિશેષ ધ્યાન રહ્યા જાએગા। ઇસ યોજના કો તીન પ્રાવસ્થાઓં મેં પૂરા કિયા જાએगા।

આવાસ યોજના કો દો સંઘટકોં- શહરી ઔર ગ્રામીણ – મેં બાંટા ગયા હૈ। ગ્રામીણ આવાસ યોજના મેં માર્ચ 2019 કે અંત તક એક કરોડ ના ઘર બનાએ જાને હું જિનમાં સે 51 લાખ ઘર માર્ચ

## प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक घर के निर्माण की भू-टैगिंग तथा संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। पीएमएवाई—जी के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति आदि सुविधाओं से ग्रामीण भारत की तरस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर, 2016 को आगरा में प्रधानमंत्री आवास योजना—(ग्रामीण) का शुभारंभ किया था। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की पुनर्संरचना करके पीएमएवाई—जी तैयार किया गया है। 2022 तक 'सबसे लिए आवास' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई—जी के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ तथा 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 51 लाख घरों का निर्माण 31 मार्च, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आईएवाई के तहत बनने वाले 2 लाख निर्माणाधीन आवास भी शामिल हैं।



ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन में पिछले 4 वर्षों के दौरान 4 गुना वृद्धि हुई है। यह वृद्धि तब है जब 20 नवंबर, 2016 को योजना के लांच होने के बाद से लाभार्थी का निबंधन, भूटैगिंग, खाते की जांच आदि प्रक्रियाओं के पूरा होने में कई महीने लग जाते हैं।

पीएमएवाई—जी के तहत निर्मित होने वाले एक करोड़ आवासों में से 76 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं तथा लगभग 63 लाख लाभार्थियों ने धनराशि की पहली किस्त प्राप्त कर ली है। वर्ष 2017–18 के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का तेजी से निर्माण संभव हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से कार्यक्रम का पारदर्शितापूर्ण और निर्बाध तथा बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए राज्य-स्तर पर एक ही नोडल खाते का संचालन किया जाता है। पीएमएवाई—जी के तहत लाभार्थियों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से निम्न लाभ हुए हैं:

- आवास निर्माण में समय और लागत में कमी
- पारदर्शिता के कारण धनराशि के दुरुपयोग में कमी
- लाभार्थियों को धन आवंटन प्रक्रिया की निगरानी में आसानी
- आवास निर्माण की बेहतर गुणवत्ता

ग्रामीण आवास योजना के तहत 2013–14 से 2017–18 तक निर्मित होने वाले आवासों की संख्या (लाख में)

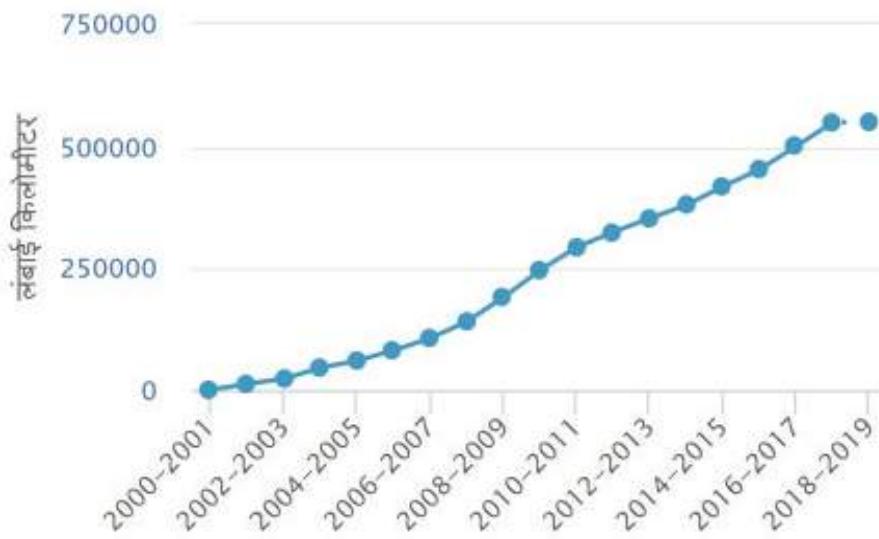
	2013–14 (आईएवाई)	2014–15 (आईएवाई)	2015–16 (आईएवाई)	2016–17 (आईएवाई पीएमएवाई—जी)	2017–18 (आईएवाई पीएमएवाई—जी)
निर्मित आवास	10.51	11.91	18.22	32.23	44.54*

\*अनुमानित

आवास के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्ट्री की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण राजमिस्ट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मार्च, 2019 तक एक लाख ग्रामीण राजमिस्ट्रियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का निर्माण संभव होगा; देश में कुशलता प्राप्त कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रशिक्षित राजमिस्ट्रियों को आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे।

साथ ही, प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीबों को सक्षम तथा सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। यूएनडीपी—आईआईटी दिल्ली ने आवासों के विभिन्न डिजाइन तैयार किए हैं। 15 राज्यों के लिए रथानीय जलवायु तथा स्थानीय निर्माण सामग्री को ध्यान में रखते हुए आवासों के 168 डिजाइन तैयार किए गए हैं। लाभार्थी इनमें से किसी भी डिजाइन का चयन कर सकता है। इन आवास डिजाइनों को केंद्रीय आवास शोध संस्थान, रुडकी ने भी मंजूरी दी है। इन आवास डिजाइनों में लागत कम आती है तथा ये आपदा प्रतिरोधी भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न डिजाइन वाले आवासों का निर्माण हो रहा है। इससे ग्रामीण परिदृश्य से सुखद बदलाव हो रहा है। गरीब लोगों को रहने के लिए सुरक्षित आवास प्राप्त हो रहे हैं जहां वे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकते हैं।

## પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ સર્વેક યોજના કી પ્રગતિ



2018 તક બનાએ જાને થે। સરકાર ને એસા હી કુછ લક્ષ્ય શહરી આવાસોંની કે લિએ ભી રખા હૈ। ઇસ લક્ષ્ય કો પૂર્ણ કરને કે લિએ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, રાજ્ય સરકારોંની સાથ મિલકર કામ કર રહા હૈ।

### પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ સર્વેક યોજના

અમ્ભી ભી બહુત સે ગાંંવ સર્વેકોની સે અચ્છી તરહ સે જુદે નહીં હું ઔર વહાં બિજલી કી ઉચિત આપૂર્તિ ભી નહીં હું હૈ। ગાંંવોની મેં રહને વાળોની કો શહરોની યા અપને ગંતવ્ય સે જોડને કે લિએ ઔર ગરીબી હટાને કી રણનીતિ કે અંતર્ગત ભારત સરકાર ને પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સર્વેક યોજના આરંભ કી હૈ। ઇસસે ન કેવેલ યાતાયાત કી સુવિધા બઢેગી બલ્ક આને-જાને મેં લગને વાલે સમય ઔર પૈસે

કી ભી બચત હોગી। રાજ્ય સરકારોં દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાએ ગએ આંકડોની કે અનુસાર લગભગ 1.67 લાખ બસાવટોની કો બારહમાસી સર્વેકોની જોડના ઇસ યોજના કા લક્ષ્ય હૈ। ઇસકે લિએ લગભગ 3.71 લાખ કિલોમીટર લંબી નર્ઝી સર્વેકોની નિર્માણ કિયા જાએગા ઔર 3.68 લાખ કિલોમીટર સર્વેકોની કો અપગ્રેડ કરને કી યોજના હૈ। લગભગ 500 કી જનસંખ્યા વાલે મૈદાની ઇલાકોની ઔર લગભગ 250 કી આબાદી વાલે પહાડી ઇલાકોની 1,78,000 બસાવટોની બારહમાસી સર્વેકોની જોડા જાના હૈ જિસમે સે લગભગ 82 પ્રતિશત કો અબ તક જોડા જા ચુકા હૈ ઔર શેષ 47,000 નિવાસોની કો જોડને કા કામ ભી પ્રગતિ પર હૈ। ઇસ યોજના કે અંતર્ગત 2004 સે 2014 તક સર્વેક નિર્માણ કી ઔસત ગતિ 98.5 કિલોમીટર પ્રતિદિન થી જિસે

2016-17 મેં બઢાકર 130 કિલોમીટર પ્રતિદિન કિયા ગયા।

### મનરેગા – પૂર્ણ પારદર્શિતા કે સાથ આજીવિકા સુરક્ષા

મનરેગા ને પૂર્ણ પારદર્શિતા કે સાથ દીર્ଘાવધિ સંપદા નિર્માણ કરતે હુએ આજીવિકા પ્રદાન કરને મેં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન દિયા હૈ। કાર્યક્રમ કે અંતર્ગત નિર્મિત પ્રત્યેક સંપદા કી ભૌગોલિક ટૈગિંગ કી ગઈ। ઇસકે લિએ આઇટી/ડીબીટી કા ઉપયોગ કિયા ગયા। મનરેગા કે તહેત 15 દિનોની અંદર હોને વાલે ભુગતાન મેં મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ હુઈ હૈ। 2014-15 મેં યાં 26.85 પ્રતિશત થા, જો 2017-18 મેં બઢાકર 85.75 પ્રતિશત હો ગયા। 2017-18 કા કુલ પરિવ્યુય 63,887 કરોડ રૂપયે હૈ, જો 2013-14 મેં વ્યય કી ગઈ કુલ ધનરાશિ સે લગભગ 25,000 કરોડ રૂપયે અધિક હૈ। ઇસી તરહ



### मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट

प्रगति	वित्तवर्ष 2017–18*	वित्तवर्ष 2016–17	वित्तवर्ष 2015–16	वित्तवर्ष 2014–15	वित्तवर्ष 2013–14
अब तक सर्जित कुल कार्य दिवस (करोड़ में)	231.60 (श्रम बजट का 100 प्रतिशत)	235.6458	235.1465	166.21	220.37
रोजगार के औसत दिन प्रति परिवार	45.44	46	48.85	40.17	45.97
परिवारों द्वारा किया गया कुल कार्य (करोड़ में)	5.10	5.1224	4.8134	4.14	4.79
दिव्यांगजनों के द्वारा किया गया कार्य	4,69,393	4,71,819	4,59,597	4,13,316	4,86,495
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (करोड़ में)	54.22	65.46	36.18	29.44	27.42
कृषि तथा कृषि संबंधित अन्य कार्यों पर परिव्यय का प्रतिशत	68.46	66	62.85	52.81	48.7
कुल परिव्यय (करोड़ में)	63,887.35	58,062.92	44,002.59	36,025.04	38,552.62
ईएफएमएस के जरिए कुल परिव्यय प्रतिशत में	96.31	92.33	91.19	77.35	37.17
15 दिनों में दिए गए भुगतान का प्रतिशत	85.75	43.43	36.92	26.85	50.09

\*वित्त वर्ष 2017–18 के आंकड़े अस्थायी हैं।

आजीविका सुरक्षा और दीर्घावधि संपदा निर्माण के लिए कृषि तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। यह परिव्यय 2013–14 के 48.7 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 68.46 प्रतिशत हो गया।

#### दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

किसी गांव को तब ही बिजलीयुक्त कहा जा सकता है जब उस गांव के स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्रों के साथ—साथ कम से कम 10 प्रतिशत घरों में भी बिजली की सुविधा हो। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2015 में विद्युतीकरण के लिए चुने गए 18,452 गांवों में से 73 प्रतिशत में अब विद्युत आपूर्ति की जा चुकी है, लेकिन इन गांवों में से अभी केवल 8 प्रतिशत गांवों में हर घर में बिजली पहुंचाई गई है। देश के 25 प्रतिशत ग्रामीण घरों में आज भी बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश, नगालैंड, झारखंड और बिहार के 50 प्रतिशत से भी कम घरों में बिजली है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने के लिए गरीबी—रेखा के नीचे रहने वाले 435 लाख घरों की पहचान की गई है। इनमें से लगभग 235 करोड़ (59 प्रतिशत) को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की घोषणा भी की है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। दूरदराज के भौगोलिक रूप से दुर्गम अनेक क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली के ऑफ—ग्रिड संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। गांवों में रोशनी लाने के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे गैर—पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बड़े

पैमाने पर उपयोग हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब गांव—गांव में उजाला फैलेगा।

**दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वासी, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक—आर्थिक परिवर्तन ला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब विशेषकर स्वयंसहायता समूह की महिला सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक दर्जा सुधारने के लिए उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हाटों को प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय की योजना वित्तवर्ष 2018–19 में पूरे देश में 22,000 ग्रामीण हाट स्थापित करने की है। मिशन 2011 में लांच किया गया था और अब इसका विस्तार 29 राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों के 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों तक हो गया है। मिशन ने 39.9 लाख स्वयंसहायता समूह को सक्रिय किया है, जो आगे 2.20 लाख ग्राम संगठनों और 19,000 कलस्टर स्तर के फेडरेशन हो गए हैं।

आज भी औरतें खेतों में काम करती हैं लेकिन अब महिलाओं को जागरूक करने का समय आ गया है। इसीलिए उन्हें भी समय—समय पर उनकी पसंद के हिसाब से काम सिखाए जाएंगे जैसे जैविक खेती करना, डेरी उद्योग और केंचुआ पालन वगैरह। जब वो कुछ अपना रोजगार करेंगी तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी। तब भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थों में करना है और लगातार लंबे समय तक करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा तब जाकर विकास की इमारत मजबूत होगी।

(लेखिका सीएसआईआर में साईंस रिपोर्टर में संपादक रह चुकी हैं।)

ई—मेल : vineeta\_niscom@yahoo.com

# नए उभरते भारत की परिकल्पना

—प्रो. सुमन पामेचा, मीनाक्षी अहीर

अगर यह कहा जाए कि गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उज्ज्वला योजना ने जहाँ करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है वहीं स्वच्छ भारत अभियान से देशभर में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और खुले में शौच जाने के मामलों में काफी कमी आई है। यही नहीं जन-धन योजना ने करोड़ों ग्रामीण के बैंक खाते खोल सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाने की सुविधा प्रदान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। ऐसी ही कई योजनाओं से आज देश उन्नति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है और नए भारत की परिकल्पना मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। इस मार्ग में कई चुनौतियां और बाधाएं भी हैं। सही रणनीति से इन बाधाओं को पार करने की जरूरत है।

**स्व** तंत्रता के बाद से भारत ने अपनी प्रगति तथा आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के लिए काफी प्रयास किए। तथा उसके लिए समय—समय पर कई नई योजनाएं तथा नीतियों का निर्माण किया गया जिनके माध्यम से आज देश सभी क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है जैसे विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार एवं स्वास्थ्य आदि।

इसके बावजूद आजादी के 70 वर्षों के बाद भी काफी सारी असंतोषजनक स्थितियां अभी तक भी हमारे बीच बनी हुई हैं जिसके कारण देश को प्रगति पथ पर चलने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय समावेशन के जरिए सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यापार रोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी को शिक्षा, महिला सुरक्षा, पोषण आदि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनडीए सरकार कई नई योजनाएं लाई। या फिर पहले से चल रही योजनाओं की कमियों को दूर कर उन्हें नया रूप—रंग दिया गया। इस लेख में ऐसी ही कुछ नवीन एवं लोकप्रिय योजनाओं का वर्णन किया गया है।

## प्रधानमंत्री जन-धन योजना

वित्तीय समावेशन के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग 60

प्रतिशत बैंक खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए (अप्रैल 17 तक)। इसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना एक बैंक अकाउंट बनाना होगा जिसमें उन्हें एक लाख रुपये की बीमा राशि एवं डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। यह योजना गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिससे व्यक्तियों में बचत की भावना का विकास हो; साथ ही अपने भविष्य की सुरक्षा का अहम भाव जागे। इसके अलावा, इस कदम से देश का पैसा भी सुरक्षित होगा और जनहित के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत गरीबों को बैंकों में मुफ्त में खाता खोलने का मौका दिया गया। इस योजना के जरिए करीब 29 करोड़ नए खाताधारक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। यह योजना जहाँ गरीबों को सशक्त करने का काम कर रही है वहीं इसके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के चलते भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े रास्ते को सरकार ने हमेशा—हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इन खातों में अप्रैल 2017 तक लगभग 65 हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके थे।

## मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2014 को की गई। यह योजना भारत में निवेश के लिए



### जनधन खाते 2017 (करोड़ में)

वर्ष	जन-धन खाते	जीरो बैलेंस खाते
2014	10	18
2015	20	25
2016	25	30
2017	30	70

**स्रोत— वित्तीय सेवा विभाग, सर्वेक्षण परिकलन**

सारणी में स्पष्ट है कि 2014 में जनधन खाते 10 करोड़ तथा जीरो बैलेंस खाते 18 करोड़ थे; 2017 तक बढ़कर जनधन खाते 30 करोड़ व जीरो बैलेंस खाते 70 करोड़ तक हो गए हैं।

(राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय) पूरे विश्व में से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को बुलाने के लिए किया गया एक प्रयास है जो देश के सभी क्षेत्रों में (उत्पादन, टेक्सटाइल्स, आटोमोबाइल्स, रसायन, आईटी, बंदरगाह, औषधि तथा रेलवे, चमड़ा आदि) अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए दिया गया अवसर था। यह योजना व्यापार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने, डिजिटल नेटवर्क के बाजार में सुधार के साथ ही असरदार भौतिक संरचना के निर्माण पर केंद्रित है।

इसका प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया हुआ एक विशाल शेर है जिसके पास ढेर सारे पहिए हैं जो शांतिपूर्ण प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के रास्ते को इंगित करता है। कई पहियों के साथ चलता हुआ शेर हिम्मत, मजबूती, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रों में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का ध्यान बड़ी संख्या में मूल्यवान और समानित नौकरी के अवसर पैदा करना है।

इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट और रहने योग्य घर बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख निवेशकों की मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के 25 क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष 74 प्रतिशत, रक्षा 49 प्रतिशत, समाचार मीडिया 26 प्रतिशत को छोड़कर 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति हुई है। जापान व भारत ने 12 बिलियन डॉलर जापान-भारत में इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस सुविधा निधि की घोषणा की।

भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए 2015 में विश्व-स्तर पर उभरा है तथा वर्ष 2016-17 में भारत को 60 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ है।

### स्वच्छ भारत अभियान

यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय-स्तर के इस अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों, शहरों, नगरों, गांवों, कस्बों आदि को साफ-सुथरा करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका

सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना उन्हें समर्पित की गई।

### पिछले कुछ वर्षों में भारत में ग्रामीण स्वच्छता दायरा

वर्ष	स्वच्छता दायरा (प्रतिशत में)
1981	9
1991	22
2001	32
2011	39
2018	76

**स्रोत— स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय (10.01.2018 के अनुसार)**

स्वच्छ भारत योजना में कलस्टर एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को धीरे-धीरे समाप्त करना है। यह मिशन शौचालयों के उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की एक पहल करेगा।

सरकार ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

मई 2018 तक 296 जिलों व 307349 गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से देश के अंतर्गत स्वच्छता का दायरा बढ़ता जा रहा है। 1981 में 9 प्रतिशत था जो इस अभियान के चलते 2018 तक 76 प्रतिशत हो गया है।

### प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ मुद्रा योजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस भारी-भरकम कोष के साथ 3,000 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी जोड़ा गया है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया योजना लागू करने के बाद सरकार ने उसमें कारोबार और रोजगार की भावना को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहयोग हेतु इस योजना को शुरू किया।

इस योजना के माध्यम से सरकार ने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों और लघु व्यवसायों को सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही कोई नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।

मुद्रा बैंक ने ऋण को तीन वर्गों में बांटा है—

1. शिशु ऋण— 50,000 रुपये तक का ऋण
2. किशोर ऋण — 50,000 से 5 लाख तक
3. तरुण ऋण — 5 लाख से 10 लाख तक

इस योजना के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राशि लोगों को जारी भी हो चुकी है। वैसे मुद्रा योजना से 7.45 करोड़ उद्यमी लाभ उठा चुके हैं। 3.17 लाख करोड़ रुपये ऋण के तौर पर दिए जा चुके हैं।

## प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की इकाइयों को वितरित ऋण (करोड़ में)

इकाइयों का वर्ग	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	खातों की संख्या	वितरित ऋण	खातों की संख्या	वितरित ऋण
शिशु ऋण	324.1	62027.69	364.98	83891.88
किशोर ऋण	20.60	41073.28	26.64	51063.12
तरुण ऋण	4.10	20853.73	5.40	40357013
योग	<b>34.88</b>	<b>132954.73</b>	<b>397.02</b>	<b>175312.13</b>

**चोत— बैंकिंग सेक्टर एवं विभाग**

### अटल पेंशन योजना

यह योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा कौलकाता में शुरू की गई थी। पहले की 'स्वावलंबन' योजना में मौजूद त्रुटियों को खत्म कर उसको नवीनीकृत कर अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। जो ग्राहक 'स्वावलंबन' से जुड़े थे, उन सभी को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा "दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तब उसके पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। इसलिए जन-धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है।"

इस योजना के शुरू होने से किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना को प्रभावी बनाया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। अटल पेंशन योजना के द्वारा 2017 तक 84 लाख से अधिक ग्राहक 3194 करोड़ रुपये से अधिक परिसंपत्ति के साथ पंजीकृत हैं।

### डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 से शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल क्षेत्र में सशक्त समाज और ज्ञान को बढ़ाना है। इस योजना के द्वारा भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सहयोग से भविष्य के भारत को सशक्त और ज्ञान—संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल इंडिया का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है—

1. हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा;
2. मांग पर संचालन एवं सेवाएं;
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

### लक्ष्य

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे

की उपलब्धि

- नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक हाईस्पीड इंटरनेट
- डिजिटल पहचान अंकित करने का अनोखा स्थान
- मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो
- पब्लिक स्थान पर सुरक्षित साइबर कैफे

### डिजिटल इंडिया के कार्यक्षेत्र

1. ब्रॉडबैंड हाइवेज, 2. मोबाइल कनेक्टिविटी
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
4. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
5. रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी

### राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

देश के प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित ब्लॉकों के प्रत्येक पात्रधारी परिवार के एक सदस्य का चुनाव करते हुए 10 लाख लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है।

### बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से शुरू किया गया। इस योजना की रूपरेखा गिरते शिशु लिंगानुपात के समाधान के लिए बनाई गई है। यह योजना शुरुआत में 100 जिलों में लागू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव विकास मंत्रालय की एक त्रि—स्तरीय पहल है।

19 अप्रैल, 2016 को यह योजना 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 61 अतिरिक्त जिलों में चलाई गई। इस योजना की उपलब्धि के तौर पर पहले साल में जन्म के समय लिंगानुपात में 49 प्रतिशत की बढ़ोतारी देखी गई। अभी के वर्षों में लिंगानुपात में न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य है तथा आगामी पांच सालों में धीरे—धीरे इसे और अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में अन्य कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं—

- बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी
- 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव
- हर गांव में गुड़डा—गुड़िया बोर्ड का गठन
- लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा
- लड़कियों के लिए स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था भी शामिल है।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला—स्तरों के सम्मिलित प्रयास से 100 जिलों से प्राप्त आंकड़ों की प्राथमिक रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2014—15 और 2015—16 के दौरान अप्रैल—मार्च के मध्य बीबीबीपी स्कॉम वाले 58 प्रतिशत जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात दर में वृद्धि दिखाई गई हैं। 69 जिलों में प्रसवपूर्ण देखभाल वाले मामलों में प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण में वृद्धि देखी गई हैं।

મંત્રાલય દ્વારા 2017 મેં રાજસ્થાન કો નારી શવિત પુરસ્કાર સે ભી સમ્માનિત કિયા ગયા।

### સ્ટાર્ટઅપ ઇંડિયા

16 જનવરી 2016 સે લાગુ હુઈ સ્ટાર્ટઅપ ઇંડિયા યોજના કા મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય યહ હૈ કિ નારી/બાળ ઉદ્યોગોं કો શુરુ કરને કે લિએ સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહન દિયા જાએગા જિસમેં ઋણ સુવિધા, ઉચિત માર્ગદર્શન એવં અનુકૂલ વાતાવરણ આદિ શામિલ કિયા ગયા હૈ। ઇસકે તહત જરૂરી સ્ટિકલ ડેવલેપમેન્ટ ટ્રેનિંગ ભી દી જાએગી।

સ્ટાર્ટઅપ યોજના પર નર્ઝ નીતિ લાગુ હોને કે બાદ હજારોં કરોડ રૂપયે કા નિવેશ હુआ હૈ। મુખ્ય બાત યહ હૈ કિ ઇસમેં મહિલાઓં કી ભી જરૂરત ભાગીદારી હૈ। ઇસસે 2020 તક કરીબ ઢાઈ લાખ લોગોં કો રોજગાર મિલને કા અનુમાન હૈ। 10 હજાર કરોડ રૂપયે કે કોષ સે શુરુ હુઆ સ્ટાર્ટઅપ અબ લોગોં કો આત્મનિર્ભર બના રહા હૈ। અબ તક 800 સ્ટાર્ટઅપ કા પંજીકરણ હુઆ હૈ।

ઇસ યોજના કે બનને સે ભારત કે અનેક રાજ્યોં ને અપને—અપને રાજ્ય મેં કર્ઝ નારી કાર્ય કિએ હૈનું। કેરલ મેં કેરલ આઇટી મિશન નામક એક સરકારી સ્ટાર્ટઅપ પૉલિસી કી શુરુઆત કી ગર્ઝ જો રાજ્ય કો સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ મેં નિવેશ કે લિએ 50 અરબ ડૉલર લાને પર કંદ્રિત હૈ। તેલંગાના ને ભારત મેં સબસે બડા ઉભાયત કેંદ્ર “ટી હબ” કે રૂપ મેં શુરુ કિયા હૈ। મધ્ય પ્રદેશ ને 200 કરોડ રૂપયે કે ફંડ બનાને કે લિએ લઘુ ઉદ્યોગ વિકાસ બેંક ઑફ ઇંડિયા કે સાથ સહયોગ કિયા હૈ। રાજસ્થાન મેં સ્ટાર્ટઅપ ઓએસીસ યોજના શુરુ કી ગર્ઝ હૈ।

### પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલા યોજના

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલા યોજના કી શુરુઆત 1 મર્ઝ, 2016 કો ઉત્તર પ્રદેશ કે બલિયા સે હુઈ। યહ યોજના મહિલા સશવિત્કરણ કી દિશા મેં બહુત હી સફળ ઔર લોકપ્રિય સાબિત હો રહી હૈ। ઇસકે તહત ગરીબ પરિવાર કો મહિલાઓં કો કેંદ્ર સરકાર કી ઔર સે નિઃશુલ્ક એલપીજી કનેક્શન દિએ જાને કી વ્યવસ્થા હૈ।

ઇસ યોજના કે તહત 2016 સે 2019 તક કુલ 5 કરોડ ગરીબ પરિવારોં કો એલપીજી કનેક્શન દિએ જાને હૈનું તાકિ માતાઓં ઔર બહનોં કે સેહત કી સુરક્ષા કી જા સકે। અબ તક ઇસ યોજના કે તહત 2.20 કરોડ સે અધિક એલપીજી કનેક્શન દિએ જા ચુકે હૈનું।

સરકાર કી અકેલી ઉજ્જ્વલા યોજના ને ગરીબી રેખા કે નીચે

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય દેશ મેં રાજ્ય સરકારોં કે સાથ મિલકર 40 લાખ સે અધિક સ્વયંસહાયતા સમૂહોં પર કામ કર રહા હૈ ઔર ઇસમે 4 કરોડ સે જ્યાદા મહિલાએ લગી હુઈ હૈનું। આને વાલે કલ મેં 8 સે10 કરોડ મહિલાઓં કો આજીવિકા કે ઇસ કામ સે જોડા જાએગા। 2014 સે અબ તક 5 લાખ 70 હજાર યુવાઓં કો પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ વિકાસ યોજના કે અંતર્ગત પ્રશિક્ષણ દિયા જા ચુકા હૈ। ઇનમેં સે તીન લાખ અડ્ઝતાલીસ હજાર યુવાઓં કો રોજગાર ઉપલબ્ધ કરાયા ગયા। ઇસી પ્રકાર ગ્રામીણ સ્વરોજગાર પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન કે માધ્યમ સે 10 લાખ 15 હજાર યુવાઓં કો પ્રશિક્ષિત કિયા ગયા ઔર ઇનમેં સે 5 લાખ 92 હજાર કો નૌકરી ઉપલબ્ધ કરાઈ ગર્ઝ।

જીવન જીને વાલી મહિલાઓં કો અબ જીવન કે પ્રતિ નજરિયા હી બદલ કર રખ દિયા હૈ। ઇસ યોજના ને કરોડોં મહિલાઓં કે ચેહરે પર મુસ્કરાહટ લાને કો કામ કિયા હૈ। ઇસ યોજના કે દ્વારા સરકાર ઇસ બાત પર દૂરદૃષ્ટિ કાયમ કર રહી હૈ કિ અગર દેશ કી મહિલાએં વ બચ્ચે સ્વસ્થ હોંગે તો ભારત ભી સેહતમંદ હોગા।

### નિષ્કર્ષ

ઇસમેં કોઈ સંદેહ નર્હી હૈ કિ વર્તમાન સરકાર કે દ્વારા ચલાઈ ગર્ઝ ઇન યોજનાઓં સે દેશ કે સભી ક્ષેત્રોં મેં કાફી પ્રગતિ હુઈ હૈ। દેખા જાએ તો ભારત તકનીકી શિક્ષા, સુરક્ષા, ચિકિત્સા તથા મહિલાઓં કે ક્ષેત્ર મેં કાફી પિછડા હુએ માના જાતા રહા હૈ પર ઇન વિભિન્ન ક્ષેત્રોં કે અંતર્ગત ચલાઈ ગર્ઝ યોજનાઓં કે પરિણામસ્વરૂપ દેશ પ્રગતિ પથ પર તેજી સે અગ્રસર હો રહા હૈ।

ઉજ્જવલા યોજના કે દ્વારા હર ઘર કે અંદર ગૈસ કનેક્શન, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન સે દેશ ભર મેં સ્વચ્છતા કે પ્રતિ જાગરૂકતા તથા ખુલે મેં શૌચ જાને આદિ મેં કમી આના; બેંકોં કે માધ્યમ સે ઋણ સુવિધા દેના તાકિ વ્યાપાર વ રોજગાર મેં બઢોતારી હો સકે; પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કે દ્વારા વ્યક્તિ કી મૂલભૂત ઘર કી જરૂરત કી પૂર્તિ કરના તથા અટલ પેંશન યોજના કે જરિએ બુજુર્ગોં કે લિએ પેંશન કી સુવિધા દેના તાકિ વહ અપને જીવન કે અંતિમ દિનોં મેં કિસી પર નિર્ભર ના રહે તથા વહ ઇસ પેંશન કી રાશિ કો અપને કમજોર સ્વાસ્થ્ય વ બોજન પર વ્યય કર સકે।

તકનીકી ક્ષેત્ર મેં જેસે ડિજિટલ ઇંડિયા, સ્ટાર્ટઅપ યોજના વ મેક ઇન ઇંડિયા જૈસી યોજનાઓં કે દ્વારા યુવા પીઢી કો સ્વાવલંબી વ આત્મનિર્ભર બનાને કો પ્રયાસ કિયા જા રહા હૈ જિસસે વહ વિદેશ જાકર નૌકરી ના કર અપની ખુદ કી પહ્યાન કે સાથ દેશ કો આગે બઢાએં।

યહ સભી યોજનાએં કાફી હદ તક સફળ હો રહી હૈનું તથા ઇન સભી યોજનાઓં કો ફાયદા જનતા કો મિલ રહા હૈ। પર કભી—કભી ઐસા હોતા હૈ કિ જબ ભી કોઈ નર્ઝ યોજના યા કાર્યક્રમ બનતા હૈ તો વહ પૂરી તરહ સે આમ જનતા તક પહુંચ હી નહીં પાતા હૈ યા ઐસા કહે કિ જિન વ્યક્તિ કો જ્યાદા જરૂરત હો વહાં તક પહુંચને મેં કાફી સમય લગતા હૈ। ઐસા ઇસલિએ હોતા હૈ ક્યોંકિ યોજના કે વિસ્તાર કાર્યક્રમ મેં દૂરદરાજ કે ક્ષેત્રોં પર જ્યાદા ધ્યાન નહીં દિયા જાતા।

ઇન યોજનાઓં કે બારે મેં ગાંગ યા પંચાયત—સ્તર પર જનતા કે અંદર જાગરૂકતા લાને કો પ્રયાસ કિયા જાના ચાહિએ। આજ કી યુવા પીઢી કો જાગરૂક હોને કી જરૂરત હૈ તાકિ વહ ઇન સભી યોજનાઓં કો લાભ ઉઠા સકે। ઇલેક્ટ્રોનિક એવં પ્રિંટ માધ્યમોં સે યોજનાઓં કો જ્યાદા સે જ્યાદા પ્રચાર કિયા જાના ચાહિએ તાકિ લોગોં તક યોજનાઓં કી જાનકારી પહુંચ સકે।

(ડૉ. સુમન પામેચા જનાર્દન રાય નાગર રાજસ્થાન વિદ્યાપીઠ વિશ્વવિદ્યાલય, ઉદયપુર કે અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ મેં પ્રોફેસર એવં મીનાક્ષી અણીર શોધાર્થી હૈનું)

ઈ—મેલ : sahir8086@gmail.com

# कृषि विकास पर टिका ग्रामीण विकास

—डॉ. के.एन. तिवारी

तमाम संदर्भों को देखें तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कृषि एवं किसानों के कल्याण से जुड़ी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं आखिर किस तरह की हैं। कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाते हुए जिस तरह युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं से लेकर वृद्धों तक को प्राथमिकता में रखा गया है, सराहनीय है।  
किसान, ग्रामीण आबादी, युवाओं, शिक्षा और छोटे उद्योगों के लिए उठाए गए कदमों का सबको लाभ मिलेगा।

**125** करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले विशाल देश में अधिसंख्य किसान अभी भी परंपरागत खेती कर रहे हैं। खेती ही नहीं, अधिकांश किसान आज के दौर में पशुपालन और कृषि से जुड़े अन्य बहुतायत व्यवसाय भी परंपरागत तरीके से ही कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों और कृषि उपकरणों की मौजूदगी के बावजूद खासतौर पर तंगहाल छोटे किसान उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे घाटे की खेती करते हुए ऐसे दुष्क्र में उलझे हैं कि ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाते हैं। खेती और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों को समेकित रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए कौशल विकास पर सरकार संजीदा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

## कृषि उत्पादकता बढ़ाने संबंधी सरकारी प्रयास

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तम बीज की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरकों से जुड़ी सरकारी नीतियां, सिंचाई जल की उपलब्धता और प्रति बूंद पानी से अधिक उपज का लक्ष्य अर्थात् पानी का किफायती एवं अधिक कारगर उपयोग, विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर फोकस, विभिन्न मदों में किसानों एवं ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी

योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाने की पहल की गई है। किसानों को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम लाभकारी उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। 'मेरा गांव मेरा गौरव' जैसे प्रयास से किसान लाभान्वित होंगे। कृषि सिंचाई योजनाओं को मिशन मोड में ले लिया गया है। बजट 2018–19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से फसल की सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, फार्म लोन टारगेट नौ लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने एवं कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा से किसानों को सस्ता ऋण मिल सकेगा। लांग टर्म इरीगेशन फंड योजना उन राज्यों के लिए अच्छी साबित होगी, जहां पानी की किल्लत है। गरीबी से निजात दिलाने वाले प्रस्ताव से गांव खुशहाल होंगे। फसलों को जोखिम से बचाने के साथ खेती की अन्य इनपुट लागत में कमी लाने के उपाय किए गए हैं। ग्रामीण जीवन–स्तर में सुधार और किसानों को समृद्ध करने वाली तकनीकें एवं उनके क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले साबित होंगे।

कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तत्पर रहें, इसका पहली बार प्रावधान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभावशीलता और प्रदर्शन



में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है। इसके साथ 543 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच राष्ट्रीय—स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। गांव के विकास के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 33097 करोड़ रुपये (2018–2019) का प्रावधान किया गया है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 412 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष भी शामिल है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंडियों या मुनाफाखोरों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया है। निस्संदेह उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से युवाओं में खेती के प्रति पुनः आकर्षण पैदा करना संभव होगा। बिंगड़ी खेती को पटरी पर लाने में सरकार पिछले सालों में काफी हद तक सफल रही है।

पिछले तीन बजटों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के सार्थक उपाय किए गए हैं। इन प्रावधानों से पटरी पर लौटी खेती को और रफ्तार मिलेगी। इसमें कृषि से जुड़े पांच मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है—

- उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी प्रयास
- किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने की नीतियां
- पट्टे पर भूमि देने की नीतियों में सुधार
- प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत के लिए तंत्र का निर्माण
- पूर्वोत्तर राज्यों में हरितक्रांति के प्रसार के लिए पहल

किसानों, गरीबों एवं जरूरतमंदों के लाभार्थ क्षेत्र विशेष की कृषि समस्याओं के समाधान हेतु चलाई गई विशिष्ट परियोजनाओं द्वारा समस्याग्रस्त अम्लीय, लवणीय एवं क्षारीय भूमि का सुधार कर कृषि योग्य बनाने तथा मृदा स्वास्थ्य में आए विकारों को दूर कर फार्मजनित निवेशों (गोबर, कूड़े की खाद, कम्पोस्ट, पशुशाला की खाद, हरी खाद, फास्फो सल्फो नाइट्रो कम्पोस्ट, फसल अवशेषों का संरक्षण एवं सदुपयोग आदि) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन, शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई साधनों का सृजन, चैकडैम, विशाल कुओं

### सारणी 1 क्षेत्रवार 5 वर्ष के बजटीय प्रावधान

प्रक्षेत्र	बजटीय प्रावधान (करोड़ रु. में)		प्रतिशत में वृद्धि
	2009–14	2014–19	
फसल बीमा	6,182	33,162	436
माइक्रो इरिगेशन	3193	12711	298
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट	162	1,573	871
कृषि यांत्रिकरण	254	2408	846
कृषि विस्तार उपमिशन	3163	4046	28
कृषि विष्णन	2666	6150	131
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	189	1322	700
डेयरी विकास	8114	10725	32
नीली क्रांति	1772	2913	64
कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार	12252	13748	12

का निर्माण एवं जल समेट क्षेत्र पर आधारित परियोजनाएं छोटे एवं सीमांत कृषकों में आशा की नई ज्योति जगाने में कारगर साबित हुई हैं।

**कृषि जिंसों का वाजिब दाम :** लंबे समय से अटकी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने रबी 2018–19 से विभिन्न कृषि जिंसों पर किसानों को उनके उत्पाद का कृषि लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का ऐलान किया है। परंतु बजट में इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा इसकी बात नहीं की गई, जिसकी वजह से सरकार के इस लोक—लुभावन कदम पर सवाल उठ रहे हैं।

सरकार द्वारा समय—समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि हम सिर्फ एमएसपी की घोषणा नहीं करना चाहते बल्कि एमएसपी का लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। यद्यपि सरकार के प्रयासों से विगत 4 वर्षों में दाल, तिलहन, धान, गेहूं जैसी फसलों की खरीदारी में वृद्धि हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। परंतु यह वृद्धि आशा के अनुरूप नहीं है। हां, वित्तमंत्री ने समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए यह जरूर कहा कि यदि बाजार में दाम एमएसपी से कम हों तो सरकार या तो एमएसपी पर खरीद करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी एमएसपी दिलाने की व्यवस्था करे। इस दिशा में केंद्र सरकार नीति आयोग एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर पुख्ता व्यवस्था करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, ऐसा कहा गया है।

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि यदि एमएसपी पर खरीदी गई ये जिंसे यदि राज्य सरकारों द्वारा दोबारा व्यापारियों को बेच दी जाएंगी तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार प्याज का हश्श हुआ कि जैसे किसान का माल व्यापारियों के हत्थे लगा, वे स्वयं इनका मूल्य निर्धारित करने लगते हैं और जिंस विशेष के मूल्य आसमान छूने लगते हैं। एफसीआई के गेहूं व चावल का भी यही हश्श होता आया है। इससे तो किसान और उपभोक्ता दोनों ही यथावत ठगे जाते रहेंगे।

सरकार द्वारा लंबी अवधि में आयात—निर्यात नीति के लिए संस्थागत व्यवस्था का सृजन भी प्रस्तावित है। इसके माध्यम से वर्ष 2022–23 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। बजट 2018–19 में मूल्य एवं मांग की पूर्व घोषणा हेतु एक संस्थागत व्यवस्था सृजित करने का भी प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से किसान यह निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कौन—सी फसल की कितने क्षेत्रफल में खेती करना अधिक लाभप्रद होगा।

**कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरुआत :** किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य से कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरुआत की गई है। वर्ष 2018–19 में 2000 करोड़ के 'कृषि बाजार विकास फंड' की घोषणा की गई

है जोकि कृषि विपणन में खुदरा बाजार की अहमियत को दर्शाता है। इन बाजारों को ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार (ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार) का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से 22,000 ग्रामीण हाट एवं 585 कृषि उत्पाद विपणन केंद्रों अर्थात् मंडियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा।

**'आपरेशन ग्रीन'** : पूरे देश में टमाटर, प्याज, आलू का उपभोग साल भर किया जाता है। जैसाकि हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से अब तक बिचौलियों के कारण कृषि जिंसों की खरीद हो जाने के बाद इनके मूल्य आसमान छूने लगते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि हर वर्ष किसी न किसी जिंस के लिए अवश्य ही देखने को मिलती है। परिणामस्वरूप किसान और उपभोक्ता दोनों को ही इसका खामियाजा झेलना पड़ता है। सरकार ने पहली बार वर्ष 2018–19 से 'आपरेशन ग्रीन' के नाम से एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि जरूरत से कम प्रतीत होता है। कुछ भी हो, किसानों एवं उपभोक्ताओं के प्रति ऐसा भाव हर दृष्टि से स्वागत योग्य है।

**किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी (FPC)** : सभी प्रकार के किसान उत्पादक संगठनों जिसमें किसान उत्पादक कंपनियां भी शामिल हैं, उन्हें इनकम टैक्स छूट का लाभ दिया गया है। इसका लाभ लघु एवं सीमांत किसान भी किसान उत्पादक संगठन और किसान उत्पादक कंपनियां बनाकर उठा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर, जमीन के बंटवारे की समस्या से उत्पन्न छोटी जोतों से भी निजात मिल सकेगा।

**फसल अवशेष प्रबंधन** : दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकार को फसल अवशेष के स्थानीय प्रबंधन हेतु भी मदद की जाएगी।

**औषधीय तथा सगंध फसलों की खेती** : हमारे देश में औषधीय तथा सगंध फसलों की खेती के लिए भी अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्र उपलब्ध है। इस प्रकार की खेती को भी बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ किसानों वरन् लघु एवं सीमांत उद्योगों का विकास भी हो सकेगा।

**जैविक कृषि** : इस जैविक कृषि के सफल कार्यान्वयन के लिए कलस्टर-आधारित खेती की जाएगी तथा इसे बाजारों से भी जोड़ा जाएगा। कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कहीं गई है। प्रत्येक समूह या संगठन के 1000 हेक्टेयर के क्लस्टर होंगे। ये अच्छी पहल है, परंतु इस क्षेत्र में निष्कर्षात्मक शोध एवं विकास की गहन आवश्यकता है। इस योजना का विशेष लाभ पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को प्राप्त हो सकेगा। जैविक कृषि के उत्पादों की बिक्री की प्रस्तावित व्यवस्था अभी तो भविष्य के गर्भ में है। इस योजना का सही लाभ किसानों को मिले, इस पर गहन मंथन होना चाहिए। इस मंथन से क्या हल निकलता है,

इसका इंतजार करना पड़ेगा। मूल्य और भुगतान के अंतर जैसी योजनाओं की सफलता इनके त्रुटिरहित संचालन पर निर्भर करेगी अन्यथा किसानों की जेब में रकम नहीं आ पाएगी, और ये सिस्टम व्यापारियों, बिचौलियों की तिजोरियां ही भरेगा।

**कलस्टर-आधारित खेती को बढ़ावा** : कृषि उत्पादों को चिन्हित कर कलस्टर आधारित जिलों का विकास किया जाएगा ताकि उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की संपूर्ण शृंखला का लाभ किसानों को मिले। यही नहीं, जिलेवार बागवानी फसलों के लिए भी कलस्टर-आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए खाद्य-प्रसंस्करण एवं वाणिज्य मंत्रालय के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार की योजना पूर्व से ही अन्य नामों से राज्यों में एग्री-एक्सपोर्ट जोन के रूप में शुरू की गई, परंतु निरंतरता, सही सोच, सही व्यवस्था और सरकार की सक्रियता के अभाव के कारण यह योजना दम तोड़ गई।

### कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा

**मछली पालन** : मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 'नील क्रान्ति: समन्वित विकास और मत्स्य प्रबन्धन' के नाम से मछली पालन के लिए पांच साल की योजना तैयार की है जिसमें 2020 तक मछली का उत्पादन 1–5 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने स्तर पर योजना तैयार करने को कहा गया है। 3000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई इस योजना के तहत मछली पालन से लेकर पकड़ने तक की सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। अंतर्रेशीय मछली पालन और समुद्र में मछली पकड़ने के मामले में एक राष्ट्रीय नीति लाने की भी योजना है।

**मधुमक्खी पालन** : रोजमर्गी की जिंदगी में शहद के बढ़ते प्रचलन के चलते मधुमक्खी पालन भी किसानों की आमदनी में अहम भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, यह भी प्रमाणित हो चुका है कि खेतों में मधुमक्खी पालन से फसल उत्पादन में भी अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी होती है। अभी भारत दुनिया के शहद उत्पादक देशों में 9वें स्थान पर है। देश में मौन पालन की असीम संभाव्य क्षमता को देखते हुए मौजूदा मौन कॉलोनियों की संख्या बढ़ाकर 2 करोड़ तक और मौन का फसली उत्पादन 240 लाख करोड़ रुपये तक किया जा सकता है क्योंकि यह बहुमुखी मांग का व्यवसाय है और इसमें संवर्धन की क्षमता बहुत अधिक है। कृषकों के लिए तो यह एक प्रकार से वरदान है, जो फसल के खेतों में मौनपालन करके इनकी पराग सेवाओं से फसलों की उत्पादकता डेढ़ गुना तक बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण जन प्रशिक्षित होकर अपने उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करके अपनी आय में सार्थक वृद्धि कर सकते हैं।

**मुर्गीपालन** : यह सर्वाधिक सफल पूरक व्यवसाय है जो कृषि, पशुपालन या अन्य पेशेवर कार्यों के साथ समानांतर कमाई के व्यवसाय हैं। इस समय कुक्कुट उत्पादों की घरेलू मांग मौजूदा उत्पादन की तुलना में अंडे की चार गुना और मीट की 6 गुना से

अधिक है। अतः कुकुट पालन की मौजूदा संवृद्धि के हिसाब से इसमें 1000 अरब रुपये के कारोबार और एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है। भारत सरकार ने गरीबों को पूरक आय और पौष्टिक सहायता हेतु ग्रामीण घरेलू कुकुट विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की मदद करना है।

**रेशमकीट पालन :** भारत सरकार रेशम उत्पादन में प्रोत्साहन, विस्तार, उन्नयन, संरक्षण और तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसके लिए किसानों के सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। आवश्यकता—आधारित कार्यक्रमों के अलावा एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत भी रेशमपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

**खुंबी उत्पादन :** सामान्य तौर पर लगभग 9–10 कि.ग्रा. खुम्बी प्रतिवर्ग मीटर में निकलती है। प्रति 10 कि.ग्रा. कम्पोस्ट से 12–15 कि.ग्रा. खुम्बी प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त तापमान और नमी एवं उचित रखरखाव अधिक पैदावार बढ़ाने में सहायता होते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्नत खुंबी उत्पादन की तरकीबों की आवश्यकता है।

**राष्ट्रीय बांस मिशन :** कृषि तथा गैर—कृषि क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को नए अवतार में 1290 करोड़ रुपये की निधि के साथ प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से न सिर्फ छोटे उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी वरन् नए रोजगार भी पैदा हो सकेंगे।

**मॉडल लैंड लाइसेंस कल्टीवेटर एक्ट :** सरकार ने वर्ष 2018–19 के बजट में ‘मॉडल लैंड लाइसेंस कल्टीवेटर एक्ट’ की भी घोषणा की है जिसके माध्यम से बंटाईदार तथा जमीन को किराए पर लेकर खेती करने वाले छोटे किसानों को भी संस्थागत ऋण व्यवस्था का लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक कार्यवाई करेगा।

#### किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय

**आजीविका सुरक्षा के लिए बागवानी को बढ़ावा :** सरकार के अगले पांच वर्षों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प में बागवानी फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बागवानी फसलों की खेती से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। सब्जियां अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र से कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। एक खेत से एक वर्ष में 3 से 5 सब्जियों की फसलें लेकर किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। कुछ सब्जियों से निर्मित कई महंगे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, पेस्ट, पाउडर, मिठाईयां बनाकर आय बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित होकर वे सब्जियों का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, कौशल विकास के तहत बागवानी फसलों की नर्सरी व बीज बनाकर बेचने से भी

किसान अपने परिवार के लिए कमाई का एक अच्छा व्यवसाय विकसित कर सकते हैं।

**विदेशी सब्जियां :** सब्जियों में ब्रोकोली, ब्रुसेल्स, स्प्राउटस, चायनीज कैबेज, लीक पार्सले, सेलरी, लैटूस, चैरी, टमाटर, रैड कैबेज, एसपैरागस आदि प्रमुख हैं। ये सब्जियां विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। इन सब्जियों की मांग बड़े शहरों के पांच सितारा होटलों और पर्यटक स्थलों पर अधिक है। यदि किसानों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे विदेशी सब्जियों की खेती से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं और यह उनकी आजीविका का एक नया साधन बनने में सहायता होगा।

**जैविक खेती :** आजकल सब्जियों की जैविक खेती का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैविक खेती में सब्जियों को जैविक खादों के सहारे व बिना कीटनाशियों के पैदा किया जाता है। इस प्रकार की सब्जियों के दाम निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके उगाई गई सब्जियों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। आज उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अच्छे गुणों वाली सुरक्षित सब्जियों को ऊंचे दाम पर खरीदना पसंद करता है। जैविक सब्जी उत्पादन का क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सब्जियों, फलों और फूलों से आर्गेनिक रंग भी बनाए जाते हैं जो न केवल शुद्ध सस्ते व खुशबूदार होते हैं बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी सुरक्षित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबाड़ सहित कई सरकारी व गैर—सरकारी संस्थान कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 से पूर्वीतर राज्यों में हो रही बागवानी फसलों की जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष का अलग से प्रावधान किया जा रहा है। जो किसान सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं यदि उन्हें कौशल विकास योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे स्वयं और समाज को पौष्टिक पीड़कनाशियों से मुक्त संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही ऐसी सब्जियों को बाजार में ऊंचे भाव पर बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। निसंदेह इन सभी क्षेत्रों में कौशल विकास की अहम भूमिका हो सकती है।

**फूलों से रोजगार :** किसान फूलों की खेती द्वारा अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। गेंदा और गुलाब महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल हैं। आज देश के अनेक भागों में कट प्लावर व लूज दोनों की काफी मांग है। इसी प्रकार रजनीगंधा व गलैडिओलस फूलों की खेती करके ग्रामीण खेतों में व्यापक बेराजगारी को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में फूलों की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है।

**खाद्य प्रसंस्करण :** उल्लेखनीय है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए बजट वर्ष 2017–18 के 715 करोड़ रुपये के



મુકાબલે વર્ષ 2018–19 મેં દુગુના કર 1400 કરોડ રૂપયે કર દિયા ગયા। ટમાટર, આલૂ, પ્યાજ કે ઉત્પાદકોं કે લિએ 'ઑપરેશન ગ્રીન' શુરૂ કિયા જા રહા હૈ જિસમે ભંડારણ, પ્રસંસ્કરણ, વિપણન કી સુવિધાએં કિસાનોં કો ઉપલબ્ધ હોંગી। યદિ યે ઑપરેશન સહી દિશા મેં દિલ્લી સે નિકલકર ગાંબ તક હકીકત મેં ઉત્તર જાતા હૈ તો ઇન ફસલોં કે કિસાનોં કો નિશ્ચિત લાભ હોગા। ખરીદ કે માનકોં પર સરકાર ને નીતિ આયોગ ઔર રાજ્ય સરકાર કો જિમ્મા દેને કી બાત કી હૈ।

કેંદ્ર એવં રાજ્ય સરકારોં સ્વરોજગાર કે લિએ પ્રોત્સાહન દેને હેતુ પ્રશિક્ષણ, ઋણ તથા સભિડી દે રહી હૈ। પ્રસંસ્કૃત ખાદ્ય પદાર્થ કો રાષ્ટ્રીય–સ્તર પર બેચને કે લિએ કેંદ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય કૃષિ બાજાર પ્રણાલી વિકસિત કર રહી હૈ। કેંદ્રીય ખાદ્ય પ્રૌદ્યોગિકી અનુસંધાન સંસ્થાન, મૈસૂર તથા રાષ્ટ્રીય પોષણ સંસ્થાન, હૈદરાબાદ જૈસે 15 સંસ્થાન ફલ વ સભિડોં ઔર દૂસરે ખાદ્ય પદાર્થોં કે પ્રસંસ્કરણ પર શોધ એવં પ્રશિક્ષણ કાર્ય કર રહે હુંએં। દેશ કે સભી રાજ્યોં મેં કૃષિ વાગવાની વિશ્વવિદ્યાલયોં મેં ભી ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ કે ક્ષેત્ર મેં પાઠ્યક્રમ સંચાલિત કિયા જા રહા હૈ જિસકે આધાર પર સરકારી વ નિઝી ક્ષેત્ર મેં સ્થાપિત ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મેં ભી રોજગાર કે અવસર ઉપલબ્ધ હોતે હુંએં। બઢે પૈમાને પર ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ક્ષેત્ર કે વિકાસ કે ફલસ્વરૂપ કૃષિ ક્ષેત્ર મેં રોજગાર કા દાયરા બઢને કી સંભાવના બઢેગી। ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ પ્રક્રિયા મેં ફલ વ સભિડોં કા મૂલ્ય બઢ જાતા હૈ। અર્થાત આલૂ ટમાટર જૈસી સભિડોં જોકિ ખુલે બાજાર મેં યદિ 10–15 રૂપયે પ્રતિ કિલો કી દર સે બેચી જાતી હુંએં જિનકો સામાન્ય તાપક્રમ પર અધિક સમય તક સુરક્ષિત નહી રખા જા સકતા હુંએં। ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ દ્વારા પ્રસંસ્કૃત ખાદ્ય પદાર્થ કે મૂલ્ય મેં તીન સે ચાર ગુના તક કી વૃદ્ધિ હો જાતી હૈ તથા ઇસે સામાન્ય તાપક્રમ પર લંબી અવધિ તક સુરક્ષિત ભી રખા જા સકતા હૈ। ઇસસે કિસાનોં કો ઉત્પાદ કા સમુચ્ચિત મૂલ્ય પ્રાપ્ત હોને કે સાથ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મેં લગે યુવકોં કો ભી રોજગાર મિલતા હૈ ઔર ઉપભોક્તા કો વર્ષ ભર પ્રસંસ્કૃત ફલ વ સભિડોં કી આપૂર્તિ સમુચ્ચિત મૂલ્ય પર સુનિશ્ચિત હો પાતી હૈ।

**બીજ ઉત્પાદન :** સભિડોં કી પૈદાવાર બઢાને મેં ઉન્નત સંકર કિસ્મોં વ ઉત્તમ ગુણોં કે બીજોં કા બડા યોગદાન હૈ। સ્વયં પરાગણ વાલી સભિડોં જૈસે મટર, સેમ, બાંકલા, ટમાટર, મિર્ચ, બેંગન, લોબિયા યા ગવાર કી ઉન્નત કિસ્મોં કે બીજ થોડી–સી જાનકારી કે સાથ કિસાન ભાઈ સ્વયં બના સકતે હુંએં। પરાગણ વાલી સભિડોં જૈસે લૌકી, તોરાઈ, કરેલા, ખીરા, કકડી, ખરબૂજા, તરબૂજ, ટિણડા, ફૂલગોભી, પત્તાગોભી, ગાંઠગોભી, મૂલી, શલગમ, ગાજર, પ્યાજ, પાલક, બ્રોકોલી ઇત્યાદિ વ સંકર કિસ્મોં કે બીજ કિસાન થોડી–સી જાનકારી વ ટ્રેનિંગ કે સાથ સફળતાપૂર્વક પૈદા કર સકતે હુંએં। બાગવાની ફસલોં કી ખેતી મેં હોને વાલે ખર્ચ કો

ભી કમ કિયા જા સકતા હૈ। સાથ હી પઢે–લિખે યુવા સભી બીજ ઉત્પાદન કો એક વ્યવસાય કે રૂપ મેં અપનાકર અપની આમદની ભી બઢા સકતે હુંએં।

**મહિલા કિસાન સશક્તીકરણ :** મહિલા કિસાન સશક્તીકરણ પરિયોજના કે માધ્યમ સે નિમ્નલિખિત પહલુઓં પર ધ્યાન દિયા જા રહા હૈ—

- (1) મહિલાઓં કી કૃષિ કાર્યો સે હોને વાલી શુદ્ધ આય કો નિરંતર બઢાના।
- (2) કૃષક મહિલાઓં ઔર ઉનકે પરિવારોં કી ખાદ્ય એવં પોષણ સુરક્ષા મેં સુધાર કરના।
- (3) ખેતી કે તહત ક્ષેત્રફલ, ફસલ તીવ્રતા તથા ખાદ્ય ઉત્પાદન મેં વૃદ્ધિ।
- (4) મહિલાઓ કી કૃષિ કાર્યો મેં કૌશલ તથા ક્ષમતાઓં કો વિકસિત કરના।
- (5) મહિલાઓં કી કૃષિ સંબંધિત ઉપયોગી જાનકારિઓં જૈસે ઉપજાઊ ભૂમિ, કૃષિ ઋણ, પ્રૌદ્યોગિકી એવં અન્ય સૂચનાઓં ઇત્યાદિ તક પહુંચ કો બઢાના;
- (6) કૃષિ ઉત્પાદોં કે બેહતર વિપણન હેતુ બાજાર સંબંધી જાનકારિઓં કી પહુંચ મેં વૃદ્ધિ।

સંક્ષેપ મેં, કૃષિ ઉત્પાદોં કે વિપણન પ્રણાલી કો બેહતર બનાને કે લિએ સરકાર એકીકૃત કૃષિ વિપણન યોજના ઔર ઈ–પ્લેટફાર્મ લેકર આઈ હૈ। ઇસસે કિસાન આસાની સે અનાજ, સભિડોં, ફલ જૈસે ઉત્પાદ બાજારોં તક પહુંચા પાએંગે। પ્રત્યેક ગ્રામ પંચાયત કો 80 લાખ રૂપયે, કિસાનોં કો નૌ લાખ કરોડ રૂપયે કા ઋણ બાંન્ટને જૈસી સૌગાતોં કે સાથ મોદી સરકાર કા પાંચ સાલ મેં કિસાનોં કી આમદની દોગુની કરને કા લક્ષ્ય હૈ। ઇન સભી પહલુઓં પર કૌશલ વિકાસ યોજના કે તહત પ્રશિક્ષણ કા લાભ ઉઠાયા જા સકતા હૈ। (લેખક ઇંટરનેશનલ પ્લાંટ ન્યૂટ્રીશન ઇસ્ટીટ્યુટ, ઇંડિયા પ્રોગ્રામ કે પૂર્વ નિર્દેશક તથા ચંદ્રશેખર આજાદ કૃષિ એવ પ્રૌદ્યોગિકી વિશ્વવિદ્યાલય કે મૃદા એવ કૃષિ રસાયન વિભાગ કે પૂર્વ પ્રાધ્યાપક એવ અધ્યક્ષ રહે હુંએં।)

ઈ–મેલ : kashinathtiwari730@gmail.com

# NeoStencil.com



120+ TOPPERS

60+ TEACHERS

1 PLATFORM

India's #1 Live Online Platform For Govt. Jobs

## Congratulations

OUR TEACHERS & STUDENTS

## OUR STELLAR PERFORMER

Civil Services Examination 2017



**Saumya Sharma**  
**AIR 09**

*I enrolled for online classes of Ethics on NeoStencil.com which not only saved my travel time but also I could attend and revise the classes of S. Ansari Sir anytime.*

120+  
Online Students  
Selected

500+ OUT OF 990  
From Our Partner Teachers  
(Online + Offline)

50+  
In Top 100

✉ info@neostencil.com | ☎ 95990 75552

# कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां

—नरेश सिरोही

सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उत्पादन लागत की कम—से—कम डेढ़ गुनी कीमत पर खरीफ की सभी गैर—घोषित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएगी। केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि फसलों को घोषित एमएसपी पर खरीदा भी जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य एमएसपी से कम है तब सरकार को स्वयं खरीदारी करनी चाहिए अथवा इस तरह की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसके जरिए किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराया जा सके।

**कृषि** भारत के आर्थिक विकास का इंजन है और इससे सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, किसानों को खेती में लगने वाली लागत पर पचास फीसदी लाभ मिले, ऐसा सुनिश्चित करने हेतु गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार को किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही का एहसास है इसलिए सरकार की नीतियों के केंद्र में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है। सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में अधिक बजटीय आवंटन किया गया है। सरकार द्वारा 2014–19 में कृषि क्षेत्र को कुल 2,11,694 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो वर्ष 2009–14 के मुकाबले 74.5 फीसदी अधिक हैं। किसानों के बजट में यह वृद्धि एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, चालू वित्तवर्ष में विभिन्न कृषि जिसों पर न्यूमतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को उनकी लागत पर डेढ़ गुना करने की घोषणा की गई है। ऐसा करके सरकार

ने किसानों से किए गए सबसे महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने का प्रयास किया है।

पिछले चार सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, परंपरागत कृषि विकास योजना सहित अनेक किसान हितैषी योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और तमाम अच्छी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद क्रियान्वयन के स्तर पर राज्य सरकारों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने एवं सरकारी—तंत्र में कमियों के चलते किसानों के जीवन—स्तर में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया है। सरकार इस बिगड़े सिस्टम को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश कर रही है। पूरी व्यवस्था के ओवरहालिंग की जरूरत है।

मैं व्यवस्थागत खामियों को लेकर यहां अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। योजना बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि योजना स्थानीय जरूरत के हिसाब से बने तथा उसके क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सरकार के लिए 'हर खेत तक पानी' पहुंचाना बड़ी चुनौती है। लेकिन स्थानीय—स्तर पर इस चुनौती से जूझने की कोशिश भी हो



રહી હૈ। એસી હી કોશિશ કરતે હુએ બુંડેલખંડ કે એક કિસાન મંગલ સિંહ ને એક ટરબાઈન કા આવિષ્કાર કિયા। મંગલ ટરબાઈન ગાંબ મેં હી બની એસી મશીન હૈ જો બહતી જલધારા સે ચલતી હૈ। આમતૌર પર ગ્રામીણ ઇલાકોં મેં જહાં કિસાન નદી—નાલોં સે ડીજલ યા બિજલી પંથોં કે જરાએ સિંચાઈ કરતે હૈનું, વહાં વે મંગલ ટરબાઈન દ્વારા બિના ડીજલ ઇંજન, બિના બિજલી મોટર સે સિંચાઈ કરતે હૈનું। પાઇપ દ્વારા પાની કો કહીં ભી લે જા સકતે હૈનું। ઇસસે પીને કે લિએ પાની ભી પંપ કર સકતે હૈનું। ઇસમેં લગે ગિયર બોક્સોં કી શાફ્ટ કે દૂસરે સિરે પર પુલી લગાકર કુદ્દી મશીન, આટા ચક્કી, ગન્ના પિરાઈ સહિત કર્ઝ અન્ય કાર્ય ભી કિએ જા સકતે હૈનું યા ફિર જેનરેટર જોડુકર બિજલી ભી બના સકતે હૈનું। મંગલ ટરબાઈન કે પ્રયોગ સે એક ઓર ડીજલ વ બિજલી કી બચત હોતી હૈ તો દૂસરી ઓર પ્રદૂષણ વિશેષકર ગ્રીનહાઉસ ગૈસોં કા ઉત્સર્જન ભી કમ હોગા। સિંચાઈ પર હોને વાલે ખર્ચોં કી દૃષ્ટિ સે દેખેં તો જહાં સરકાર એક વર્ગ કિલોમીટર ભૂમિ કો સિંચિત કરને કે લિએ 5 સે 6 કરોડ રૂપયે ખર્ચ કરતી હૈ। વહીં, મંગલ ટરબાઈન દ્વારા સિંચાઈ કા ખર્ચ માત્ર છહ લાખ રૂપયે કે લગભગ આએગા। દેશ—વિદેશ કે અનેક જાને—માને તકનીકી વિશેષજ્ઞોં એવં અધિકારિયોં ને ભી જાકર મંગલ ટરબાઈન કા અધ્યયન કિયા હૈ ઔર ઇસ આવિષ્કાર કી પ્રશંસા કરતે હુએ ઇસકી વ્યાપક સંભાવનાઓં કી ઓર ધ્યાન દિલાયા હૈ। ઇતને ઉચ્ચ એવં વ્યાપક—સ્તર પર મંગલ ટરબાઈન કી ઉપયોગિતા સ્વીકાર હોને, લિમકા બુક મેં નામ દર્જ હોને તથા પુરસ્કાર વ પેટેંટ પ્રાપ્ત હોને કે બાદ ભી સરકારી તત્ત્વ કી ખામિયોં કે ચલતે ઇસકે આવિષ્કારક પ્રતિભાશાલી મંગલ સિંહ દર—દર કી ઠોકરોં ખા રહે હૈનું। એસે કિસાનોં કો પ્રોત્સાહિત કરના સરકાર કી પ્રાથમિકતા મેં હૈ। કિંતુ સિસ્ટમ કી ખામિયોં કી વજહ સે સરકાર કી તમામ બેહતરીન યોજનાએં જ્યોતિરીન પર નહીં પહુંચ પા રહી હૈનું, જિનસે કિસાનોં કી કિરમત સુધર સકતી હૈ। કર્જ મેં ડૂબા કિસાન આજ અપની ફસલ સરકાર દ્વારા ઘોષિત એમએસપી સે ભી નીચે બેચને કો મજબૂર હૈ। ખેતી લગાતાર ઘાટે કા સૌદા બનતે જાને સે દેશભર કે કિસાન સંગઠનોં દ્વારા રાષ્ટ્રીય કિસાન આયોગ (સ્વામીનાથન આયોગ) કી સિફારિશોં કો લાગુ કરને ઔર કર્જ માફી કી માંગ ભી ઉઠ રહી હૈ।

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેંદ્ર મોદી કે નેતૃત્વ મેં બની રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠબંધન વાલી સરકાર 26 મર્ચ, 2018 કો ચાર સાલ પૂરે કર ચુકી હૈ। સરકાર દ્વારા કિએ ગએ કામકાજ કા મૂલ્યાંકન કરને સે પહલે હમેં વિગત સત્તર સાલોં પર એક નજર ડાલની હોગી। તથી હમ સમજ પાએંગે કી ચાર સાલોં મેં કૃષિ ક્ષેત્ર મેં કિતના અચ્છા કામ હુ�आ હૈ। આજાદી કે સત્તર સાલોં મેં કૃષિ ક્ષેત્ર પરિવર્તનોં કે કર્ઝ દૌર સે ગુજરા હૈ, ઉસ પર ભી ધ્યાન દેને કી આવશ્યકતા હૈ। દેશ કી આજાદી કે બાદ પહલા દૌર 1947 સે 1968 તક કા હૈ જિસમે બુઆઈ ક્ષેત્ર કા વિસ્તાર, સિંચાઈ કે સંસાધનોં મેં વૃદ્ધિ ઔર ભૂમિ સુધાર કાનૂનોં કી મુખ્ય ભૂમિકા રહી હૈ। દૂસરા કાલ 1968 સે 1980 તક કા હૈ, જિસમે અધિક ઉત્પાદન

વાળી બૌની કિસ્મોં, ઉર્વરકોં, કીટનાશકોં એવં નવીન તકનીક કા પ્રયોગ હુ�आ, જિસે હરિતક્રાંતિ કે પ્રાર્બુદ્ધ કા કાલ કહા જાતા હૈ। તીસરા કાલખંડ વર્ષ 1981 સે 1991 તક કા હૈ, જિસ દૌરાન કૃષિ ઉત્પાદોં કે લિએ ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય કી નીતિ, સુનિશ્ચિત સરકારી ખરીદ ઔર ભંડારણ એવં વિતરણ કી રાષ્ટ્રવ્યાપી વ્યવસ્થા હુઈ। ચૌથા કાલ વર્ષ 1991–1998 તક કા હૈ, જિસે ઉદારીકરણ, ઔદ્યોગીકરણ ઔર વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન કી સ્થાપના કા દૌર કહા જાતા હૈ। પાંચવાં કાલ વર્ષ 1999 સે 2014 તક કા રહા। પરંપરાગત જૈવિક ખેતી કો બઢાવા દેને, ગ્રામીણ આધારભૂત ઢાંચા મસલન, સડક, બિજલી, શિક્ષા, ચિકિત્સા આદિ કે વિકાસ તથા કૃષિ ક્ષેત્ર મેં આઈ વિસંગતિયોં કો દૂર કરને કે લિએ નવંબર 2004 મેં પ્રોફેસર એમએસ સ્વામીનાથન કી અધ્યક્ષતા મેં રાષ્ટ્રીય કિસાન આયોગ કા ગઠન કિયા ગયા। આયોગ ને અપની પાંચવોં એવં અંતિમ રિપોર્ટ 4 અક્ટૂબર, 2006 કો કેંદ્ર સરકાર કો સૌંપ દી।

સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ કે બાદ કૃષિ ક્ષેત્ર મેં આશાતીત વૃદ્ધિ હુઈ હૈ, ઇસ તથ્ય સે કોઈ ભી ઇંકાર નહીં કર સકતા હૈ। ક્યોંકિ વર્ષ 1951 મેં જહાં ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદન 5.10 કરોડ ટન થા વહી આજ બઢકર 27.749 કરોડ ટન તક પહુંચ ગયા હૈ। ખાદ્યાન્ન કે સાથ ફલ—સબ્જી, દૂધ ઔર મછલી કે ઉત્પાદન મેં ભી રિકોર્ડ વૃદ્ધિ હુઈ હૈ। ઇસમેં કોઈ દો રાય નહીં હૈ કી હમ અધિક ઉત્પાદન ઔર ખાદ્ય—સુરક્ષા કે લક્ષ્ય કો પ્રાપ્ત કરને મેં કામયાબ હુએ હૈનું। લેકિન, ઇસ ભારી સફલતા કે બાવજૂદ અપનાઈ ગઈ કૃષિ પદ્ધતિ સે અનેક એસી સમસ્યાએં ભી પૈદા હુઈ જિસને કૃષિ ઔર કિસાનોં કો સંકટ મેં લા ખડા કિયા હૈ। કૃષિ પદ્ધતિ કે અલાવા કૃષિ પારિસ્થિતિકી ઔર નીતિયાં ભી કિસાન કે અનુરૂપ નહીં રહીંનું, જોસે બઢતી આબાદી કી વજહ સે કિસાન કી જોત કા આકાર ભી એક હેકટેયર સે કમ હો ગયા હૈ। પહલે કે મુકાબલે કૃષિ ભૂમિ પર આશ્રિત જનસંખ્યા કા ભાર ભી ઢાઈ ગુના સે અધિક હો ગયા હૈ।

નીતિયોં કે સ્તર પર દેખેં તો સાપેક્ષ મૂલ્યોં કો રુખ કિસાનોં કે અહિત મેં રહા હૈ। કૃષિ ઉત્પાદોં કે મૂલ્ય, દૂસરે ઉત્પાદોં કે મૂલ્ય કે મુકાબલે 82 સે 88 ફીસદી કે બીચ રહે હૈનું। ઇસ અહિતકારી મૂલ્ય પ્રણાલી કે કારણ અર્થવ્યવસ્થા કે અન્ય વર્ગોં કી અપેક્ષા કિસાનોં કો ઔસતન 15 પ્રતિશત પ્રતિ વર્ષ ઘાટા ઉઠાના પડ રહા હૈ। ઇસકા સીધા પરિણામ યહ હુ�आ કી લગભગ હર સાત વર્ષ મેં કૃષિ કાર્ય મેં લગે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કી ઔસત આય, અન્ય વ્યવસાયોં મેં લગે વ્યક્તિયોં કે મુકાબલે આધી હોતી ચલી ગઈ। કૃષિ ક્ષેત્ર કી સભી વિસંગતિયોં કી ચિંતા ઔર અવિલંબ સમાધાન કરના લંબે સમય સે અપેક્ષિત હૈ જિસમે રાષ્ટ્રીય કિસાન આયોગ 1976 કી વ્યાપક રિપોર્ટ એવં રાષ્ટ્રીય કિસાન આયોગ (સ્વામીનાથન આયોગ) 2004 દ્વારા 4 અક્ટૂબર, 2006 કો સૌંપી અંતિમ રિપોર્ટ કો લાગુ કરના ભી શામિલ હૈ જિસમે ઉન્હોને કિસાનોં કે સંકટ ઔર આત્મહત્યાઓં કે કારણોં પર ખાસતૌર સે ફોકસ કરતે હુએ ઉનકે લિએ રાષ્ટ્રીય નીતિ બનાને કી સિફારિશ કેંદ્ર સરકાર સે



की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 2014 तक इन सिफारिशों को ठोस नीतियों में बदले जाने और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ठोस पहल नहीं हो सकी।

आजादी के सत्तर वर्षों बाद यह पहला अवसर है जब सरकार का फोकस उत्पादन की जगह किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। नतीजन कृषि पद्धति और कृषि परिस्थितियों में सुधार की सिफारिशों को ठोस नीतियों में बदलकर धरातल पर उतारने का सार्थक प्रयास किया गया।

वर्तमान सरकार ने कृषि और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि राज्यों का विषय होने के कारण केंद्र की योजनाओं का अलग—अलग राज्यों में अलग—अलग परिणाम मिला है। कई राज्यों में योजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिले हैं जिनका लाभ किसानों को मिला है। लेकिन कई राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि उपज के भाव, कृषि कर्ज, व्यापार जैसे महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय केंद्र सरकार करती है। इसी तरह पौध संरक्षा, जैव—विविधता, खाद्य कानून, कृषक अधिकार कानून, गांवों में आधारभूत ढांचे और मंडियों तथा कृषि मद के लिए धनराशि प्राप्त करने में भी केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका है। लेकिन भारतीय संविधान में कृषि राज्यों का विषय होने के कारण तमाम कानूनों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। दरअसल हमारे संविधान में कामकाज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वे हैं जो केंद्र की सूची में हैं जिन पर कायदे—कानून का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा, वे जो समर्वती सूची में हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार

है। अलबत्ता मतभेद की स्थिति में केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है। तीसरा, वे विषय हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और कृषि इसी सूची में है। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 70 सालों में राज्य खेती—किसानी की जरूरत पूरी कर पाएं हैं? क्या वैश्वीकरण के कारण कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार की भूमिका का बढ़ाना जरुरी है? शायद इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कृषि को समर्वती सूची में रखने की सिफारिश की है। आज किसानों की विकाराल होती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है तथा योजना बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर पुनः विचार कर बदलाव की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी परिकल्पना को वर्ष 2022 तक साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन सभी तीन विभागों के तहत संचालित विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और मिशनों को एक नई दिशा प्रदान की गई है और एक अंतर—मंत्रालयी समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति में व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिकों, नीति—निधारकों और अर्थशास्त्रियों सहित प्रगतिशील किसानों को भागदारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि “मैं वर्ष 2022 तक, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाए, किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है, पर यह केवल एक चुनौती नहीं है। एक अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधनों एवं कार्यान्वयन में सुशासन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।”

सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उत्पादन लागत की कम—से—कम डेढ़ गुनी कीमत पर खरीफ की सभी गैर—घोषित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएगी। केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि फसलों को घोषित एमएसपी पर खरीदा भी जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य एमएसपी से कम है तब सरकार को स्वयं खरीदारी करनी चाहिए अथवा इस तरह की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसके जरिए किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराया जा सके। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से एक ऐसे कार्यतंत्र की व्यवस्था करेगा, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो सके।

किसानों की सी—2 फार्मूले से एमएसपी तय करने की बात को ध्यान में रखते हुए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्रीसमूह का गठन किया गया है, जो जल्द ही इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करेगा। दरअसल कृषि और किसानों के लिए ये फैसला भील का पथर साबित होगा। किसानों को प्राकृतिक आपदा और दूसरे नुकसानों से संरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री ने पुरानी योजना में कई बदलाव करते हुए इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया है। इस योजना में प्रीमियम घटाया गया है और क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसी क्रम में इस वर्ष 2018—19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत 44.59 प्रतिशत वृद्धि कर इस योजना के बजट को 9000.75 करोड़ से बढ़ाकर 13014.15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेहतर करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पर गौर करना होगा। कैग ने फसल बीमा योजनाओं के अमल में वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई अनियमिताओं एवं कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया है कि तमाम किसान बैंकों की अनदेखी के चलते बीमा के अपने दावों को खो देते हैं। फसल बीमा योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों ने बीमा को लेकर बैंकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में कमियों के चलते भी किसानों के दावों को खारिज किया है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि मुआवजे के दावों की रकम को बैंकों ने लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया। इसीलिए कैग ने सरकार से कहा है कि इन तमाम निजी बीमा कंपनियों का लेखा—जोखा सार्वजनिक तौर पर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जनता के करों से एकत्रित पैसों से भारी मात्रा में फंड दिए जाते हैं। फसल बीमे का मुआवजा तय करने में क्राप कटिंग एवं टीआरएस (टाइमली रिकॉर्डिंग स्कीम) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को और अधिक समयबद्धता और गंभीरता के साथ संपादित कराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कार्य कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्राप कटिंग के नमूनों के परिणाम से नुकसान का पता लगाया जाता है तथा मुख्य फसलों के उत्पादन व उत्पादकता की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाता है।

लेकिन कर्मचारियों की शिथिलता के कारण इस महती कार्य में चूक हो जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' के तहत सिंचाई के संसाधनों में बढ़ोत्तरी हुई है और सिंचाई के तहत आने वाली ज़मीन में इजाफा हुआ है। माइक्रो इरिगेशन में भी काम तेजी से हो रहा है। इसके लिए खास बजट का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक लगभग 10.48 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। करोड़ों कार्ड बनने के बाद कितने किसान इसके अनुसार न्यूट्रिएंट उपयोग कर रहे हैं, अभी इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन नीमलेपित यूरिया का 100 फीसदी लक्ष्य पूरा हो गया है। इससे जहां यूरिया की कमी से परेशान किसान को फायदा हुआ है। वहीं यूरिया का इंडस्ट्री को डायवर्जन बंद हुआ है और सरकार की सब्सिडी बची है। प्रधानमंत्री सतत कृषि प्रबंधन द्वारा हर स्तर पर उत्पादन और उत्पादकता बनाए रखते हुए, रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए देशी पारंपरिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। अभिलेखों यानी लैंड रिकार्ड्स को डिजिटल करने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कई राज्यों में यह काम काफी आगे बढ़ गया है। तेलंगाना में तो रिकॉर्ड डिजिटल करने के बाद अब उनको आधार नंबर से जोड़ने का भी काम शुरू हो चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही पिछले चार सालों के दौरान देश के गांवों में साढ़े पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है जिससे किसानों की बाजार तक कनेक्टिविटी का बेहतर ढांचा तैयार हुआ है। जाहिर है कि मंडी और बाजार तक किसानों की आसान पहुंच उन्हें उनकी फसलों का अधिक लाभ भी दिलाएगी।

चार सालों में खेती—किसानी से जुड़ी योजनाएं सरकार द्वारा की गई अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अपने 4 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय आय बढ़ाने और उन्हें खेती हेतु प्रोत्साहित करने हेतु संरक्षण एवं सुरक्षा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत—सी व्यावहारिक समस्याएं सामने आएंगी, हमेशा इनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी, जो समय—समय पर होने भी चाहिए। वर्तमान समय में किसानों की हालत अच्छी नहीं है और उनके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार में किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाई देता है। सरकार ने किसानों के हितों में न केवल बेहतरीन और ठोस योजनाओं का निर्माण किया है, बल्कि उन्हें ज़मीन पर सार्थक रूप से उतारने का प्रयास भी किया है। इसके सुखद नतीजे आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे।

(लेखक कृषि एवं किसान मामलों के विशेषज्ञ तथा दूरदर्शन किसान चैनल के संस्थापक सलाहकार रहे हैं।)

ई—मेल : nnareshsirohi@gmail.com



# गांवों में शिक्षा की अलख जगाता सर्व शिक्षा अभियान

## सब पढ़ें सब बढ़ें

—सुरभि जैन और पूरबी पटनायक

शिक्षित समाज किसी राष्ट्र के विकास की अनिवार्य पूर्व-शर्त है। जैसे—जैसे नौजवान भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, भावी पीढ़ी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत बुनियाद रखे जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल निश्चय ही ग्रामीण भारत को अधिकार—संपन्न बनाने के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

**शि**क्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और समाजमूलक समाज के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इक्कीसवीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुशिक्षित जनता का सुसंगत ज्ञान, विचार और कौशल से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के लिए तो यह बात विशेष रूप से सत्य है जहां 10 से 24 आयु वर्ग के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। यहीं वे लोग हैं जो देश के भविष्य की बुनियाद रखते हैं। इन्हाँ ही नहीं, भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए शिक्षा संबंधी किसी भी नीति का केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों को बनाना चाहिए।

### प्राथमिक शिक्षा के प्रति भारत की वचनबद्धता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के लागू होने के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इन प्रयासों को 1980 और 1990 के दशकों में योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से और तेज किया गया जिनमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षाकर्मी परियोजना, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, महिला समाख्या, लोक जुंबिश परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान देशभर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित और केंद्र द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संबंधी अधिनियम के पारित होने से इसे और बल मिला। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ और इससे देश में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुरूप बनाया गया ताकि अधिनियम को लागू करने में राज्यों और

केंद्रशासित प्रदेशों की मदद की जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के समग्र लक्ष्यों में शिक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाना और शिक्षा पूरी कराना, शिक्षा के क्षेत्र में लिंग और सामाजिक श्रेणी संबंधी अंतर को पाठना और बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि करना जैसी बातें शामिल थीं। सर्व शिक्षा अभियान में कई तरह के उपाय शामिल थे जिनमें अन्य बातों के अलावा नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण, उनमें अतिरिक्त कमरों, शौचालयों व पीने के पानी की सुविधा, शिक्षकों और समय—समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक संसाधनों में मदद देना, पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता देना शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान को भारत के सभी जिलों में लागू किया गया और इसमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम पहलों के विकेंद्रित नियोजन और कार्यान्वयन के लिए व्यापक विस्तार वाला समेकित ढांचा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान देश में अकेला सबसे बड़ा और समग्र कार्यक्रम था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। इसमें 10 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों और वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा केंद्रों को शामिल करते हुए 20 करोड़ बच्चों को इसके दायरे में लिया गया था।

### प्राथमिक स्तर पर प्रगति

पिछले दशक में भारत ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाने के लिए शानदार प्रगति की है। आज 14.6 लाख प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 19.67 करोड़ बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है जहां देश के कुल प्राथमिक विद्यालयों में से 85.4 प्रतिशत विद्यालय स्थित हैं। देश में प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वाले कुल बच्चों में से 74.5 प्रतिशत बच्चे इन्हीं ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते हैं। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो पहल की गई

હૈ ઉસકા સબસે અધિક પ્રભાવ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોं મેં પડ્ય હૈ।

તમામ રાજ્યોં ઔર કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં મેં પ્રમુખ શૈક્ષિક સંકેતકોં મેં જર્બર્ડસ્ટ પ્રગતિ હુઈ હૈ। સમેકિત જિલા સૂચના શિક્ષા પ્રણાલી (યૂડીઆઈએસઈ) 2015–16 કે અનુસાર પ્રાથમિક–સ્તર પર સકળ દાખિલા દર 99.21 પ્રતિશત ઔર ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તર પર 92.81 પ્રતિશત રહી જો પ્રાથમિક સ્તર પર લગભગ સભી બચ્ચોં કે સ્કૂલ મેં દાખિલા લેને કો પ્રદર્શિત કરતા હૈ। વિદ્યાર્થીઓં ઔર શિક્ષકોં કા અનુપાત જો 2009–10 મેં 32 થા, 2015–16 મેં સુધરકર 25 હો ગયા। યૂડીઆઈએસઈ 2015–16 કે અનુસાર પ્રાથમિક–સ્તર પર સ્કૂલી શિક્ષા અધૂરી છોડને વાલે બચ્ચોં કી ઔસત વાર્ષિક દર 2009–10 કે 6.76 પ્રતિશત સે ઘટકર 2014–15 મેં 4.13 પ્રતિશત રહ ગઈ। યૂડીઆઈએસઈ 2015–16 કે અનુસાર પ્રાથમિક સ્તર સે ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તર પર જાને વાલે બચ્ચોં કી દર જો 2009–10 મેં 85.17 પ્રતિશત થી, 2014–15 મેં બઢકર 90.14 પ્રતિશત હો ગઈ। સ્કૂલોં મેં પ્રાથમિક સ્તર પર લિંગ સંબંધી સંતુલન કો પ્રદર્શિત કરને વાલા લિંગ સમાનતા સૂચકાંક પ્રાથમિક સ્તર પર 2014–15 મેં 0.93 પ્રતિશત ઔર ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તર પર 0.95 પ્રતિશત પર પહુંચ ગયા થા।

ઇસમેં કોઈ સંદેહ નહીં કી કાર્યક્રમ કે અંતર્ગત રાજ્યોં ઔર કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં દ્વારા કિએ ગએ પ્રયાસોં સે સ્કૂલોં તક પહુંચ તો બઢી હૈ લેકિન ઇન સ્કૂલોં મેં દી જાને વાલી શિક્ષા કી ગુણવત્તા કો લેકર ચિંતાએં વ્યક્ત કી જાતી રહી હૈનું। યહ સવાલ ભી ઉઠા હૈ કી ક્યા યે બચ્ચે કુછ સીખ્યે ભી પા રહે હૈનું, યા નહીં। દેશ કી ભાવી પીડી કે લિએ ઇસકે જબરદસ્ત પરિણામ હો સકતે હૈનું ક્યોંકિ ઇન્હીં બચ્ચોં કો બઢે હોકર રાષ્ટ્ર કે વિકાસ કી દિશા તથા કરની હૈ।

### હાલ કી પહેલ

શિક્ષા કી ગુણવત્તાપૂર્ણ બનાને કી આવશ્યકતા કે મહત્વ કો સમજાતે હુએ કેંદ્ર સરકાર ને રાજ્ય સરકારોં કે સહયોગ સે બચ્ચોં કે સીખને કે સ્તર મેં સુધાર કે લિએ કરી પહેલ કી હૈનું। ઇનમેં સે પ્રમુખ ઇસ પ્રકાર હૈનું :

**'પઢે ભારત, બઢે ભારત'** : વિભિન્ન અનુસંધાન ઔર અધ્યયનોં સે યહ બાત સાબિત હો ગઈ હૈ કી પહલી ઔર દૂસરી કક્ષા બચ્ચોં કી શિક્ષા કે દો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ચરણ હૈનું જીનમેં બચ્ચોં કો ભાષા ઔર અંકોં કે માધ્યમ સે સીખને કી દુનિયા સે પરિચિત કરાયા જાતા હૈ। જો બચ્ચે ઇન દો કક્ષાઓં મેં સીખને મેં અસફલ હો જાતે હૈનું વે પઢાઈ મેં પિછડે જાતે હૈનું ઔર ઉનકે લિએ અન્ય વિષયોં કો પઢને—સમજાને મેં મુશ્કિલોં આતી હૈનું। ઇસલિએ શુરુઆત મેં પઢના—લિખના ઔર સમજાના તથા ગણિત કા જ્ઞાન દેશ મેં પ્રાથમિક શિક્ષા કી ગુણવત્તા મેં સુધાર કે લિએ અત્યંત આવશ્યક હૈ। સર્વશિક્ષા અભિયાન કે તહેત એક રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉપ—કાર્યક્રમ 'પઢે ભારત, બઢે ભારત' અગસ્ત 2014 મેં શુરુ કિયા ગયા જિસકા ઉદ્દેશ્ય પઢને—લિખને કે સાથ—સાથ ઉસે સમજાને મેં બચ્ચોં કી રૂચિ જગાના ઔર બનાએ રખના; તથા અપને ભૌતિક ઔર સામાજિક જગત સે સંબંધિત ગણિત મેં ઉનકી સ્વાભાવિક વ સકારાત્મક રૂચિ જગાકર ઉસે બનાએ રખના થા।

યહ કાર્યક્રમ ઇસ પૂર્વશર્ત પર આધારિત હૈ કી પુસ્તકોં મેં બચ્ચોં કી ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ ઔર સામાજિક દૃષ્ટિ સે પ્રાસંગિક દિલચસ્પી કે સાથ—સાથ ઉનકે મુદ્રિત સામગ્રી કો પઢને—લિખને સંબંધી વિભિન્ન ગતિવિધિઓં મેં સક્રિય ઔર ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ તરીકે સે જુડને કી જરૂરત હોતી હૈ। ઇસ પહેલ કે તહેત રાજ્યોં ઔર કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં ને પૂરક અધિગમ સામગ્રી તૈયાર કરને ઔર પઢને કી જગહોં કે વિકાસ તથા બચ્ચોં કે લિએ એકિવિટી કિટ બનાને જૈસે કર્ઝ કદમ ઉઠાએ હૈનું જિસસે ઉન્હેં સક્રિય રૂપ સે ઔર ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ તરીકે સે પઢાઈ સે જોડે રખા જા સકા હૈ। યહ પહેલ બચ્ચોં મેં વિસ્તૃત આધારભૂત કૌશલોં કે વિકાસ મેં મદદ કરકે ઉચ્ચ—સ્તર કી ક્ષમતાઓં કે સૃજન કી મજબૂત બુનિયાદ ડાલને કે મકસદ સે કી ગઈ હૈ।

એક કમી યહ મહસૂસ કી ગઈ કી પ્રત્યેક કક્ષા કે અંત મેં અધ્યાપકોં ઔર બચ્ચોં કે લિએ કોઈ લક્ષ્ય નિર્ધારિત નર્હી કિએ ગએ હૈનું। ઇસી બાત કો ધ્યાન મેં રખતે હુએ શિક્ષા કે અધિકાર સંબંધી કેંદ્રીય કાનૂન મેં 20 ફરબરી, 2017 કો સંશોધન કિયા ગયા ઔર પ્રત્યેક કક્ષા મેં પ્રત્યેક વિષય કે લિએ સીખને કા પરિણામ નિર્ધારિત કિયા ગયા। ઇસી કે અનુસાર પ્રત્યેક કક્ષા મેં ભાષાઓં (હિન્દી, અંગ્રેજી ઔર ઉર્દૂ), ગણિત, પર્યાવરણ અધ્યયન, વિજ્ઞાન ઔર સામાજિક વિજ્ઞાન મેં પ્રાથમિક સ્તર કે સીખને કે પરિણામોં કા અંતિમ રૂપ સે નિર્ધારણ કર દિયા ગયા ઔર સભી રાજ્યોં ઔર કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં કે સાથ ઇન્હેં સાઝા કિયા ગયા। યે માનદંડ [http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/Print\\_Material.html](http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/Print_Material.html) વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ હૈનું। ઇન્સે શિક્ષકોં ઔર માતા—પિતા કો યહ સુનિશ્ચિત કરને કા મૌકા મિલેગા કી બચ્ચે વાંછિત કૌશલ સહી—સહી હાસિલ કર પા રહે હૈનું। ઇસ્સે જરૂરત પડને પર સુધારાત્મક કદમ ઉઠાકર સભી વિદ્યાર્થીઓં કો સક્ષમ બનાને કે લિએ સીખને કે અવસર ઉપલબ્ધ કરાને મેં ભી મદદ મિલેગી।

સીખને કે પરિણામોં કે આધાર પર 2017–18 મેં દેશ કે સભી 36 રાજ્યોં/કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં કે 700 જિલોં મેં સરકારી ઔર સહયોગત પ્રાપ્ત સ્કૂલોં મેં કક્ષા 3, 5 ઔર 8 કે બચ્ચોં કો રાષ્ટ્રીય ઉપલબ્ધી સર્વેક્ષણ કિયા ગયા। ઇસમેં 1,10,000 સ્કૂલોં કે 20 લાખ સે અધિક વિદ્યાર્થીઓં કે સીખને કે સ્તર કા આકલન કિયા ગયા। વિદ્યાર્થીઓં કે સીખને સંબંધી ઉપલબ્ધીઓં કો યહ શાયદ સબસે બડા સૈંપલ સર્વેક્ષણ થા। આંકડોં કે પ્રારંભિક વિશ્લેષણ સે પતા ચલા કી સીખને કી પ્રક્રિયા કે નિષ્પાદન મેં ગ્રામીણ ઔર શહીરી બચ્ચે એક સમાન સ્તર પર પાએ ગએ। વિશ્લેષણ કે આધાર પર જિલાવાર ઔર રાજ્યવાર રિપોર્ટકાર્ડ તૈયાર કિએ ગએ જિન્હેં સાર્વજનિક સંદર્ભ કે લિએ ઇસ વેબસાઇટ (<http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/Training.html>) પર રખા ગયા હૈ। જિલા—સ્તર કે રિપોર્ટકાર્ડ સે બચ્ચોં કે સીખને સે સંબંધિત કક્ષાવાર ઔર વિષયવાર જાનકારી મિલતી હૈ। ઇસ્સે યહ ભી પતા ચલતા હૈ કી જિલે મેં કહાં પર સુધાર કી જરૂરત હૈ ઔર કહાં નીતિ/શિક્ષાશસ્ત્રીય

હસ્તક્ષેપ કી આવશ્યકતા હૈ। ઇસસે શિક્ષા કી ગુણવત્તા મેં સુધાર કી અચૂક કાર્યનીતિ બનાને કે લિએ ઉપયોગી જાનકારી ભી પ્રાપ્ત હોતી હૈ। રાજ્ય સંબંધી રિપોર્ટકાર્ડ સે પરખે જા ચુકે સમી માનદંડોં પર સીખને કે પરિણામોં કા પતા ચલતા હૈ જિસકે આધાર પર અધિકારી શિક્ષકોં કે પ્રશિક્ષણ ઔર નીતિગત ઉપાયોં કી કમજોરિયોં ઔર કમિયોં કો દૂર કર સકતે હોય। ઇન રિપોર્ટકાર્ડોં કે વિસ્તૃત વિશ્લેષણ સે શૈક્ષિક નીતિયાં બનાને, નિયોજન ઔર રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય, જિલા ઔર કક્ષા સ્તર પર બચ્ચોં કે અધિગમ કે સ્તર મેં સુધાર કે લિએ મહત્વપૂર્ણ જાનકારી પ્રાપ્ત કી જા સકતી હૈ। (4) શિક્ષક કિસી ભી શૈક્ષિક પ્રણાલી કી ધૂરી હોય ઔર કક્ષા મેં કયા હો રહા હૈ, ઇસકા નિર્ધારણ કરને વાળા સબસે મહત્વપૂર્ણ ઘટક હોય। શિક્ષા કા અધિકાર અધિનિયમ, 2009 કે અનુસાર સમી સેવારત શિક્ષકોં કે પાસ કુછ ન કુછ વ્યાવસાયિક યોગ્યતા હોની ચાહેલી હૈ। એસે સમી શિક્ષક (કરીબ 13 લાખ) યે યોગ્યતાએં હાસિલ કર સકે ઇસકે લિએ રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિદ્યાલયી શિક્ષા સંસ્થાન કો દો સાલ કા ઑનલાઇન પાઠ્યક્રમ શુરૂ કરને કી જિમ્મેદારી સૌંપી ગઈ હૈ। ઇસ પાઠ્યક્રમ કે લિએ અધ્યયન સામગ્રી સંસ્થાન ને સ્વયં-શિક્ષા રીતિ સે તૈયાર કી હૈ ઔર 'સ્વયં' પ્લેટફાર્મ પર ઑડિયો/વીડિયો વ્યાખ્યાન, મુદ્રણીય સામગ્રી/ડાઉનલોડ કી જા સકને વાળી પાઠ્ય સામગ્રી કે રૂપ મેં અપલોડ કી હૈ। શંકાઓં ઔર જિજાસાઓં કે સમાધાન કે લિએ ઑનલાઇન ચર્ચાઓં કે સાથ-સાથ પરીક્ષા ઔર કિવજ કે જરિએ અપના મૂલ્યાંકન ખુદ કરને કી ભી ઇંતજામ કિએ ગએ હોય। ઇસ સમૂચી પ્રક્રિયા કો બડા આસાન ઔર ઇંટરएક્ટિવ બના દિયા ગયા હૈ તાકિ શિક્ષક પાઠ્યક્રમ મેં વાંછિત કૌશલ પ્રાપ્ત કરને કે લિએ પૂરા પ્રયાસ કર સકે ઔર બાદ મેં યહી કૌશલ ઉન્હેં અપની શિક્ષણ સંબંધી જિમ્મેદારિયોં કો કારગર તરીકે સે પૂરા કરને મેં મદદ કર સકે। સંભવત: યહ બડી ભારી તાદાદ મેં શિક્ષકોં કે વ્યાવસાયિક કૌશલ સે યુક્ત કરને કી દિશા મેં ઉઠાયા ગયા સબસે બડા કદમ હૈ ઔર યહ હમારે દેશ કે શિક્ષકોં, ખાસતૌર પર ગ્રામીણ ઇલાકોં કે શિક્ષકોં કો ગુણવત્તાપૂર્ણ શિક્ષણ કૌશલ સે યુક્ત કરને મેં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાએગા।

કેંદ્ર સરકાર ને 2017 સે સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર કી ભી શુરૂઆત કી હૈ જિસકા ઉદ્દેશ્ય બચ્ચોં કે સાફ-સફાઈ કે બારે મેં જાગરૂક બનાના ઔર ઉન્હેં સ્વચ્છતા કી આદતોં વ તૌર-તરીકોં કો અપનાને કે લિએ પ્રેરિત કરના હૈ। ઇસસે બચ્ચોં કો સ્કૂલી શિક્ષા પૂરી કરને મેં તો મદદ મિલેગી હી, ગંદગી કી વજહ સે હોને વાળી બીમારિયાં કમ કરને તથા ઉન્હેં ભવિષ્ય કે જિમ્મેદાર નાગરિક બનાને મેં ભી મદદ મિલેગી। પુરસ્કાર કી શુરૂઆત કે પહલે હી સાલ મેં 2.5 લાખ સે અધિક સરકારી સ્કૂલોં ને પ્રતિયોગિતા મેં ઑનલાઇન હિસ્સા લિયા ઔર ઇનમેં સે 91 પ્રતિશત સ્કૂલ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં સે થે। ઇન સ્કૂલોં કા સમગ્ર સ્વચ્છતા, પીને કે પાની કી વ્યવસ્થા, શૌચાલય ઔર કક્ષાઓં મેં સફાઈ કો ધ્યાન મેં રહ્યે હુએ નિરીક્ષણ કિયા ગયા। જિલા ઔર રાજ્ય-સ્તર પર કડી ચયન પરીક્ષા સે ગુજરને કે બાદ 712 સ્કૂલોં કો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોં કે લિએ ચુના ગયા।

ઇનમેં સે 126 સ્કૂલ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં કે થે। ઇસસે યહ બાત સ્પષ્ટ હો જાતી હૈ કે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં કે સ્કૂલ શહરી સ્કૂલોં સે જરા ભી પીછે નહીં હોય ઔર રાષ્ટ્રીય-સ્તર કે ઉત્કૃષ્ટતમ સ્કૂલોં કો કડી ટકકર દે સકતે હોય।

### આગે કા રાસ્તા

કેંદ્ર સરકાર ને અબ ફેસલા કિયા હૈ કે વહ સ્કૂલી શિક્ષા પર પૂરી સમગ્રતા સે વિચાર કરેગી ઔર પ્રાથમિક, ઉચ્ચ પ્રાથમિક, માધ્યમિક વ વરિષ્ઠ માધ્યમિક જૈસે ખંડોં મેં વિભાજિત કર ઇસે નહીં દેખા જાએગા। વર્ષ 2018-19 સે 'સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન' નામ કી કેંદ્ર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજના શરૂ કી ગઈ હૈ જિસકા ઉદ્દેશ્ય પૂર્વ-વિદ્યાલય-સ્તર સે ઉચ્ચ માધ્યમિક-સ્તર તક ગુણવત્તાપૂર્ણ સમાવેશી ઔર સમતામૂલક શિક્ષા ઉપલબ્ધ કરાના હૈ। ઇસમેં ઐસી વ્યવસ્થા કી ગઈ હૈ જિસસે કે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી સુચારુ રૂપ સે લગતાર શૈક્ષિક પ્રગતિ કર સકે ઔર સ્કૂલી શિક્ષા કે વિભિન્ન સ્તરોં કો બિના કિસી બાધા કે પૂરા કરે।

ઇસ કાર્યક્રમ મેં સ્કૂલ પ્રશાસન, શિક્ષકોં ઔર છાત્રોં કો ટેકનોલોજી કે જરિએ સમન્વિત કરતે હુએ સમી સ્તરોં પર શિક્ષા કી ગુણવત્તા મેં સુધાર કરને પર ધ્યાન કેંદ્રિત કિયા ગયા હૈ। સ્કૂલી શિક્ષા કે કાર્ય નિષ્ઠાદન મેં આમૂલ પરિવર્તન કે જરિએ સુધાર કરને કા લક્ષ્ય રહ્યા ગયા હૈ જિસકે લિએ સ્કૂલોં કો ઔર અધિક કારગર બનાને ઔર ઉન્કી સંસ્થાગત ક્ષમતા કો બનાએ રહ્યા હોય કે ઉપાય કરને કા પ્રાવધાન કિયા ગયા હૈ। ઇસ કાર્યક્રમ કા મુખ્ય જોર દેશ કે શૈક્ષિક રૂપ સે પિછલે ઇલાકોં કા ખાસતૌર પર ધ્યાન રહ્યે હુએ રાજ્યોં કો શિક્ષા કી ગુણવત્તા મેં સુધાર કે લિએ પ્રોત્સાહિત કરના હૈ। કાર્યક્રમ મેં વિશેષ જરૂરતોં વાળે બચ્ચોં, બાળિકાઓં ઔર ઉપેક્ષિત સમુદાયોં કા વિશેષ ધ્યાન રહ્યે હુએ એક ઐસે બદલાવ કી શુરૂઆત કી ગઈ હૈ જો સમતામૂલક ઔર સમાવેશી હો।

ઇસ સમન્વિત દૃષ્ટિકોણ સે સેવાકાલીન ઔર સેવા-પૂર્વ શિક્ષા પ્રશિક્ષણ એવં શિક્ષા કી દિશા મેં નર્ઝ ડિજિટલ પહલ કે માધ્યમ સે ડિજિટલ અધિગમ સામગ્રી, અભિનવ શિક્ષણ કૌશલ ઔર ક્ષમતા સૃજન આદિ કે ઉપાય ખોજને મેં મદદ મિલેગી। ઇસસે સ્કૂલી શિક્ષા કે સમી સ્તરોં પર ગુણવત્તાપૂર્ણ શિક્ષા કી બુનિયાદ મજબૂત હોગી। ઇસમેં ટેકનોલોજી કા ફાયદા જા સકેગા ઔર દેશ કે તમામ રાજ્યોં, કેંદ્રશાસિત પ્રદેશોં ઔર સમાજ કે સમી વર્ગોં મેં ગુણવત્તાપૂર્ણ શિક્ષા તક લોગોં કી પહુંચ કા દાયરા વિસ્તૃત હોગા।

શિક્ષિત સમાજ કિસી રાષ્ટ્ર કે વિકાસ કી અનિવાર્ય પૂર્વ-શર્ત હૈ। જૈસે-જૈસે નૌજવાન ભારત પ્રગતિ કે માર્ગ પર અગ્રસર હો રહા હૈ, ઇસકી ભાવી પીઢી કે લિએ ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળી શિક્ષા કે માધ્યમ સે એક મજબૂત બુનિયાદ રહ્યે જાને કી જરૂરત હૈ। સરકાર દ્વારા કી ગઈ વિભિન્ન પહલ નિશ્ચય હી ગ્રામીણ ભારત કો અધિકાર-સંપન્ન બનાને કે લિએ સહી દિશા મેં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ હૈ।

(સુરભી જૈન માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય કે સ્કૂલી શિક્ષા ઔર સાક્ષરતા વિમાગ મેં નિદેશક ઔર પૂર્બી પટ્ટનાયક તકનીકી સહયોગ ગુપ્ત મેં વરિષ્ઠ પરામર્શદાતા હોય। લેખ મેં વ્યક્ત વિવાર ઉનકે નિઝી વિવાર હોય।)

ઈ-મેલ : surbhi.jain@nic.in



मार्गदर्शक



卷之三

जो विद्युतीय संरचनाएँ बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी विद्युतीय संरचना को बदलने की क्षमता नहीं है।

卷之三

21 जून, 2018

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)

क्या आपने स्वास्थ्य और तन्तुकर्ती के लिए इस विशेषज्ञापी अंदाजान का हिस्सा बनाने की योजना रखा ही?

આપણી ઉપરિયત્તિ સુનિશ્ચત કરેં!

देवादया और तजदुआसी के लिए

एक पिशव्यापी आंदोलन

- आपां यावा !  
भारतीय !  
संस्कृत के सुनिधन  
संवर्धन के लिए आपां यावा !

अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://yoga/ayush.gov.in> पर जाएं।

卷之三

Seite 1 von 1



卷之三

- प्राचीन विद्यालयों के अधिकारी ने इसका उत्तराधिकारी के रूप में लिखा है। इसका उत्तराधिकारी ने इसका उत्तराधिकारी के रूप में लिखा है। इसका उत्तराधिकारी ने इसका उत्तराधिकारी के रूप में लिखा है। इसका उत्तराधिकारी ने इसका उत्तराधिकारी के रूप में लिखा है।

卷之三

100

100

## भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बढ़ता दायरा

**भा**रतीय चिकित्सा पद्धतियों का अपना प्राचीन इतिहास रहा है। भारत हमेशा से चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दे तो भारत की प्राचीन चिकित्सकीय परंपरा हमेशा से सर्वोपरी रही है। वर्तमान समय में भी देश-दुनिया के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि स्वस्थ रहना है तो भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाना ही होगा। आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं सोवा—रिंगा जैसी चिकित्सा पद्धतियों को संवर्धित करने एवं इनकी पहुंच आमजन तक पहुंचाने के लिए ही भारत सरकार ने अलग से 'आयुष' मंत्रालय बनाया है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की पहल के कारण योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान जून 2015 में मिला। और पूरी दुनिया ने एक स्वर में 21 जून, 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर अपनी सहमति प्रदान की। तब से योग का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योग के लिहाज से 27 सितंबर, 2014 का वह दिन बहुत ही ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के महत्व को दुनिया को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवनशैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।'

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अपने देश के इस प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। इस महीने 21 जून को फिर से पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। भारत सरकार भी पूरे देश में योग को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मंचों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिवस को और व्यापक बनाने के लिए जुट गई हैं। योग से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी सबके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं—

### सामान्य योगाभ्यास से जुड़ी सावधानियाँ

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखकर 'सामान्य योग अभ्यास क्रम (प्रोटोकॉल)' नाम



से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। पुस्तक के पीडीएफ को आप दिए गए लिंक ([https://moayush-files-wordpress-com/2017/05/common&yoga&protocol&hindi\\_0-pdf](https://moayush-files-wordpress-com/2017/05/common&yoga&protocol&hindi_0-pdf)) से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक में योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन बहुत जरूरी है। इन निर्देशों को संक्षेप में जानते हैं।

### अभ्यास के पूर्व

- शौच-शौच का अर्थ है शोधन, यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अपेक्षित क्रिया है। इसके अंतर्गत आसपास के वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि की जाती है।
- योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए।
- योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा-सा शहद मिलाकर लेना चाहिए।
- योगाभ्यास मल एवं मूत्र विसर्जन करने के उपरान्त प्रारंभ करना चाहिए।
- अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योग मैट का प्रयोग करना चाहिए।
- अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती के हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए।
- थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए।
- यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्याएं हों तो ऐसी स्थिति में योग अभ्यास शुरू करने के पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।
- गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

### अभ्यास के समय

- अभ्यास सत्र प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि प्रार्थना अथवा स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करने के लिए शांत वातावरण निर्मित करते हैं।
- योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास-प्रवास की सजगता के साथ धीरे-धीरे प्रारंभ करना चाहिए।
- अभ्यास के समय श्वास-प्रवास की गति नहीं रोकनी चाहिए, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से कहा न जाए।
- श्वास-प्रवास सदैव नासारन्ध्रों से ही लेना चाहिए, जब तक कि आपको अन्य विधि से श्वास-प्रवास लेने के लिए न कहा जाए।
- अभ्यास के बाद स्नान करना चाहिए।
- अभ्यास के 20–30 मिनट बाद ही आहार ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले नहीं।

## राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम



राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 3 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।

वर्ष 2016 में एनएसएपी योजना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना के तहत लाने का जब से रणनीतिक फैसला लिया गया तब से केंद्र सरकार योजना की शत-प्रतिशत जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को लगातार बढ़ा रही है। वित्तवर्ष 2018–19 के लिए एनएसएपी योजना को 9975 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो वर्ष 2014–15 के दौरान 7241 करोड़ रुपये के

आवंटित बजट से 38 प्रतिशत अधिक है। वित्तवर्ष 2017–18 के दौरान एनएसएपी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 8696 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जो वर्ष 2014–15 के दौरान जारी राशि से 23 प्रतिशत अधिक है।

योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और कमियां हटाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एनएसएपी के तहत लाभार्थियों के आंकड़े एनएसएपी–पीपीएस पर डिजिटल फार्म में रखे गए हैं। योजना के तहत 173 लाख लाभार्थियों के आधार नंबर उनकी सहमति से जोड़े गए हैं। सरकार ने आधार आधारित भुगतान व्यवस्था (एबीपीएस) स्वीकार करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2018 करने का फैसला लिया है। इस दिशा में तेजी लाते हुए डिजिटल लेन–देन की सुविधा बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की सहमति से आधार–आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है ताकि किसी भी तरह की संभावित कमियों को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आधार आधारित व्यवस्था से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को विशेष लाभ होगा चूंकि बैंक/डाकघर के जरिए उनके खाते में सीधे भुगतान पहुंचाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की शुरुआत में सिर्फ 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों गुजरात, लक्ष्मीप, बिहार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, झारखण्ड और महाराष्ट्र में ही डिजिटल लेन–देन के जरिए एनएसएपी सहायता पहुंचाई गई और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एक 1.73 करोड़ लेन–देन दर्ज किए गए। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में विशेष कोशिश के तहत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, लक्ष्मीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 10.73 करोड़ लेन–देन हुए। अतः 2016–17 में डीबीटी के जरिए डिजिटल लेन–देन की तुलना में 2017–18 में 520 प्रतिशत लेन–देन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2017–18 में 6791.70 करोड़ रुपये मूल्य के डिजिटल लेन–देन किए गए जो इस साल जारी रकम का लगभग 78 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत मासिक सहायता 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीना करने के अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एमजीएनआरइजीए के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालनाघर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग मजदूरों को अन्य मजदूरों के बराबर ही मजदूरी दी जाती है। दिव्यांग मजदूरों को उनके अनुसार उचित काम के चुनाव जैसी कई और छूट दी गई हैं। वित्तवर्ष 2017–18 में एमजीएनआरइजीए के तहत लगभग 4.7 लाख दिव्यांग मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

डीडीयू–ग्रामीण कौशल योजना के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए लोगों का कौशल बढ़ाने के लक्ष्य का कम से कम 3 प्रतिशत कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस योजना के तहत दिव्यांग योजनाओं के लिए पृथक प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं और नियमित परियोजना से अलग इनकी लागत भी अलग हो सकती है। डीडीयू–ग्रामीण कौशल योजना के तहत देशभर में अभी कुल 243 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डीडीयू–जीकेवाई के तहत 5 विशेष परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें 1500 दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। वित्तवर्ष 2016–17 में 662 उम्मीदवारों की तुलना में डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के तहत वित्तवर्ष 2017–18 (फरवरी 2018 तक) में 912 दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) में भी राज्यों के लिए यह प्रावधान है कि वह कम से कम 3 प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) के तहत दिव्यांगों के लिए 5682 घर मंजूर किए गए जिनमें से 1655 घरों का निर्माण हो चुका है। □

# ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार

-ए. सृजा

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ 30 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्ति की आयु में आ जाते हैं लेकिन मात्र 30 लाख रोजगार ही हर वर्ष सूजित हो रहे हैं। विशाल जनसंख्या जिसका हमेशा से ही लाभ मिलता रहा है, के लिए यह समय की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शक्ति का इस तरह से कौशल विकास किया जाए कि उन्हें डिजिटल भारत, ग्रामीण सड़क संपर्क, स्मार्ट शहरों का विकास, एक्सप्रेस मार्ग, स्वच्छ भारत—ग्रामीण जैसे कार्यों से सूजित होने वाले सकारात्मक उत्पादक रोजगार में लगाया जा सके।

**भा**रत की जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ लेने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस नीति का लक्ष्य वर्तमान में लागू कौशल—तंत्र की सीमा और क्षमता बढ़ाकर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सभी तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना, जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का संवर्धन तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी बहुविध प्रयासों का स्कूली शिक्षा में समावेशन एवं प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें संबंधित मंत्रालयों सहित सभी संबद्ध पक्ष भागीदार होंगे। प्रत्येक पांच साल में इस नीति की समीक्षा करने का प्रावधान रखा गया है।

कौशल विकास पारिस्थितिकी में आए बदलावों और कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में नई राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति की घोषणा की गई। नई नीति का लक्ष्य द्रुत गति, गुणवत्ता और दीर्घकालिकता के साथ कौशल उन्नयन नवाचारों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में चल रही कौशल गतिविधियों के लिए समावेशी तंत्र की व्यवस्था की गई है तथा इसके द्वारा शुरू की गई अनिवार्य उद्यमिता में वैतनिक और स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल मापदंडों के अनिवार्य रूप से मानकीकरण करने पर जोर देना भी इस नीति का लक्ष्य है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लागू किए जा रहे कौशल विकास

कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए वर्ष 2015 में एक समान मानक दिशानिर्देश बनाए गए थे। इन निर्देशों में निवेश मानकों, प्राप्त परिणाम, वित्तीय आबंटन के मानक, आबंटित कोष की प्रवाही व्यवस्था, कार्य की निगरानी व सही संचालन हेतु व्यवस्था और प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का एम्पैनलमेंट (चयन) करने के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 20 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एक समान मानकों पर आधारित 40 से अधिक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहे हैं।

कौशल विकास के लिए अवसंरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) आते हैं। वर्ष 2014 में इन सबका विलय कर एक नया विभाग 'कौशल विकास एवं उद्यमिता' गठित किया गया जिसे वर्ष 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। राज्यों के स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे नोडल एजेंसी के रूप में राज्य कौशल विकास मिशनों की स्थापना करें।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) ने राष्ट्रीय कौशल



યોગ્યતા અવસરંચના (એનએસક્યૂએફ) કો એકીકૃત કરને ઔર ઉસે કાર્યાન્વિત કરને, એક એસા રાષ્ટ્રીય યોગ્યતાએં પંજિકા (એનક્યૂઆર) વિકસિત કરના જો સમી સ્વીકૃત યોગ્યતાઓં કા સંગ્રહ હૈ, રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તા આશ્વસ્ત અવસરંચના (એનક્યૂએફ) વિકસિત કરના, કૌશલ વિકાસ પર એક એસા રાષ્ટ્રીય ડાટા બેસ બનાકર સંચાલિત કરના જિસમેં એક ગતિશીલ શ્રમિક બાજાર સૂચના પ્રણાલી ભી તૈયાર કી ગઈ હો।

રાષ્ટ્રીય કૌશલ વિકાસ એવં ઉદ્યમિતા નીતિ 2015 મેં 24 પ્રમુખ સેક્ટરોં મેં 10,973 કરોડ રૂપયે કી બઢી સંસાધન આવશ્યકતા કી પહોંચ કી ગઈ હૈ ઔર વર્ષ 2022 તક શ્રમશક્તિ કે રૂપ મેં લગભગ 10,462 કરોડ વ્યક્તિ નાને શ્રમિકોં કે રૂપ મેં ઉપલબ્ધ હોંગે। વર્ષ 2022 તક લગભગ 29,825 કી વર્તમાન શ્રમશક્તિ કો પૂર્વ અધ્યયન માન્યતા (આરપીએલ), ફિર સે કૌશલ પ્રાપ્ત કરને ઔર ઉસકે ઉન્નયન કી આવશ્યકતા પડેગી ઔર 10,462 કરોડ નાને શ્રમિકોં કો ફિર સે કૌશલ પ્રશિક્ષણ લેના આવશ્યક હોગા।

### ગ્રામીણ યુવાઓં કે લિએ કૌશલ વિકાસ યોજના

#### પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના (પીએમકેવીવાઈ)

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના એક ફ્લેગશિપ યોજના હૈ જિસે વર્ષ 2015 મેં યુવાઓં કો ઉદ્યોગોં કી આવશ્યકતાઓં કે અનુરૂપ પ્રશિક્ષણ લેકર અપને લિએ બેહતર રોજગાર પ્રાપ્ત કરને કે યોગ્ય બનાને કે લિએ શુરૂ કિયા ગયા થા। યહ યોજના રોજગાર પાને કે ઇચ્છુક યુવાઓં કો લઘુકાળીન પ્રશિક્ષણ દેને એવં વર્તમાન શ્રમશક્તિ કો માન્યતા પ્રાપ્ત એવં સંબંધ પ્રશિક્ષણ સહયોગી/પ્રશિક્ષણ કેંદ્રોં કે માધ્યમ સે ઉનકી પૂર્વ અધ્યયન માન્યતા (આરપીએલ) કો માન્ય કરતે હુએ ઉન્હેં રોજગાર દિલવાને કે લિએ શુરૂ કી ગઈ થી। પ્રશિક્ષણ મેં ગુણવત્તા ઔર માનકીકરણ કો સુનિશ્ચિત કરને કે લિએ અનેક કદમ ઉઠાએ ગએ હૈને, જો ઇસ પ્રકાર હૈને: કેંદ્રીય પ્રત્યાયન કે લિએ એક ઠહરાવ વાલા વેબ-આધારિત સમાધાન, દેશભર મેં પ્રશિક્ષણ કેંદ્રોં કો એકરૂપ (બેંચમાર્ક) કરને કે લિએ એક્ઝ્યુફિલેશન સ્ટેંડર્ડ્સ ગ્રેડિંગ મેટ્રિક્સ, રોજગાર હેતુ પ્લેસમેન્ટ, બ્રાંડિંગ, અવસરંચના જૈસે માનકોં કે નિગરાની સંબંધી, નિરંતર કાર્ય નિષ્પાદન કે લિએ પ્રશિક્ષણ કેંદ્રોં કો મૂલ્યાંકન કરના, પ્રશિક્ષુઓં, પ્રશિક્ષકોં ઔર મૂલ્યાંકનકર્તાઓં કે લિએ આધાર આધારિત બાયોમેટ્રિક ઉપસ્થિતિ કો અનિવાર્ય કરના, પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત યુવાઓં કો પ્લેસમેન્ટ દિલવાને કે લિએ પ્રશિક્ષણ કેંદ્રોં કો પ્રોત્સાહિત કરના, આદિ।

દિસંબર 2017 તક લગભગ 40.5 લાખ પ્રત્યાશિયોં કો પ્રશિક્ષણ દિયા ગયા હૈ જિસમે 27.56 લાખ કો લઘુકાળીન પ્રશિક્ષણ દિયા ગયા તથા 7.76 લાખ કો આરપીએલ મિલા વ 05 લાખ પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર રહે હૈને। ઇસ યોજના મેં પ્લેસમેન્ટ પર વિશેષ ધ્યાન દિયા ગયા હૈ। ઇસમેં ઉદ્યમિતા ભી શામિલ હૈ। યોજના મેં મહિલાઓં કો કુશલ બનાને પર ભી બલ દિયા ગયા હૈ જિસકે લિએ ઉન્હેં પ્રશિક્ષણ અવધિ મેં રૂપયે 1000 / 1500 પ્રતિ માહ કા યાત્રા ભત્તા ઔર પ્લેસમેન્ટ

કીએ જાને કે બાદ અગલે દો/તીન મહીને તક રૂપયે 1450 પ્રતિ માહ કી દર સે પ્લેસમેન્ટ પશ્ચાત સમર્થન દિયા જાએગા જો ઉનકે મૂલ નિવાસ સ્થાન અથવા મૂલ નિવાસ સે દૂર રહને પર નિર્ભર કરેગા।

પીએમકેવીવાઈ કે અંતર્ગત જનજાતીય જનસંખ્યા કે લિએ નિર્મલિખિત પરિયોજનાએ ચલ રહી હૈને :

**બ્રૂ પરિયોજના :** ઇસ પરિયોજના કા ઉદેશ્ય મિજોરમ કી બ્રૂ જનજાતિ કા કૌશલ ઉન્નયન કરના હૈ જિસે વિસ્થાપન હોને કે કારણ ઉત્તરી ત્રિપુરા મેં સ્થિત આંતરિક વિસ્થાપિત વ્યક્તિ કેંદ્રોં (આઈડીપી) મેં રહના પડ રહા હૈ। (ii) કતકરી મૂલ આદિવાસી જનજાતિ : ઇસ પરિયોજના કા લક્ષ્ય મહારાષ્ટ્ર કી કતકરી જનજાતિ કે 1020 યુવાઓં કો કૌશલ ઉન્નયન કરના હૈ। (iii) ઓડિશા મેં કૌશલ વિકાસ : પરિયોજના કા લક્ષ્ય ઓડિશા કે 62 સ્થાનીય આદિવાસી સમુદાયોં કે 12,000 પ્રત્યાશિયોં કો કૌશલ ઉન્નયન કરના હૈ। ઇન 62 મેં સે 13 સમુદાય મૂલ આદિવાસીયોં કે રૂપ મેં વર્ગીકૃત હૈને। (iv) પરિયોજના યુવા (વાઈયુવીએ) દિલ્લી પુલિસ ઔર એનએસડીસી દ્વારા સંયુક્ત રૂપ સે ચલાઈ જા રહી હૈ જિસકે અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્લી કે 3000 વંચિત યુવાઓં સે સંપર્ક સાધ કર ઉન્હેં ઉનકી ક્ષમતા કે અનુસાર કૌશલ વિકાસ પ્રશિક્ષણ દિયા ગયા ઔર રોજગાર દિલવાને મેં મદદ કી ગઈ। એસા ઇન યુવાઓં કો અપરાધ કી દુનિયા મેં જાને સે રોકને ઔર કાનૂન વ્યવસ્થા બનાએ રખને કે કાર્ય મેં પુલિસ કી સહાયતા કરને કે લિએ પ્રેરિત કરને કે લિએ કિયા ગયા હૈ। વર્તમાન મેં 715 યુવાઓં કો પંજીકરણ કિયા ગયા હૈ જિસમેં સે 390 કો પ્રશિક્ષણ દિયા ગયા ઔર ઉસમેં સે 240 યુવકોં કો વિભિન્ન કંપનીયોં મેં નૌકરી દિલવાઈ ગઈ હૈને।

#### દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના (ડીડીયુ-જીકેવાઈ)

ડીડીયુ-જીકેવાઈ નિર્ધારન ગ્રામીણ યુવાઓં કો ઉન્હેં રોજગારપરક પ્રશિક્ષણ દેકર શ્રમશક્તિ બાજાર કે અનુરૂપ તૈયાર કરને કી પ્લેસમેન્ટ સે જુડી કૌશલ વિકાસ કી સશક્તીકરણ યોજના હૈ। અક્ટૂબર 2017 તક ડીડીયુ-જીકેવાઈ કે અંતર્ગત 674 પરિયોજનાઓં મેં 566 સે અધિક પ્રશિક્ષણ કેંદ્ર થે જો 28 રાજ્યોં મેં 39 સેકટરોં મેં 329 પ્રકાર કે રોજગારોં કે લિએ 310 પરિયોજના ક્રિયાન્વયન એઝેસિયોં કે સહયોગ સે સંચાલિત કીએ જા રહે થે। વર્ષ 2017-18 કે લિએ નિર્ધારિત 02 લાખ પ્રત્યાશિયોં કો કૌશલ પ્રશિક્ષણ દેને કે લક્ષ્ય કે અંતર્ગત 83,745 સે અધિક ઉમ્મીદવારોં કો પ્રશિક્ષણ દિયા જા ચુકા હૈ। ઇનમેં સે ભી 46,654 ઉમ્મીદવારોં કો નૌકરી દિલવાઈ જા ચુકી હૈ। મંત્રાલય ને 12 ના ચેંપિયન નિયોક્તાઓં કી પહોંચ કર લી હૈ ઔર ઉનકે સાથ ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાલે પ્રશિક્ષણ એવં પ્લેસમેન્ટ કરવાને કે લિએ સમજોતી જ્ઞાપન પર હસ્તાક્ષર કીએ ગએ હૈને।

ડીડીયુ-કેવીવાઈ યોજના કે અંતર્ગત યુવાઓં કો 'કૌશલ પંજી' અથવા 'સ્ક્લિલ રઝિસ્ટર' એપ કે માધ્યમ સે સ્વયં કે કૌશલ પ્રશિક્ષણ કે લિએ પંજીકૃત કરવાને કા વિકલ્પ દિયા જાતા હૈ। ઇસસે ગ્રામીણ

যুবা প্রশিক্ষণ সহযোগিয়ে এবং বৈঁকোঁ সে জুড়ে রহ সকতে হৈ ওৱ উন্হেঁ  
অপনে আসপাস কে ভৰ্তী শিখিৰোঁ, প্ৰশিক্ষণ কেঁদ্ৰোঁ, রোজগার মেলোঁ এবং  
প্ৰশিক্ষণ কে নে বৈচোঁ কে প্ৰাৰংভ হোনে কী সূচনা মিলতী রহতী হৈ।

### গ্ৰামীণ স্বৰোজগার প্ৰশিক্ষণ সংস্থান (আৱেসইটী)

গ্ৰামীণ যুবাওঁ কী পাৰিবাৰিক আয় মেঁ বিবিধতা লানে কে  
উদ্দেশ্য সে গ্ৰামীণ বিকাস মন্ত্ৰালয় নে অপনী যোজনা গ্ৰামীণ  
স্বৰোজগার প্ৰশিক্ষণ সংস্থান (আৱেসইটী) চলাই হৈ। আৱেসইটী  
এক ত্ৰিমার্গ যোজনা হৈ জিসে গ্ৰামীণ বিকাস মন্ত্ৰালয়, রাজ্য  
সকারেঁ ওৱ বৈঁক মিল কৰ চলাতে হৈ। ইস যোজনা মেঁ 31 সহযোগী  
বৈঁকোঁ নে পূৰে দেশ মেঁ 586 আৱেসইটী কী স্থাপনা কী হৈ। যে  
কৃষি, প্ৰসংস্কৰণ (প্ৰক্ৰিয়া), উত্পাদ ওৱ সামান্য উদ্যমিতা বিকাস  
কাৰ্যক্ৰমোঁ (ইডীপী) পাঠ্যক্ৰমোঁ কী প্ৰত্যাশিয়োঁ কী প্ৰশিক্ষণ দে রহে  
হৈ জিসে কি বে স্বয়ং কাৰোজগার / বৈতনিক কাৰ্য কৰনে কে  
লিএ সক্ষম হো সকেঁ। বৰ্ষ 2017–18 কে লিএ কৌশল বিকাস হেতু  
নিৰ্ধাৰিত 3.97 লাখ প্ৰত্যাশিয়োঁ কে লক্ষ্য কী তুলনা মেঁ অভী তক  
2.35 লাখ প্ৰত্যাশিয়োঁ কী প্ৰশিক্ষণ দিয়া গয়া হৈ ওৱ ইসমেঁ সে ভী  
1.55 লাখ প্ৰত্যাশিয়োঁ কী রোজগার উপলব্ধ কৰা কে স্থাপিত কীয়া  
জা চুকা হৈ। স্টার্টআপ গ্ৰামীণ উদ্যমিতা কাৰ্যক্ৰম (এসবীইপী) কে  
অন্তৰ্গত 31 দিসেংবৰ, 2017 তক 25,409 ব্যক্তিয়োঁ কে লিএ রোজগার  
কে অবসৰ সৃজিত কী গए হৈ।

### প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হৰ ঘৰ যোজনা

গ্ৰামীণ যুবাওঁ কে সশক্তিকৰণ ওৱ উত্থান কে উদ্দেশ্য সে  
কৌশল বিকাস এবং উদ্যমিতা মন্ত্ৰালয় নে ঊৰ্জা (বিজলী) মন্ত্ৰালয় কে  
সহযোগ সে প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হৰ ঘৰ যোজনা (সৌভাগ্য) কে  
অন্তৰ্গত ছহ রাজ্যোঁ— অসম, বিহাৰ, মধ্য প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা  
ওৱ উত্তৰ প্ৰদেশ মেঁ গ্ৰামীণ যুবাওঁ কে লিএ ব্যাবসায়িক প্ৰশিক্ষণ  
প্ৰাৰংভ কীয়া। যুবাওঁ কী দো প্ৰকাৰ কে কাৰ্যোঁ— লাইন মেন বিতৰণ  
(ডিস্ট্ৰিব্যুশন) (বহু—আয়ামী কৌশল) এবং তকনীকী সহায়ক কা  
প্ৰশিক্ষণ দিয়া জাতা হৈ। ইস কৌশল বিকাস কে উদ্দেশ্য যোজনা  
কে সবসে বড়ে লক্ষ্য পূৰে দেশ মেঁ হৰ ঘৰ মেঁ বিজলী পহুচানে কে  
লিএ প্ৰশিক্ষিত কামগাৰোঁ কী আবশ্যকতা কী পূৰা কৰনা হৈ। ইন  
প্ৰমুখ ছহ রাজ্যোঁ মেঁ কুল 47,000 যুবাওঁ ওৱ পূৰে দেশ মেঁ 55,000  
যুবাওঁ কী ইসকে লিএ প্ৰশিক্ষণ দিয়া জাএগা। ইস যোজনা কে  
অন্তৰ্গত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ সংস্থানোঁ কী অবসৰণাওঁ ওৱ রাজ্যোঁ  
কে বিজলী বিতৰণ সংস্থানোঁ মেঁ উপলব্ধ কৌশল বিকাস সুবিধাওঁ  
কে প্ৰযোগ কীয়া জাএগা।

### সহভাগিতা কৌশল নথাচাৰ

**জল সংসাধন মন্ত্ৰালয় কে সাথ সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ  
হস্তাক্ষৰ :** নমামি গংগে প্ৰিয়োজনা কে লিএ কৌশল প্ৰশিক্ষিত  
শ্ৰমশক্তি কা বিকাস কৰনে কে উদ্দেশ্য সে কেঁদ্ৰীয় কৌশল বিকাস  
এবং উদ্যমিতা মন্ত্ৰালয় ওৱ কেঁদ্ৰীয় জল সংসাধন, নদী বিকাস ওৱ  
গংগা পুনৰ্জীৱন মন্ত্ৰালয় কে বীচ এক সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ  
কী গए।

### সীমা সুৰক্ষা বল ওৱ অসম রাইফল্স কে সাথ সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ :

সীমা সুৰক্ষা বল ওৱ রাষ্ট্ৰীয় কৌশল বিকাস কোষ (এন  
এসডীএফ), এন এসডীসী কে বীচ এক সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ  
কী গए হৈ জিসকা উদ্দেশ্য সীমা সুৰক্ষা বল কে সেৱাৰত, সেৱানিবৃত্ত  
হোনে বালে এবং সেৱানিবৃত্ত হো চুকে কৰ্মচাৰিয়োঁ ওৱ উনকে পৰিবাৰ  
জনোঁ কী লাভাদ্যক রোজগার মুহূৰ্যা কৰানে কে লিএ সীমা সুৰক্ষা  
বল দ্বাৰা সংচালিত বহুআয়ামী কৌশল বিকাস কেঁদ্ৰোঁ মেঁ এসে সমী  
সংভাৱিত লাভাৰ্থিয়োঁ কী এনএসক্যুএফ আধাৰিত কৌশল প্ৰশিক্ষণ সে  
সংৰক্ষ কৰনা সুনিশ্চিত কীয়া জাতা হৈ। অসম রাইফল্স কে সাথ  
ভী এসে হৈ এক সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ কী গए হৈ।

### ऊৰ্জা গংগা গৈস পাইপ লাইন প্ৰিয়োজনা কে লিএ সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ :

ऊৰ্জা গংগা গৈস পাইপ লাইন প্ৰিয়োজনা কে লিএ কুশল  
শ্ৰমশক্তি কী উপলব্ধতা কে উদ্দেশ্য সে এনএসডীসী, জীএআইএল,  
কৌশল বিকাস সংস্থান (এসডীআই), ভুবনেশ্বৰ ওৱ লেবৰনেট কে  
বীচ এক চতুৰ্পঞ্চিয সমজীৱীতা জ্ঞাপন পৰ হস্তাক্ষৰ কী গए হৈ। যহ  
সমজীৱীতা জ্ঞাপন ঊৰ্জা গংগা গৈস পাইপ লাইন প্ৰিয়োজনা কে পূৰা  
হোনে মেঁ উচ্চ শ্ৰেণী মেঁ গুণবত্তা ওৱ উত্পাদকতা কে সুনিশ্চিত  
কৰনে কে লিএ ত্ৰুটিৱাহিত কৌশল বিকাস গতিবিধিয়োঁ কা সংৰ্ধন  
ওৱ উন্নয়ন কৰনে কে সাথ হৈ বড়ি সংখ্যা মেঁ যুবাওঁ কী রোজগার  
মুহূৰ্যা কৰাএগা।

### প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেঁদ্ৰ

কৌশল প্ৰশিক্ষণ দেনে কে লিএ উদ্যোগোঁ কী নবীনতম  
আবশ্যকতাওঁ কী পূৰ্ণ হেতু উনকে অনুৰূপ হৈ আধুনিকতম প্ৰশিক্ষণ  
উপকৰণ অত্যন্ত আবশ্যক হৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেঁদ্ৰ এসে হৈ  
আদৰ্শ কৌশল বিকাস কেঁদ্ৰ হৈ জিনমেঁ ঔদ্যোগিক মানকোঁ কে অনুৰূপ  
কৌশল বিকাস অবসৰণ কে নিৰ্মাণ, প্ৰশিক্ষণ ওৱ প্লেসমেণ্ট পৰ  
পূৰা ধ্যান দিয়া জাতা হৈ। দিসেংবৰ 2017 তক দেশ মেঁ 27 রাজ্যোঁ কে  
484 জিলোঁ হেতু 527 প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেঁদ্ৰ অনুমোদিত কী গए হৈ।  
ইনমেঁ সে 328 প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেঁদ্ৰ কী স্থাপনা কী জা চুকি হৈ।

### ভাৰতীয় কৌশল সংস্থান (আইআইএস)

আইটীআইআই সিংগাপুৰ কী তৰ্জ পৰ দেশ কে পাংচ ক্ষেত্ৰোঁ  
মেঁ আধুনিকতম উত্কৃষ্টতা কেঁদ্ৰ স্থাপিত কী জা রহে হৈ। মুঁবৰ্ই  
মেঁ টাটা সমূহ কে সহযোগ সে দেশ কা পহলা আইআইএস নিৰ্মিত  
কীয়া জা রহা হৈ। যহ আইআইএস ঊৰ্জা সক্ষম নিৰ্মাণ, ঔদ্যোগিক  
ইলেকট্ৰোনিক্স এবং আঁটোমেশন জৈসে উচ্চস্তৰীয় পাঠ্যক্ৰমোঁ মেঁ  
‘হেঁড়স—আঁন’ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰেগা।

### শুল্ক—আধাৰিত প্ৰশিক্ষণ

এনএসডীসী দ্বাৰা সংচালিত কৌশল বিকাস কে শুল্ক  
আধাৰিত মুড়ল কে অন্তৰ্গত 74 লাখ সে অধিক যুবাওঁ কী  
প্ৰশিক্ষণ দিয়া গয়া হৈ। বৰ্ষ 2017 মেঁ রাজমিৰ্তী, বিক্ৰী তকনীশিয়ন,  
ৱিফিজৱেশন মেকেনিক, বীমা প্ৰশিক্ষণ, ঵োশিং মশীনোঁ কে লিএ ফীল্ড

तकनीशियन जैसे मांग—आधारित पेशों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत 07 लाख प्रत्याशियों में से 50 प्रतिशत से अधिक को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है।

### तक्षशिला (प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पोर्टल)

प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का यह राष्ट्रीय पोर्टल एनएसडीसी का एक नवाचार है। यह पोर्टल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक समर्पित मंच है और यह भारत की कौशल पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं के संग्रहालय की तरह कार्य करेगा। इसकी एक विशिष्टता ऐसे योग्य एवं कुशल पेशेवर प्रशिक्षकों के बारे में सूचना का मिलना है जिसके माध्यम से सभी राज्यों और क्षेत्रों में उपलब्ध कर्मचारी चयन आयोगों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के बारे में आवश्यकतानुसार जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराई जाएगी।

### माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता से कौशल को शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातक उपाधि दे रहा है। दायित्व स्थानांतरण द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिक्षा को 10वीं और 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अप्रैटिसिप घटक को औपचारिक शिक्षा का भाग बनाकर डिग्री अप्रैटिसिप को वैकल्पिक शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।

### 'तकनीकी शिक्षा संस्थान'

### नक्सल—प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) में कौशल विकास

देश के 10 राज्यों के 47 नक्सल—प्रभावित जिलों में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया है ताकि वहां रहने वाले युवा उचित कौशल प्रशिक्षण लेकर अपने लिए बेहतर जीवनयापन करने का जरिया अपना सकें।

### उड़ान (यूडीएएन)

उड़ान जम्मू—कश्मीर राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही अनूठी पहल है। इस योजना का उद्देश्य स्नातक/स्नातकोत्तर एवं त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देकर उन्हें निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दिलवाना है। यह योजना निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट्स के सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है। लगभग 84 कॉर्पोरेट्स ने प्रशिक्षण देने के लिए उड़ान महाचयन अभियानों में अपनी सहभागिता की है।

### हिमायत

जम्मू—कश्मीर के बेरोजगार युवाओं विशेषकर बीच में ही स्कूली/कॉलेज शिक्षा छोड़ देने वाले युवकों के लिए बनाया गया प्रशिक्षण—सह—प्लेसमेंट कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत युवाओं को उन कौशल कार्यक्रमों के लिए तीन महीने की लघु अवधि वाले प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें मिले रोजगार में उनके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य से एक साल तक नजर रखी जाती है।

### राष्ट्रीय कैरियर सेवा

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना में एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है जिसमें रोजगार के इच्छुक युवाओं और नियोक्ताओं को एक ऐसा राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वांछित कार्य/नौकरी की आवश्यकता पूर्ति त्वरित, सक्षम एवं सकारात्मक तरीके से हो सके और जिसमें विभिन्न प्रकार के कैरियर्स की पूरी जानकारी उपलब्ध रहे। 31 मार्च, 2018 तक इस पोर्टल पर 14.87 लाख नियोक्ताओं एवं 4.24 करोड़ रोजगार चाहने वालों ने अपना पंजीकरण करवाया था और इस पर 8.61 लाख रोजगार संबंधी नियुक्तियां भेजी गई थी। उपलब्ध रोजगारों तक युवाओं की पहुंच को बढ़ाने एवं रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के लिए प्रमुख जॉब पोर्टलों, प्लेसमेंट संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

### प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (पीएम—वाईयूवीए)

इस योजना के अंतर्गत पांच वर्षों में देशभर में उच्च शिक्षा के चयनित संस्थानों (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रमुख संस्थानों), स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं उद्यमिता विकास केंद्रों (ईडीसीएस्ज) में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, छात्रों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञों, संरक्षकों, परिचालकों, कोष एवं वाणिज्यिक सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था मिलेगी। अब तक 239 उच्च शिक्षा संस्थानों ने उद्यमिता शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने आप को एम्पैनल कराया है तथा 200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। पीएमके—वीवाई पाठ्यक्रमों के जीवन कौशल मॉड्यूल के अंतर्गत संपूर्ण रूप से परिष्कृत उद्यमिता ओरिएंटेशन मॉड्यूल को समाहित किया गया है जिससे पीएमके—वीवाई पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक प्रत्याशी को उद्यमिता में दिशानिर्देश मिल सकेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी रोजगार सक्षम कौशलों के एक भाग के रूप में उद्यमिता मॉड्यूल को समाहित किया गया है।

### ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ईजीएस) का उद्देश्य ही प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को,



जो स्वयं को अकुशल रोजगार के लिए प्रस्तावित करे, साल में 100 दिनों के सुनिश्चित भुगतान योग्य रोजगार देकर उपयोगी दीर्घकालिक परिसंपत्ति के निर्माण के जरिए सामाजिक समावेशन करना है। हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशन के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत पीएम एवाई-जी लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप से घरों में शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण, कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों के लिए अवसंरचना निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान 4.63 करोड़ परिवारों को 163 लाख कार्यों के लिए रोजगार दिया गया और इस प्रक्रिया में 182 करोड़ मानव श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक प्रमुख ऋण—संबद्ध अनुदान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत हस्तकला वाले कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को सहायता देकर गैर-कृषि क्षेत्र में लघु-उद्योगों की स्थापना कर स्वरोजगार का सृजन करना है।

अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंडअप योजना के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों द्वारा उनकी प्रत्येक शाखा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक व्यक्ति और कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये का ऋण विपणन, सेवाओं अथवा वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में हरितक्षेत्र उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा (एमयूडीआरए) योजना में गैर-कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने अथवा व्यावसायिक कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 लाख रुपये तक का समावेशी ऋण दिया जाता है। इसे तीन श्रेणियों— शिशु (50,000 रुपये तक),

किशोर (50,000 रुपये – 05 लाख रुपये तक) और तरुण (05–10 लाख रुपये तक) में विभाजित किया गया है। 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों के माध्यम से अब तक 4.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। 76 प्रतिशत ऋण लाभार्थी महिलाएं और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आने वाले ऐसे नई भर्ती वाले कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है, के लिए नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले 8.33 प्रतिशत अंशदान का भुगतान तीन वर्षों तक सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही वस्त्र निर्माण उद्योग, चमड़ा एवं जूते-चप्पल उत्पादन जैसे श्रमोन्मुख क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए जाने वाले 12 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा तीन साल के लिए दिया जाएगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ 30 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्ति की आयु में आ जाते हैं लेकिन मात्र 30 लाख रोजगार ही हर वर्ष सृजित हो रहे हैं। विशाल जनसंख्या जिसका हमेशा से ही लाभ मिलता रहा है, के लिए यह समय की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शक्ति का इस तरह से कौशल विकास किया जाए कि उन्हें डिजिटल भारत, ग्रामीण सड़क संपर्क, स्मार्ट शहरों का विकास, एक्सप्रेस मार्ग, स्वच्छ भारत— ग्रामीण जैसे कार्यों से सृजित होने वाले सकारात्मक उत्पादक रोजगार में लगाया जा सके।

(लेखिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं।)

ई-मेल : srija.a@gov.in



# रीड IAS

---

**An initiative of अभ्य कुमार**

उथल पुथल के काल में हिन्दी माध्यम...

प्रिय विद्यार्थियों,

2011 के उपरांत प्रारम्भिक परीक्षा में और 2013 के उपरांत मुख्य परीक्षा में, जब से नया पाठ्यक्रम आया है हिन्दी माध्यम के परिणाम अत्यंत चिंताजनक रहे हैं। इसके लिये आप निम्नांकित सारणी का विश्लेषण करें।

प्रारम्भिक परीक्षा में सकाल अध्यार्थियों की संख्या			
वर्ष	प्रारम्भिक परीक्षा दिनों	सकाल संख्या	प्रतीक्षा संख्या
2011	63rd Report / Page 96 (परीक्षा 1)	1788	9316
2012	64th Report / Page 105 (परीक्षा 1)	1878	9881
2013	65th Report / Page 79 (परीक्षा 1)	1498	12287
2014	66th Report / Page 78 (परीक्षा 1)	2185	13733
2015	66th Report / Page 83 (परीक्षा 1)	2633	11799

क्या कभी आपने सोचा है कि हिन्दी मात्राम के लगातार प्रियते परिणाम के पीछे क्या कारण हैं?

- प्राण पर में अनुकूल की स्थिति इसका प्रमुख कारण नहीं रहा है लालिक दो-दो वर्षों तक भेड़ जाल में परामरणगत घट्टति से रोधारी करने के प्रवाह इसका प्रमुख कारण है।
  - 20 से 25 कृषिसेतु के माध्यम से और शिर्फ लम्बात्यक अध्ययन समझौते के माध्यम से अध्ययन भी इसका एक कारण है।
  - परीक्षा की मांग और अपेक्षाओं के अनुकूल कला कार्यक्रम का मन्त्रालय न होना भी इसमें जापित है।
  - देश सीरीज के जाग पर अधिक से अधिक संख्या में गैर-परीक्षार्थी ने प्रश्नों का अन्वयन दृढ़ी कही ये जापित हैं।
  - सामाजिक अध्ययन के विभिन्न परामरणों की सही प्रारूपिकता के सबै नीचारों न करना भी माध्यमिक है।

**नोट-** यहाँ परीक्षा के निश्चल नोट्स हैं हमारे कार्यालय में आ कर पंजीकरण कराएँ, **धन्यवाद**

**Reed IAS Add:- B-7/8 Shop No.4 Mezzanine Floor  
Bhandari House Commercial Complex  
Dr Mukherjee Nagar Delhi-9**

सामान्य अध्ययन

## निःशुल्क परिचर्चा तिथि व समय

3 जून साप्तर्ष 7 बजे 4 जून प्रातः 11:30 बजे 12 जून शोधवत्र 3 बजे

अभय कुमार के साथ निःशुल्क परिवहनी एवं मूल्य जीका  
के लिए ईर के निःशुल्क बोर्ड विभाग कल्पना में अप्रकल्प स्थगित है।

परिचर्चा सत्र में पढ़ाएं और जानें

- हमारी टोप
  - हमारे आवासन के सीके
  - हमारे नियमित बोहस
  - हमारी देश परिवार
  - उनमें से अधिकांश मात्र
  - अधिकांश विवाह चरित्रात्मा मात्र
  - युवा शिव अवस्थन
  - हमारी मासिक परिवार
  - "ईएस डॉट
  - हमारी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के बड़े गुण

जब प्रारंभिक परीक्षा में ही कानूनता वा परिवर्तन दूसरों का है तो मुख्य परीक्षा और अलग परिवर्तन के नाम प्राप्त वा होता अपरिहार्य है।

ऐसे ही वीर में रीढ़ आँखेण्ठा लिपिस देखा या साथन सेहता लिलहै उमे यासे  
लिपिसिंहों के रीढ़ एवं लिपिस के सब से ग्रन्थित है।

- ५. अपना जीव जीते ही सोचो कि, अब कौन से व्यापारिक वर्गों में दिलचस्पी नहीं हो रही है और आगामी ही बुल ट्रॉफी का जीत का बाबों कुछ जीवों के बाबत 20-25 लाख रुपये का हो।
  - ६. इनके व्यापार में उत्तम IAS प्रश्नों का विषयी ज्ञान की।
  - ७. अपने Youtube Channel Reed IAS को subscribe कर लें ताकि वहाँ से विवरणों का अभिज्ञान हो।
  - ८. इसकी Website- [www.reedias.com](http://www.reedias.com) पर नियम उपलब्ध होने वाली को लिखें ताकि जान लाये।
  - ९. ग्री IAS को E-Magazine की Website- [iasemag.com](http://iasemag.com)
  - १०. अपनी विद्या के दौरान जब जुड़ जायेंगे तो व्यापारिक, उनके व्यापार व्यवस्था का विस्तृत ज्ञान करें।
  - ११. अपनी जीव जीते ही एवं अपना जीवों में इसी फ्रिग्यूल व्यवस्था की बहुत जीव जीतें।

9870309939

# स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास

—आशुतोष कुमार सिंह

आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, इंद्रधनुष अभियान, नल—जल योजना, उज्ज्वला योजना सहित तमाम ऐसी योजनाएं बीते चार वर्षों में लागू हुई हैं। इसका सकारात्मक असर देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव की तरह दिख रहा है। प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान की है।

**भा**रत की आत्मा गांवों में बसती हैं। यही कारण है कि आजादी से लेकर अभी तक भारत के गांवों को समृद्ध एवं सेहतमंद बनाने के लिए सरकारें नई—नई योजनाएं बनाती रही हैं। सेहतमंद भारत के लिए यह आवश्यक भी है कि गांवों की सेहत में सुधार किए जाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि सरकार की योजनाओं की कसौटी अंतिम जन होता है। गर अंतिम जन तक किसी भी लोक—कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह योजना धरातल पर सफल नहीं हो पाई है।

भारत के राजनीतिक इतिहास में 2014 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में एक नई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस सरकार ने आते ही स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता से अपने एजेंडे में शामिल किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वास्थ्य का विषय एक जन—आंदोलन बन गया।

2 अक्टूबर, 2014 को भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' अभियान की शुरुआत की। इसका असर यह हुआ कि पूरे देश में बड़े—बड़े सेलिब्रेटियों ने भी अपने हाथ में झाड़ू उठा लिया। गली—मुहल्लों में साफ—सफाई के लिए युवा स्वयंसेवक सामने आने लगे। बीते चार वर्षों में स्वच्छता आग्रहियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। गांवों में भी अब कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर आता है तो छोटे—छोटे बच्चे इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा जन—आंदोलन बन चुका है और इससे भारत के गांवों को बहुत लाभ हुआ है।

इतना ही नहीं इस सरकार ने घर—घर शौचालय अभियान को भी जन—आंदोलन बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि शौच के लिए बाहर जाने वालों की संख्या 30 फीसदी से भी कम रह गई है। इस अभियान ने एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लिया है। जिस घर में शौचालय नहीं हैं, उस घर में लड़कियां शादी तक नहीं

करना चाहती हैं। मीडिया में ऐसे कई मामले देखने—पढ़ने को मिले हैं जिसमें लड़की ने शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ससुराल पक्ष में शौचालय नहीं बना है। इस संदर्भ को सिनेमा जगत ने भी बड़े पर्दे पर बखूबी उकेरा है। 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' फिल्म का उद्देश्य लोगों में शौचालय के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इतना ही नहीं, सभी घरों में शौचालय हो, इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद भी की है। सबसे ज्यादा बीमारी अस्वच्छ जल के कारण लोगों को होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जल—नल योजना चला रही है। इसके तहत प्रत्येक घर को नल से जोड़ा जा रहा है, ताकि पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके।

## स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी

किसी भी देश का 'स्वास्थ्य बजट' वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होता है। यही कारण है कि भारत सरकार भी अपने स्वास्थ्य बजट को उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। रोगों के भार को कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है। इस नजर से इस बार का स्वास्थ्य बजट भारत की तर्सीर बदलने वाला कहा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा



बजट सेहत के मद में सरकार ने जारी किया है। इस बार 56,226 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रत्येक बजट में सरकार ने स्वास्थ्य के मद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बजट आवंटन पर विशेष ध्यान दिया है। इस सरकार का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा कि लोग बीमार ही न पड़े। यही कारण है कि इस सरकार ने स्वास्थ्य के मसले को जन-आंदोलन बनाया; लोगों को भागीदार बनाया।

### वित्तमंत्री के बजटीय भाषण में स्वास्थ्य की तस्वीर

1 फरवरी, 2018 को वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने वित्तीय भाषण में 'स्वास्थ्य' विषय पर विशेष ध्यान दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि, "हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपने को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके। सरकार सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांग जनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु 2018–19 में 9975 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 'सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं 'आयुष्मान भारत' में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं। टी.बी. पीडित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषाहार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाएं एवं नैसर्जिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को इलाज के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं, सरकार निर्धन एवं कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक विंतित है। अब हम 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ करेंगे। इसके तहत द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति पांच लाख

रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। 'आयुष्मान भारत' की यह दो पहल वर्ष 2022 तक एक नए भारत की निर्माण करेंगी।'

30 अप्रैल, 2018 से आयुष्मान भारत के अंतर्गत वेल इक्विवॉड आरोग्य केंद्र खुलने शुरू हो चुके हैं। जिस दिन डेढ़ लाख आरोग्य केंद्र खुल जाएंगे, निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य जरूरतों को बहुत हद तक पूर्ण किया जा सकेगा।

### स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति

भारत में कुल जीडीपी में महज 1.4 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में 170 देशों में से भारत 112वें स्थान पर है। चीन में कुल जीडीपी का 3 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है। वैश्विक औसत स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का 5.4 फीसदी है। अन्य देशों का स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च तालिका-1 में देखें। यहां यह समझना भी जरूरी है कि लोग बीमार न पड़े, इसके लिए भी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे मद में खर्च कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ जल, पोषण अभियान जैसे मदों में भी सरकार खर्च कर रही हैं, जिसका संबंध स्वास्थ्य से ही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी के आधार पर स्वास्थ्य के मद में किए जा रहे खर्च प्रतिशत के आंकड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह सटीक नहीं माने जाने चाहिए।

### स्वास्थ्य की दिशा में सरकारी कदम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 31 पृष्ठों के अपने मसौदे में भारत को स्वस्थ रखने की अपनी नीतियों को प्रस्तुत किया है। पृष्ठ 9 के अनु. 3.2 में बचावात्मक स्वास्थ्य नीति का उल्लेख किया गया है।

#### तालिका-1 देश में स्वास्थ्य पर खर्च

देश	जीडीपी (प्रतिशत में)
भारत	1.4
अमेरिका	18.1
जर्मनी	11.3
फ्रांस	11.0
जापान	10.9
इटली	8.9
कनाडा	10.6
ब्रिटेन	9.7
पाकिस्तान	0.7
नेपाल	2.3
श्रीलंका	2.0

इसी तरह नई स्वास्थ्य नीति के अनु.4.2 में किशोर स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कही गई है।

## આયુષ્માન ભારત : એક સાર્થક પહેલ

વિગત 22 માર્ચ, 2018 કો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેંદ્ર મોદી કી અધ્યક્ષતા મેં કેંદ્રીય મંત્રિમંડળ કેબિનેટ ને કેંદ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય સંરક્ષણ મિશન કો મંજૂરી દી। ઇસ મિશન મેં કેંદ્રીય સરકાર કા હિસ્સા આયુષ્માન ભારત કે તહત ઉપલબ્ધ હોગા, જો સ્વાસ્થ્ય એવં પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય કે અંતર્ગત એક કાર્યક્રમ હૈ। ઇસ બાવત કેંદ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી શ્રી જેપી નંડા કા કહના હૈ કી એનએચ્પીએમ સાર્વભૌમિક સ્વાસ્થ્ય કવરેજ કી દિશા મેં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ હૈ। યહ સ્વાસ્થ્ય ખર્ચ કી ભયાવહતા સે 50 કરોડ લોગોં (10 કરોડ પરિવારોં) કો સુરક્ષિત કરેગા। ઇસસે દેશ કી 40 પ્રતિશત જનસંખ્યા કો લાભ મિલેગા। યહ યોજના અસ્પતાલ મેં ભર્તી હોને કે દ્વિતીયક ઔર તૃતીયક—સ્તર કો કવર કરેગી। ગૌરતલબ હૈ કી પાંચ લાખ રૂપયે કી કવરેજ વાલી ઇસ યોજના મેં પરિવાર કે આકાર ઔર ઉત્ત્ર કી કોઈ સીમા નહીં રહેગી। ઇલાજ કે લિએ અસ્પતાલ મેં દાખિલ હોને કે વક્ત યહ યોજના ગરીબ ઔર કમજોર પરિવારોં કે મદદ કરેગી। સામાજિક—આર્થિક—જાતિ જનગણના કે આંકડોં કે આધાર પર સમાજ કી ગરીબ ઔર અસહાય જનસંખ્યા કો આયુષ્માન ભારત—એનએચ્પીએમ યોજના સે વિતીય મદદ મિલેગી। કેંદ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય બીમા યોજના' (આરએસબીવાઈ) તથા વરિષ્ઠ નાગરિક સ્વાસ્થ્ય બીમા યોજના (એસસીએચાઈએસ) એનએચ્પીએમ મેં શામિલ કર દી જાએંગી। સરકાર દ્વારા વિત્તપોષિત યહ વિશ્વ કી સબસે બડી સ્વાસ્થ્ય બીમા યોજના હોણી। લોગ સરકારી ઔર અધિસૂચિત નિઝી અસ્પતાલોં મેં ઇલાજ કી સુવિધા પ્રાપ્ત કર સકેંગે। સભી સરકારી અસ્પતાલોં કો ઇસ યોજના મેં શામિલ કિયા ગયા હૈ। નિઝી અસ્પતાલોં કી આંનલાઇન સૂચી બનાઈ જાએંગી। નિશ્ચિત રૂપ સે સરકાર કા યહ પ્રયાસ સાર્વભૌમિક સ્વાસ્થ્ય કી દિશા મેં એક સાર્થક કદમ હૈ।

ઇસ દિશા મેં સરકાર વિદ્યાલયી પાઠ્યક્રમ મેં સ્વાસ્થ્ય ઔર સ્વચ્છતા કો શામિલ કરને કા વિચાર કર રહી હૈ। વહીં કિશોરોં કી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓં સે નિપટને કે લિએ પ્રયત્નશીલ હૈ। કિશોરોં કો સમુચ્ચિત પોષણ મિલ સકે, ઉનકી માનસિક સમસ્યાઓં કા નિદાન હો સકે; ઇસ દિશા મેં સરકાર ચિંતનશીલ હૈ। અનુ.4.3 મેં કૃપોષણ એવં અન્ય પોષક કમિયોં કો દૂર કરને કી બાત કહી ગઈ હૈ। ઇસમેં યહ માના ગયા હૈ કી પોષણ કે અભાવ કે કારણ બીમારિયોં કા બોઝ બઢતા જા રહા હૈ। ખાસતૌર સે એનીમિયા એક પ્રમુખ બીમારી કે રૂપ મેં સામને આઈ હૈ। ઇસસે નિજાત પાને કે લિએ સરકાર સ્કૂલી—સ્તર પર આયરન, કૈલિશ્યમ, વિટામિન એ કી ગોલિયાં વિતરિત કર રહી હૈ। વહીં અનુ. 4.7 મેં માનસિક સ્વાસ્થ્ય એવં અનુ.5 મેં મહિલાઓં કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓં સે નિજાત પાને કે ઉપાયોં પર સરકાર ને અપની સ્થિતિ કો સ્પષ્ટ કિયા હૈ।

ગૌરતલબ હૈ કી વર્ષ 2017 મેં 15 વર્ષોં કે અંતરાલ કે બાદ નર્હ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ જારી કી ગઈ। 15 માર્ચ, 2017 કો મંત્રિમંડળ ને રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ (એનએચ્પી) 2017 કો અપની સ્વીકૃતિ દી। રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નીતિ 2017 મેં સરકાર ને યહ સંકલ્પ લિયા

હૈ કી 2025 તક સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્ય વ્યય કો જીડીપી કા 2.5 પ્રતિશત તક બઢાયા જાએગા। સાથ હી યહ ભી કહા ગયા હૈ કી ભારત સરકાર સ્વાસ્થ્ય ઔર આરોગ્ય કેંદ્રોં કે માધ્યમ સે વ્યાપક પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સેવા કા બડા પૈકેજ ઉપલબ્ધ કરાને કે પ્રતિ કૃત સંકલ્પ હૈ। ઇસી સંકલ્પ કા અસર ઇસ બાર કે બજટ મેં ભી દેખને કો મિલા હૈ।

### 'બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ'

લડકોં કે મુકાબલે લડકિયોં કી લિંગાનુપાત મેં કમી સે પૂરા દેશ ચિંતિત હૈ। લડકિયોં કો ગર્ભ મેં હી માર દેના એક સામાજિક બીમારી કે રૂપ મેં સામને આયા હૈ। ખૂન હત્યા ન સિર્ફ એક બેટી કી હત્યા હૈ બલ્ક એક માં કે લિએ માનસિક એવં શારીરિક પ્રતાડના કા કારણ ભી હૈ। ઇસ બીમારી કો દૂર કરને કે લિએ સરકાર ને 'બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ' અભિયાન કી શરૂઆત કી હૈ। પ્રધાનમંત્રી દ્વારા શરૂ કિયા ગયા બેટી બચાઓં, બેટી પઢાઓં કાર્યક્રમ લડકિયોં કા માન બઢાને ઔર ઉનકે અધિકારોં કે લિએ અનુકૂલ વાતાવરણ તૈયાર કરને કે લિએ પ્રતિબદ્ધ હૈ। 161 જિલોં મેં શરૂ કિએ ગએ ઇસ કાર્યક્રમ કે પરિણામ અત્યધિક ઉત્સાહવર્ધક હૈનું। વર્ષ 2015–16 ઔર 2016–17 કી અવધિ મેં 104 જિલોં મેં જન્મ કે સમય લિંગાનુપાત (એસસારબી) મેં સુધાર દેખા ગયા, 119 જિલોં મેં એનસી પંજીકરણ કી તુલના મેં પહલી તિમાહી મેં પંજીકરણ મેં પ્રગતિ દર્જ હુઈ ઔર 146 જિલોં મેં અસ્પતાલોં મેં પ્રસવ કરાને કી સ્થિતિ મેં સુધાર હુआ। ઇન્ના હી નર્હીં સમાજ ભી બેટિયોં કે સ્વાસ્થ્ય કે મુદ્દે પર જ્યાદા સક્રિય હુઆ હૈ। બિહાર સમસ્તીપુર મેં એક ચિકિત્સક હૈનું ડૉ. એન. કે આનંદ। વે 'સ્વસ્થ બાલિકા સ્વસ્થ સમાજ' કે ધ્યેય કો લેકર આગે ચલ રહે હૈનું ઔર અભી તક 7000 સે અધિક બાલિકાઓં કા નિઃશુલ્ક ઇલાજ કર ચુકે હૈનું। ઇસી તરહ પુણે મેં ડૉ. ગણેશ રાખ હૈનું, જો બેટિયોં કે જન્મ પર પૈસા નર્હીં લેતે બલ્ક ઉનકે જન્મ કો સેલીબ્રેટ કરતે હૈનું। ઉપરોક્ત બદલાવ વિગત ચાર વર્ષોં મેં જ્યાદા દેખને કો મિલે હૈનું।

### મિશન સઘન ઇંદ્રધનુષ

અંગ્રેજી મેં એક કહાવત હૈ 'પ્રિવેંશન ઇઝ બેટર દૈન ક્યોર' યાની કિસી ભી બીમારી કો રોકને કા સબસે ઉત્તમ ઉપાય બચાવ હૈ। ઇસ બાત કો સરકાર ભી માનતી હૈ। ઔર ઇસ દિશા મેં ટીકાકરણ અભિયાન ચલા રહી હૈ। દેશ કે નૌનિહાલોં કો બીમારી સે બચાને કે લિએ સરકાર ટીકાકરણ પર બહુત જોર દે રહી હૈ। હાલ હી મેં દેશ કે પ્રધાનમંત્રી ને કહા કી યદિ ટીકે સે કિસી રોગ કા ઇલાજ સંભવ હૈ તો કિસી ભી બચ્ચે કો ટીકે કા અભાવ નર્હીં હોના ચાહિએ। ગુજરાત કે વડનગર મેં સઘન મિશન ઇંદ્રધનુષ કા શુભારંભ કરતે હુએ પ્રધાનમંત્રી ને કહા કી ઇસ કાર્યક્રમ કે જરિએ ભારત સરકાર ને દો વર્ષ કી આયુ કે પ્રત્યેક બચ્ચે ઔર ઉન ગર્ભવતી માતાઓં તક પહુંચને કા લક્ષ્ય રખા હૈ જો ટીકાકરણ કાર્યક્રમ કે અંતર્ગત યહ સુવિધા નર્હીં પા સકી હૈનું।

યહાં ધ્યાન દેને વાલી બાત યહ હૈ કી વિશેષ અભિયાન કે તહત ટીકાકરણ પહુંચ મેં સુધાર કે લિએ ચુને હુએ જિલોં ઔર રાજ્યોં મેં

दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण से 90 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 90 प्रतिशत क्षेत्रों को शामिल किया जाना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस कार्यक्रम को 11 अन्य मंत्रालय और विभाग भी अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा कार्य एवं अन्य मंत्रालयों ने सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है।

### प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना

लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके, इसके लिए सरकार ने तीव्रगति से 3350 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुलवाए हैं। इस वर्ष के अंत तक इसकी संख्या 4000 तक होने की संभावना है। इन केंद्रों पर 100 रुपये बाजार मूल्य की दवा 10–15 रुपये में उपलब्ध है। देश की गरीब जनता के लिए ये केंद्र बहुत उपयोगी हैं। गौरतलब है कि महंगी दवाइयों के कारण देश की 3 फीसदी जनता गरीबी—रेखा से ऊपर नहीं पा रही थी। ऐसे में जनऔषधि केंद्रों की बढ़ती उपलब्धता एक क्रांतिकारी बदलाव है।

### वर्तमान में स्वास्थ्य चुनौतियां

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण—4 के अनुसार भारत में 6.8 फीसदी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन किया है। 4.4 फीसदी शहरी क्षेत्र एवं 8.1 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने तंबाकू का सेवन किया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे—3 के परिणाम से बेहतर है, तब 10.8 फीसदी महिलाएं तंबाकू का सेवन करती थीं। इस सर्वे के अनुसार भारत का 44.5 फीसदी पुरुष वर्ग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। शहरी क्षेत्र में 38.9 फीसदी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 48 फीसद पुरुष तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। पिछले सर्वे में भारत के 57 फीसदी पुरुष तंबाकू सेवन करते थे। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि देश की 1.5 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, जिसमें 0.7 फीसदी शहरी एवं 1.5 फीसदी ग्रामीण महिलाएं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे—3 के अनुसार 2.2 फीसदी महिला आबादी शराब का सेवन करती थी। वहीं 29.2 फीसदी पुरुष आबादी शराब का सेवन करती है, शहर में रहने वाले 28.7 एवं गांव में रहने वाले 29.2 फीसदी पुरुष शराब का सेवन करते हैं। युवाओं में शराब पीने की लत से तकरीबन 60 प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। इसका सीधा संबंध आपके हिंसायुक्त व्यवहार से भी है। भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे—4 (आईएफएचएस—4) की रिपोर्ट में पोषण संबंधित आंकड़ों को दिया गया है। इस सर्वे के अनुसार 22.9 फीसदी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बीएमआई सामान्य से कम है। शहरी महिलाओं में यह स्थिति 15.5 फीसदी है तो ग्रामीण महिलाओं में यह 26.7 फीसदी है। आईएफएचएस—3 के सर्वे में देश की 35.5 फीसदी महिलाओं का बीएमआई सामान्य से कम था। इन आंकड़ों को देखकर यह तो कहा जा सकता है कि सुधार हो, रहा है लेकिन यह सुधार

और तीव्र गति से हो इसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है।

### ध्यान देने योग्य अन्य बिंदु

- जन्म के समय लिंगानुपात**— जोकि प्रति एक हजार बच्चों पर बच्चियों की संख्या से जाना जाता है, सुधार कर 914 से 919 हो गया है। सुधार की यही गति रही तो लिंगानुपात पूरा ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
- शिशु मृत्यु दर कम होकर 57 से 41 पर आ गई। इस मामले में विश्व का औसत 30.5 और विश्व का सर्वोत्तम 2 है। वैश्विक मानदंड पर आने में अभी बहुत समय लगेगा।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम होकर 74 से 50 पर आ गई। इस मामले में विश्व का औसत 41 और विश्व का सर्वोत्तम 2.1 है।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों में, प्रत्येक दो में से एक खून की कमी का शिकार है। प्रत्येक तीन में से एक अपेक्षित वजन से कम और कुपोषित है और प्रत्येक पांच में से एक दुर्बल है।
- बच्चों के पोषण और उनकी सेहत की परवाह नहीं की है, इसलिए हमारे मानव संसाधन की गुणवत्ता शोचनीय है। आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर तकनीकी प्रगति और सामाजिक सौहार्द तक, सब कुछ मानव पूँजी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टरों पर हमारे मानव संसाधन को पल्लवित—पुष्टि करने का उत्तरदायित्व है, खासकर हमारे बच्चों के संदर्भ में, पर डॉक्टर बहुत कम हैं। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है (2016 का आंकड़ा) और 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हम हर साल सिर्फ 55 हजार स्नातक चिकित्सक और 25 हजार परास्नातक चिकित्सक तैयार करते हैं। हर चिकित्सक पर कम से कम दो चिकित्सकों के काम का भार है।

### निष्कर्ष

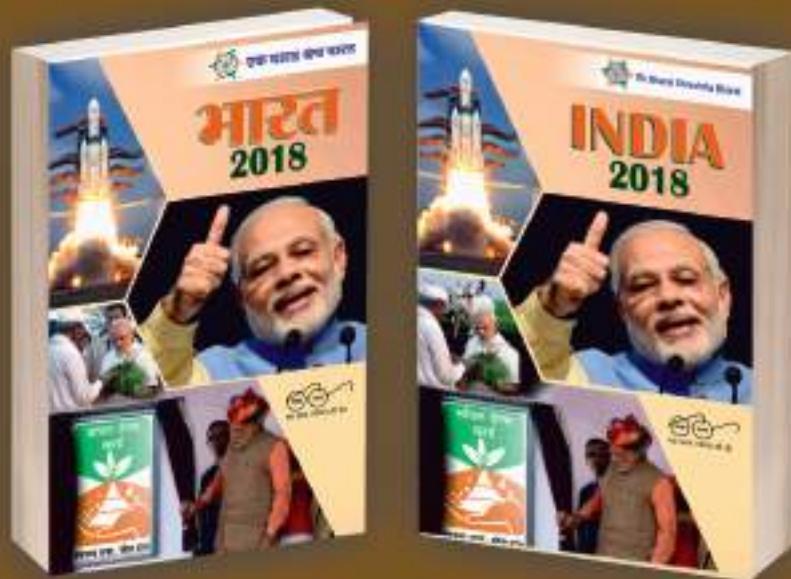
आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, इंद्रधनुष अभियान, नल—जल योजना, उज्ज्वला योजना सहित तमाम ऐसी योजनाएं बीते चार वर्षों में लागू हुई हैं। इसका सकारात्मक असर देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव की तरह दिख रहा है। प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान की है। बावजूद इसके भारत जैसे बड़े भूभाग एवं जनसंख्या वाले देश के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को सेहतमंद बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को इस सरकार ने बीते चार वर्षों में सफलतापूर्वक स्वीकार किया भी है। अगले कुछ वर्षों में सरकारी—स्तर पर उठाए गए कदमों का प्रभाव दिखाई देगा।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हैं।)

ई—मेल : [forhealthyindia@gmail.com](mailto:forhealthyindia@gmail.com)

# भारत 2018

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की  
जानकारियों से परिपूर्ण पुस्तक



amazon.in और play.google.com पर  
'ई बुक' के रूप में भी उपलब्ध



प्रकाशन विभाग  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,  
भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ऑनलाइन आर्डर के लिए  
लॉग इन करें – [www.bharatkosh.gov.in](http://www.bharatkosh.gov.in)  
या [www.publicationsdivision.nic.in](http://www.publicationsdivision.nic.in)  
अथवा संपर्क करें –  
फोन – 011 24367453, 24367260, 24365609

प्रकाशन विभाग की अन्यापुनिक पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन में पाठी



@ DPO\_India



[www.facebook.com/publicationsdivision](http://www.facebook.com/publicationsdivision)  
[www.facebook.com/yojana.journal](http://www.facebook.com/yojana.journal)

# महिलाओं की उन्नति के खुलते नए द्वार

—सिद्धार्थ झा

राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनें, शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस कर सकें और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकें।

**म**हिलाओं के प्रति आदर और गौरवपूर्ण व्यवहार हमारे देश के चिंतन का मूलभूत सिद्धांत रहा है और महिलाओं ने समाज के आधे हिस्से के रूप में आदिकाल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में अपनी प्रमाणिकताएं, प्रासंगिकताएं, क्षमता और सामर्थ्य का भरपूर परिचय दिया है। एक महिला सशक्त होती है, तो वह दो परिवारों को सशक्त बनाती है। प्राचीनकाल में भी महिलाएं शक्ति का उदाहरण थीं। वे ज्ञान का भंडार थीं। किंतु, एक समय ऐसा आया कि महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। किंतु, ये समय भी अधिक समय तक नहीं टिका। एक बार फिर से महिलाएं घर की चौखट से बाहर आने लगी हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं।

दरअसल महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज का विकास अधूरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से ही नए भारत की नीव पड़ेगी। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो आधी आबादी में ये

उम्मीद जागी थी कि अब उनके भी नए सफर की शुरुआत यहीं से होगी। आपको याद होगा कि वर्ष 2012 में थामसन रायटर्स फाउंडेशन के द्वारा 19 उभरते हुए देशों में किए गए सर्वे में भारत सबसे निचले पायदान पर था और उसकी वजह बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारण गिनाए गए। ये वो दौर था जब यूपीए की अध्यक्ष, राष्ट्रपति और लोकसभाध्यक्ष इन सभी पदों की शोभा महिलाएं ही बढ़ा रही थीं। एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपने शुरुआती कामों से ही ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर वो कितनी गंभीर है। सरकार महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं।

सरकार महिलाओं के लिए पिछले कुछ समय में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। संभवतः किसी एक आलेख में इसे समेट पाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा



## 100 और वन स्टॉप सेंटर

आने वाले वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर को 50,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक धनराशि प्राथमिक चिकित्सा के लिए दी जाएगी। 21 अप्रैल, 2018 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 से अब तक 182 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) का निर्माण किया है। ये केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.3 लाख से ज्यादा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

ओएससी का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता की सेवा उपलब्ध कराना है जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, मानसिक –सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, पांच दिनों का अस्थाई निवास आदि। पीड़ित महिला एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण मानक प्रारूप में वर्तमान में उपलब्ध भवनों तथा नए भवनों में किया गया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ का वन स्टॉप सेंटर एक शानदार भवन में कार्यरत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

मंत्रालय की महिला हेल्पलाइन—181 को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अप्रैल, 2015 से शुरू किया गया है और अब यह 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है। प्रत्येक ओएससी को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इन हेल्पलाइनों के जरिए अब तक 16.5 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके द्वारा सरकार की ये कोशिश है कि गिरते लिंगानुपात के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकना इसका मुख्य मकसद है। जिसके लिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है। इस पहल को लोगों ने हाथों—हाथ लिया क्योंकि ये सरकारी पहल से कहीं अधिक सामाजिक पहल थी। हरियाणा से ही इस योजना का शुभारंभ करने का संदेश साफ था क्योंकि वहां समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस योजना का परिणाम हरियाणा में काफी हद तक दिखाई देने भी लगा है, जहां हर 1000 पुरुषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है। हाल तक यहां के आंकड़े काफी चिंताजनक थे।

इसके कुछ ही महीने बाद केंद्र सरकार बलात्कार, यौन हिंसा जैसे घृणित अपराध से महिलाओं और बच्चियों की रक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम लेकर आई जिसे पहली अप्रैल 2015 से निर्भया फंड से लागू किया गया। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग—अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेरेक्टर, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। इस हेल्पलाइन का भी सार्वभौमिकरण किया गया यानी सभी राज्यों में ये हेल्पलाइन नंबर मान्य है। इतना ही नहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए ई—प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया

गया है। इस ई—प्लेटफॉर्म की सुविधा के माध्यम से केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी ऐसे मामलों में ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भी कार्यान्वयन में लाया गया है। हाल में ही बच्चियों के साथ बढ़ती हुई दरिंदगी पर चिंतित सरकार पासको एकट में भारी बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए फांसी का अध्यादेश लेकर आई है जिसका सभी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वागत किया है। इतना ही नहीं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए फारस्ट ट्रेक अदालतों का भी गठन किया गया है जिसको एक निश्चित समय—सीमा में फैसला करना होता है। इतना ही नहीं कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है इसका प्रमाण है सरकार की ये दूरगामी सोच जिसके तहत मोबाइल फोन और कैब में पैनिक बटन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं और बहुत हद तक ये सुविधा उपयोग में लाई जाने लगी है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है। ऐसे में महिलाओं के साथ हुई किसी अप्रिय घटना में पुलिस की भूमिका कैसे संवेदनशील हो सकती है इसके लिए जरूरी है महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में बढ़े। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत पुलिस में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन उपायों से देश भर की महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। ये सभी योजनाएं एक—दूसरे से जुड़ी हैं। सभी मंत्रालयों के बीच

बेहतर समन्वय करने की बेहतरीन कोशिश की गई है वरना अब तक पीड़िता को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। एक डेस्क से दूसरे डेस्क और न्याय की संभावनाएं भी धूमिल हो जाती थीं। लेकिन निश्चिंत तौर पर उपरोक्त सुधारों से महिलाएं कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस कर रही होंगी।

महिलाओं को सशक्त करना है तो जरूरी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आई जिसने आधी आबादी की नींव को मजबूत किया है। अगर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें तो हम पाएंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं सिर्फ निजी क्षेत्र में इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि मां बनना एवं बच्चे का पालन-पोषण उनके कैरियर की राह में बहुत बड़ी बाधा साबित होता है। सरकार ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में एक निश्चित दूरी पर क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि महिलाएं अपने छोटे बच्चों को वहां छोड़ सकें। महिलाओं को मातृत्व अवकाश के समय घर से भी काम करने की छूट दी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए नया मातृत्व लाभ संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत **कामकाजी महिलाओं के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश** की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।

**मातृत्व लाभ कार्यक्रम 1** जनवरी, 2017 से लागू है। इसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में 6000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। साथ ही काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध

करवाने के उद्देश्य से वर्किंग वुमेन होस्टल भी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर उनके बच्चों के देखभाल की सुविधा और जरुरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं और अन्य प्रयास महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये सब बातें महिला सशक्तिकरण के संबंध में इस सरकार की प्रतिबद्धता को ही दिखाती है। इसी तरह उनको उद्यमी बनाने की दिशा में मुद्रा योजना मील का पथर साबित हुई है। इस योजना का लाभ किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना संगठित क्षेत्र में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाई है जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से बिना गारंटर के मिल जाता है। इस दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं जिससे कि महिलाएं भी कारोबार के क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकें। इन योजनाओं को तुमन स्पेशल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें महिला वैभव लक्ष्मी, महिला शक्ति, मुद्रा स्कीम जैसी तमाम स्कीमों पर सस्ती दरों पर ऋण मिल रहा है। मुद्रा लोन के तहत 70 फीसदी लोन महिला उद्यमियों को दिए गए।

महिला ई-हाट एक अनोखा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, साथ ही सरकार के इस कदम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनने का अवसर भी मिल रहा है। इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल



- સ્ટેંડઅપ ઇંડિયા કે તહત 8000 કરોડ રૂપયે સે અધિક કાન્દ્રણ મહિલાઓં કો દિયા ગયા।
- ઉજ્જવલા યોજના કે તહત 2 કરોડ સે અધિક મહિલાઓં કો ગૈસ સિલેંડર વિતરિત કિએ જા ચુકે હોયાં।
- જન-ધન ખાતોં સે કરીબ 16.5 કરોડ મહિલાએ લાભાન્વિત હો રહી હોયાં।
- રાષ્ટ્રીય આજીવિકા મિશન કે તહત મહિલા સ્વયંસહાયતા સમૂહોં કો દી જાને વાલી રાશિ મેં પિછલે ચાર વર્ષો મેં 175 પ્રતિશત કી બઢોતરી।
- મુદ્રા યોજના સે 9 કરોડ મહિલાઓં કો લાભ।
- સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કે તહત દેશભર મેં બેટિયોં કે નામ કરીબ સવા કરોડ બેંક ખાતે ખુલે જિનમેં 19000 કરોડ રૂપયે સે અધિક રકમ જમા રૂઝી।
- પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન કે તહત એક કરોડ સે અધિક પ્રેનેંસી ચૈકઅપ પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ વંદના યોજના કે અંતર્ગત 11 લાખ સે અધિક મહિલાઓં કો 271.66 કરોડ રૂપયે કા ભુગતાન કિયા ગયા।
- મિશન ઇંદ્રધનુષ કે તહત 80 લાખ સે જ્યાદા ગર્ભવતી મહિલાઓં કા ટીકાકરણ।

વિકાસ મંત્રાલય ને એક મંચ તૈયાર કિયા હૈ જિસકે માધ્યમ સે મહિલાએ અપને હુનર કે જરિએ કમાઈ ભી કર સકતી હોયાં। મહિલાઓં કો સશક્ત બનાને કી દિશા મેં ઈ-હાટ તીન ચરણોં કી શૃંખળા કા પહલા ચરણ માત્ર હૈ। દૂસરે ચરણ મેં વ્યાપાર ઔર વાણિજ્ય કે સાથ એક બડા મંચ પ્રદાન કરને કે લિએ ઈ-કોર્મર્સ પોર્ટલ કે સાથ જુડ્ઝના હોગા ઔર આખિરકાર, યહ એક મહિલા ઉદ્યમિયોં કે પરિષદ કે રૂપ મેં પરિણત હો રહા હૈ, જો ઇસ ઉદ્યમ કો વ્યાપક બનાને ઔર સંસ્થાગત બનાને મેં મદદ કરેગા।

### બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ યોજના

ઇસ યોજના કે ઉત્સાહજનક પરિણામ સામને આએ હોયાં। લિંગાનુપાત બેહતર હુઅ હૈ ઔર લડ્કિયોં કી સ્કૂલી શિક્ષા બીચ મેં છોડને કે મામલોં મેં ભી કમી આઈ હૈ। 'બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ' યોજના વર્તમાન મેં યહ યોજના દેશ મેં 161 જિલોં મેં લાગ્યું હૈ ઔર ઇસમેં 244 નાને જિલોં કો જોડા ગયા હૈ। ઇસ યોજના કા વિસ્તાર ભારત કે સભી 640 જિલોં મેં કિયા જાના હૈ। શેષ 235 જિલોં કો મીડિયા વ જાગરૂકતા અભિયાન દ્વારા જોડા જાએગા।

**સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના** સરકાર દ્વારા લડકી કી સુરક્ષા ઔર ભવિષ્ય કે સાથ-સાથ સમાજ મેં સકારાત્મક માનસિકતા બનાને કે પ્રયાસ કે રૂપ મેં હી શુરૂ કિયા ગયા થા। ઇસ યોજના કે અંતર્ગત જન્મ સે લેકર 10 સાલ તક કી કન્યાઓં કે ખાતે ડાકઘર મેં ખોલે જાતે હોયાં। ઇન ખાતોં મેં જમારાશિ પર 8.1 પ્રતિશત કી દર સે વાર્ષિક બ્યાજ દેને કા પ્રાવધાન હૈ। બેટિયોં કી શિક્ષા ઔર સમૃદ્ધિ કી યહ યોજના અભિભાવકોં કે લિએ વરદાન સિદ્ધ હો રહી હૈ। ઇસકે

અલાવા, અલ્પસંખ્યક મહિલાઓં મેં નેતૃત્વ ક્ષમતા વિકસિત કરને કે લિએ 'નई રોશની યોજના' બનાઈ ગઈ હૈ તાકિ વે ઉદ્યમશીલતા કે ક્ષેત્ર મેં આગે બઢ સકેં।

હાલ હી મેં, સરકાર ને એક નई કલ્યાણ યોજના 'મહિલા શક્તિ કેંદ્ર યોજના' કો મંજૂરી દી હૈ। યહ યોજના ગ્રામીણ મહિલાઓં કે લિએ શુરૂ કી ગઈ હૈ। ઇસ યોજના કો શુરૂ કરને કે બાદ કેંદ્ર સરકાર કા મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમુદાય કી ભાગીદારી કે માધ્યમ સે ગ્રામીણ મહિલાઓં કો સશક્ત બનાના હૈ।

અસુરક્ષિત ઔર અસ્વારથ્યકર વાતાવરણ મેં અપને પરિવારોં કે લિએ ખાના પકાને વાલી મહિલાઓં કી તો જિંદગી હી બદલ ગઈ હૈ। લકડી સે નિકલને વાલે ધૂએ ઔર સ્ટોવ કે ધૂએ કે ખતરનાક પ્રભાવ સે મહિલાઓં કો મુક્ત કરને કે લિએ ઉજ્જવલા યોજના શુરૂ કી ગઈ। ગરીબી-રેખા કે નીચે (બીપીએલ) કે પરિવારોં કો બેહતર જીવન કે લિએ સરકાર ને ઉન્હેં બેહતર ઔર સ્વરથ વાતાવરણ પ્રદાન કિયા। પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના કે તહત ગરીબી-રેખા સે નીચે જીવનયાપન કરને વાલી 2 કરોડ સે અધિક મહિલાઓં કો ગૈસ સિલેંડર વિતરિત કિએ ગએ। સરકાર ને પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના કે અંતર્ગત અગલે તીન સાલોં મેં ગરીબી રેખા સે નીચે રહને વાલી 5 કરોડ સે અધિક મહિલાઓં કો નાને એલપીજી કનેક્શન ઉપલબ્ધ કરાને કે લિએ 8000 કરોડ રૂપયે કી મંજૂરી દી હૈ। ઇસકે અલાવા, પૂર્વવર્તી સરકારોં દ્વારા ચલાઈ જા રહી અનેક યોજનાએ આજ ભી જારી હોયાં જે જિસસે મહિલા સશક્તિકરણ કે ઉદ્દેશ્ય મેં લગાતાર સફલતા મિલ રહી હૈ।

અબ સબકી નજરેં સંસદ કી તરફ હૈ જહાં સંસદ મેં મહિલાઓં કો 33 ફીસદી હિસ્સેદારી મિલે। રાજ્યસભા મેં યે બિલ પહલે હી પાસ હો ચુકા હૈ લેકિન લોકસભા મેં અભી ઇસકી રાહ આસાન નહીં હોયાં। અગર યે બિલ પાસ હો જાતા હૈ તો લોકસભા કી 543 મેં સે 179 સીટોં મહિલાઓં કે લિએ આરક્ષિત હોંગી જવકિ રાજ્ય વિધાનસભાઓં કી 4120 સીટોં મેં સે 1360 મહિલાઓં કે લિએ આરક્ષિત હોંગી યાની મહિલાઓં કો સાથ લેકર દેશ કે વિકાસ કા સ્વચ્છ સાકાર હોને કા રાસ્તા ખુલેગા। ઐસા માના જા રહા હૈ કી તીન તલાક કો ગૈર-કાનૂની ઘોષિત કરને સંબંધી બિલ લોકસભા મેં પાસ કરને કે બાદ કેંદ્ર મહિલા આરક્ષણ બિલ કો લેકર સક્રિય હો ગઈ હૈ।

હર રોજ આસાની સે હમારી જિંદગીયોં મેં કરી અહુમ ભૂમિકાએં નિભાને વાલી મહિલાએ નિર્વિબાદ રૂપ સે કિસી ભી સમાજ કી રીઢ હોતી હોયાં। રાષ્ટ્ર કે વિકાસ ઔર પ્રગતિ કે લિએ ભી મહિલાઓં કી ભાગીદારી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હૈ। ઇસી ભાગીદારી કો સુનિશ્ચિત ઔર પ્રોત્સાહિત કરને કે લિએ સરકાર લગાતાર ઐસે કદમ ઉઠા રહી હૈ તાકિ મહિલાએ સ્વાવલંબી બનેં, શિક્ષિત હોયાં, સુરક્ષિત મહસૂસ કર સકેં ઔર દેશ કી ઉન્તિ મેં કંધે સે કંધા મિલાકર સહયોગ કર સકેં।

(લેખક લોકસભા ટીવી મેં પત્રકાર હૈની)  
ઈ-મેલ : sidharthjha@gmail.com

CIVIL SERVICES



Announcing

# GS Foundation Batch for Civil Services Examination 2019

New Batches Starting

16 June  
(Weekend)

18 June  
(Weekdays)

Every 2nd\* selected candidate of UPSC  
CSE'17 is from ETEN IAS

\* Results from the House of KSC

## Program Features



Module-based Study  
& Daily Class Notes



Team of Highly  
Experienced Faculty



SIS  
(Online Support)



Video Archive  
Facility



Comprehensive  
Test Series

To know more, please visit your nearest center

Agra: 9760008389 Allahabad: 9455375599 Aluva: 8281711688 Amritsar: 8054373683 Bangalore: 9964322070  
 Bangalore: 9035651622 Bhiwani: 7015382123 Bilaspur: 9907969099 Chennai: 9962981646 Dibrugarh: 7086708270  
 Ghaziabad: 120-4380998 Hissar: 9355551212 Hyderabad: 8008006172 Hyderabad: 9908414441 Imphal: 7005607850  
 Jamshedpur: 9102993829 Kolkata: 9836990904 Lucknow: 7311116911 Ludhiana: 9968299001 Meerut: 8433180973  
 Moradabad: 9927035451 Mysore: 9945600866 Nagpur: 8806663499 Patna: 9430600818 Raipur: 8871034889  
 Ranchi: 651-2331645 Shimoga: 9743927548 Sonipat: 9871683147 Srinagar: 9797702660 Tirupati: 9698123456  
 Trivandrum: 8138885136 Udaipur: 9828086768 Varanasi: 9718493693 Vijaywada: 9912740699



[www.etenias.com](http://www.etenias.com)

Career  
Launcher

# लोगों की मानसिकता बदलता स्वच्छ भारत अभियान

—संजय श्रीवास्तव

स्वच्छ भारत अभियान चार साल पहले शुरू हुआ था। इसने निश्चित तौर पर देश की तस्वीर बदली है और उससे भी ज्यादा बदली है लोगों की सोच। गांव साफ होने लगे हैं। खुले में शौच जाने की आदत काफी हद तक खत्म होने लगी है। सोलह राज्य पूरी तरह शौचमुक्त घोषित हो चुके हैं। कई जिलों और गांवों में इसके क्रियान्वयन या जागरूकता के लिए अलग-अलग तरीके से काम हो रहे हैं, ये खास तरीके चर्चित भी हो रहे हैं।

**स्व**च्छ भारत अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर, 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर पांच सालों के लिए की गई थी। अभियान का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। जाहिर-सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश में करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों को बनाने के लिए एक लाख चाँतीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य है। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल को पूँजी का रूप देकर उसे जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। इस अभियान को बड़े स्तर पर ग्रामीण आबादी और ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से जोड़ा जा रहा है।

'निर्मल भारत' अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा ऐसा अभियान है, जो मांग-आधारित एवं जन-केंद्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाया जाए। स्व-सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध

कराया जाए। ऐसा होने पर ग्रामीणों का जीवन-स्तर खुद-ब-खुद बेहतर हो जाएगा। गांव न केवल स्वच्छ होंगे बल्कि काफी हद तक बीमारियों से मुक्त भी हो जाएंगे।

सरकार ने मार्च 2018 में लोकसभा में बताया कि वर्ष 2015–16 में 47,101, वर्ष 2016–17 में 1,36,981 और वर्ष 2017–18 में 1,39,478 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए।

## ओडीएफ गांवों में इजाफा

ओडीएफ गांवों की संख्या में लगातार जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ओडीएफ का मतलब है खुले में शौच से मुक्त। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का पैमाना आवश्यक रूप से शौचालय का इस्तेमाल है यानी जिस ग्राम पंचायत, जिला या राज्य (सभी ग्रामीण) के सभी परिवारों के सभी लोग शौचालय इस्तेमाल करते हों। ओडीएफ को चार-स्तरीय सत्यापन से गुजरना पड़ता है। पहले ब्लॉक-स्तर, फिर जिला, फिर राज्य-स्तर के अधिकारी और आखिर में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारी सत्यापन करते हैं।



## खुले में शौच से कौन-सी बीमारियां फैलती हैं

मानव मल पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है। मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। एक ग्राम मानव मल में रोगों के इतने वाहक हो सकते हैं—

1,00,00,000 वायरस

10,00,000 बैक्टीरिया

1000 परजीवी पुटी/अंडाणु

100 परजीवी अंडे

खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, रोहा, हुक वार्म, मलेरिया, फालेरिया, पीलिया, टिटनस आदि बीमारियां हो सकती हैं।

### किस तरह बढ़ रही है स्वच्छता

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2018 तक करीब 6 करोड़ 13 लाख घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। पिछले दो सालों में ओडीएफ गांवों की संख्या 2,69,565 यानी 572 फीसदी (करीब 6.7 गुना) बढ़ी है। आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2015 के बाद से तीन सालों में रोजाना करीब 51 हजार शौचालय गांवों में बन रहे हैं। वर्ष 2016 से रोज करीब 370 गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।

कई जिलों और गांवों में इसके क्रियान्वयन या जागरूकता के लिए अलग-अलग तरीके से काम हो रहे हैं, ये खास तरीके चर्चित भी हो रहे हैं।

### अलग तरह से काम करने वाले लोग

मसलन महाराष्ट्र में सोलापुर जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉ. निशि गंधा माली गांवों का दौरा करती रहती हैं। पंचायत सदस्यों, स्कूली बच्चों, अधिकारियों, नागरिकों से मिलती हैं। वो बहुत असरदार तरीके से लोगों को इसके फायदे और जरूरतों के बारे में बताती हैं। उन्होंने तब तक कि उनका जिला खुले में शौचरहित ना हो जाए। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में एक स्कूली बच्चे ने गांवों के ऐसे लोगों के नामों को चिन्हित करते हुए गांव की खास जगहों पर इश्तहार लगाया। इस नए विचार ने अपने अभियान में सफल होने में समुदाय की मदद की। हिमाचल में कोठी ग्राम पंचायत के महिला मंडल ने कचरा प्रबंधन के लिए एक नई चीज शुरू की। ये लोग घरों से पॉलिथीन इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके कचरा उठाने के लिए बैग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सड़कों के किनारे पेड़ों पर टांग दिया जाता है, ताकि लोग सड़कों पर गंदगी करने से बचें। रांची नगर निगम ने खुले में शौच करने वाले के खिलाफ 'हल्ला बोल, लुंगी खोल' अभियान छेड़ा। इसके तहत निगम अधिकारी खुले में शौच करते लोगों को पकड़ते और उनकी

लुंगी जब्त कर लेते।

मंडी में ग्राम पंचायत—स्तर पर विकास निधि स्थापित की गई है, जिसमें घरों की संख्या के हिसाब से सात से 20 लाख रुपये तक की राशि इकट्ठी हो गई है। इस निधि का उपयोग गांवों में शौचालय, खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे या बारिश के पानी के लिए नालियां विकसित करने के लिए किया जाता है, अवार्ड भी दिए जाते हैं। मंडी जिले में लगभग 70 हजार सदस्यों वाले 4,490 महिला मंडल हैं, जो गांवों में सफाई सुनिश्चित करने के साथ लोगों को संपूर्ण स्वच्छता और जल संरक्षण का महत्व समझाते हैं। मंडी को वर्ष 2016 में केंद्र ने सबसे साफ—सुथरा पहाड़ी जिला घोषित किया था।

बिहार के गया के एक गांव में स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर एक परिवार की बहू ने घर में शौचालय बनाने के लिए अपने गहने निकाल कर सास को सौंप दिए। बहू की सोच को सही मानते हुए उनकी सास ने उसके गहने लौटा दिए और घर में दूध देने वाली गाय को बेचकर शौचालय बनवा कर ही दम लिया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण और अच्छा काम करने वालों की सूची तैयार की जा सकती है।

### 16 राज्य खुले में शौचमुक्त

जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तब जम्मू—कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखण्ड और ओडिशा में 30 प्रतिशत से कम शौचालय थे। हालांकि आज कोई राज्य इस श्रेणी में नहीं है। अलबत्ता बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में शौचालय निर्माण की प्रगति धीमी है। यहां अभी 30—60 प्रतिशत घरों में ही शौचालय बनवाए जा सके हैं। राजस्थान खुले में शौचमुक्त की श्रेणी में आ चुका है। जम्मू—कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखण्ड में 60 से 90 प्रतिशत तक शौचालय बनवाए जा चुके हैं। अभियान की शुरुआत के समय केवल केरल ही ऐसा राज्य था जो खुले में शौचमुक्त था। आज इस श्रेणी में 16 राज्य आ चुके हैं। करीब साढ़े छह लाख गांवों में से साढ़े तीन लाख से अधिक गांव खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं।

### समाज में फैल रही है जागरूकता

राष्ट्रीय—स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धि शानदार रही है। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि बिहार, उत्तर प्रदेश

### कैसे करा सकते हैं शौचालय का निर्माण

**शौचालय निर्माण:** (i) बेसलाइन सर्वे में जिसका नाम हो वह व्यक्ति स्वच्छता अधिकारी के पास नाम दर्ज कराता है। (ii) अधिकारी निर्माण शुरू करने की मंजूरी की रसीद देता है। (iii) 45—50 दिन में निर्माण पूरा करना होता है। (iv) बने शौचालय में पानी की टंकी, रोशनी की व्यवस्था, दरवाजा होना जरूरी है। (v) काम पूरा होने की सूचना के बाद अधिकारी रसीद लेकर 12,000 की प्रोत्साहन राशि जारी करता है।

## 2019 तक 80 फीसदी साफ हो जाएगी गंगा

गंगा की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष मार्च तक नदी का 80 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ हो जाएगा। हम मार्च 2019 तक 70 से 80 प्रतिशत गंगा के स्वच्छ होने की उम्मीद करते हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि गंगा के किनारे सक्रिय 251 सकल प्रदूषण उद्योग (जीपीआई) को बंद कर दिया गया है। 938 उद्योगों और 211 मुख्य 'नालों' में प्रदूषण की 'रियल-टाइम मॉनिटोरिंग' पूरी हो चुकी है, जो नदी को प्रदूषित करते हैं। अब परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलकर इसके क्रियान्वयन का काम शुरू करना है।



नमामि गंगे परियोजना कोई साधारण परियोजना नहीं है बल्कि ये उस नदी की सफाई से ताल्लुक रखती है जो 2,500 किमी. लंबी है। ये 29 बड़े शहर, 48 कर्बे और 23 छोटे शहरों को कवर करती है। भारत के पांच राज्य उत्तराखण्ड, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी के रास्ते में आते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये परियोजना काफी चुनौतीपूर्ण है। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी एनएमसीजी नाम का प्रोजेक्ट बनाया है। एनएमसीजी ने पिछले दो सालों में गंगा की सफाई के 16.6 अरब रुपये की राशि खर्च की है। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के मुताबिक गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 67 अरब रुपये की रकम आवंटित की है। ये आंकड़ा अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच का है। गंगा नदी की सफाई के लिए अगर सरकार अपने स्तर पर जुटी हुई है तो आम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो देश की पुण्य सलिला की सफाई को लेकर जागरूक हों। इस तरह का काम राज्य सरकारें भी लगातार कर रही हैं। वहीं ये भी जरूरी है कि ये जिन शहरों, गांवों और कस्बों से होकर गुजरती है, वहां का स्थानीय प्रशासन भी इसकी सफाई में अहम भूमिका निभाए।

जैसे राज्यों में आखिर कौन-सी समस्याएं सामने आ रही हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। चूंकि ये सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, लिहाजा उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। वैसे ये बात सही है कि स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीणों की सोच को बदला है। गांवों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है; ये शुभ संकेत भी हैं। अगर समाज संघेत है, तो वो अपनी व्यवस्था भी कर लेता है। गंदगी की तरफ वो खुद ध्यान देने लगता है।

### बढ़ी सहायता राशि

अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3000 रुपये होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10800 होगी जिसमें राज्य

का योगदान 1200 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

### सरकार की इच्छाशक्ति नजर आ रही है

मोदी सरकार अगले साल गांधी जी की 150वीं जयंती को यादगार बनाना चाहती है। इसीलिए वो देश को खुले में शौचमुक्त बनाने के इरादे से काम कर रही है। पिछली सरकारों ने भी ऐसी योजनाएं चलाने की कोशिश की थीं लेकिन वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई थी जिस तरह मौजूदा स्वच्छ भारत अभियान शक्ति ले रहा है। 1999 में भारत सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को नए सिरे से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में लांच किया था। बाद में मनमोहन सिंह के शासनकाल में इसका नाम बदल कर 'निर्मल भारत अभियान' कर दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इसमें कुछ बदलाव करके इसे 'स्वच्छ भारत अभियान' नाम दिया। बहुत से देशों में गंदगी फैलाने की आदत को सुधारने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। हमारे यहां वैसा तो नहीं है लेकिन अब स्वच्छता कर (सेस) जरूर है।

## विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सतत विकास के राष्ट्रीय प्रयासों तथा पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस वर्ष का थीम है—**प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।** इस वर्ष भारत को विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान भी बनाया गया है।

वन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1972 से दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष का थीम लोगों को प्रकृति से जोड़ना था। इस दौरान प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर हरियाली को बढ़ावा देने तथा सभी प्रकार के अपशिष्ट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए।

प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय-स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, महिला और युवा संगठनों को पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संबंधित समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने में लगभग 12000 संगठन शामिल हैं।

देश भर के 4000 शहरों में विशाल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत इन शहरों में कूड़ा एकत्र करने के नीले और हरे रंग के डिब्बे वितरित किए गए तथा आम लोगों को अपनी जीवनशैली में स्वच्छता की संस्कृति अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सरकार का उद्देश्य मूल स्थान पर ही सूखे और गीले कूड़े को अलग-अलग करने में लोगों की आदत में बदलाव लाना है ताकि तदनुसार कूड़े का प्रबंधन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि भारत के सिक्किम में गंगटोक में स्थित मावलिन्नांग में पॉलीथीन पर प्रतिबंध है; थूकना मना है। रास्तों पर कूड़े का नामों—निशां नहीं मिलता; कूड़ा फेंकने के लिए बांस के बने कूड़ेदान हैं; रास्ते के दोनों ओर फूल—पौधे हैं; स्वच्छता का निर्देश देते बोर्ड हैं। इस गांव को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा भी मिल कर चुका है। अगर हम स्वच्छता हासिल करने की संस्कृति विकसित करेंगे और उसे जारी रखने के लिए नए कदम उठाएंगे, तभी हम गांधीजी के उस सपने को साकार कर सकेंगे, जो उन्होंने स्वच्छता के लिए देखा था।

### जुटे हैं सांसद भी

पिछले कुछ महीनों से सरकार ने इसके लिए सभी सांसदों से गोद लिए गए गांवों में इस अभियान की अगुवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सांसदों से गांवों के 'समग्र विकास' के लिए पंचायत-स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध भी किया। हालांकि अच्छी बात यही है कि सरकार की योजना लगातार जारी है और इसमें उसकी पूरी इच्छाशक्ति भी नजर आ रही है। इसलिए इसमें लगातार प्रगति भी दिख रही है।



किसी भी योजना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उससे आम लोगों को कैसे जोड़ा जाता है तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि गांवों में लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि हर घर में शौचालय होना न केवल जरूरी है बल्कि अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना आवश्यक है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)  
ई-मेल : [sanjayratan@gmail.com](mailto:sanjayratan@gmail.com)

## जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति—2018

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति—2018 को मंजूरी दे दी है।

### मुख्य विशेषताएं

- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथनॉल और जैव डीजल तथा "विकसित जैव ईंधनों" – दूसरी पीढ़ी (2जी) इथनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे – भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
- अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति की मंजूरी से इथनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- जैव ईंधनों के लिए, नीति में 2जी इथनॉल जैव रिफाइनरी के लिए 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की निधियन योजना के लिए व्यावहारिकता अंतर का संकेत दिया गया है।
- नीति गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गाभ फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति शृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया।
- इन प्रयासों के लिए नीति दस्तावेज में जैव ईंधनों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिग्रहण किया गया है।



### संभावित लाभ

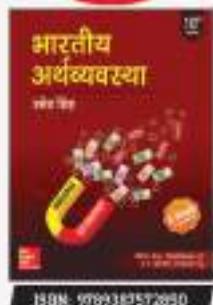
- आयात निर्भरता कम होगी :** एक करोड़ लीटर ई-10 वर्तमान दरों पर 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर इथनॉल की आपूर्ति दिखाई देने की उम्मीद है जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- स्वच्छ पर्यावरण :** एक करोड़ लीटर ई-10 से करीब 20,000 हजार टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। वर्ष 2017-18 इथनॉल आपूर्ति के लिए कार्बन-डाई-ऑक्साइड 30 लाख टन उत्सर्जन कम होगा। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव ईंधनों में बदलकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी।
- स्वास्थ्य संबंधी लाभ :** खाना पकाने के लिए तेल खासतौर से तलने के लिए लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है और अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- एमएसडब्ल्यू प्रबंध :** एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष 62 एमएमटी निगम का ठोस कचरा निकलता है। ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो कचरा/प्लास्टिक, एमएसडब्ल्यू को ईंधन में परिवर्तित कर सकती हैं। ऐसे एक टन कचरे में ईंधनों के लिए करीब 20 प्रतिशत बूंदें प्रदान करने की संभावना है।
- ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश :** एक अनुमान के अनुसार 100 केएलपीडी जैव रिफाइनरी के लिए करीब 800 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बारह 2जी रिफाइनरियां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। साथ ही देश में 2जी जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- रोजगार सृजन :** एक 100 केएलपीडी 2जी जैव रिफाइनरी संयंत्र परिचालनों, ग्रामीण-स्तर के उद्यमों और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में 1200 नौकरियां देने में योगदान दे सकती हैं।
- किसानों की अतिरिक्त आय :** 2जी प्रौद्योगिकियों को अपना कर कृषि संबंधी अवशिष्टों/कचरे को इथनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे अन्यथा किसान जला देते हैं। साथ ही, अतिरिक्त उत्पादन चरण के दौरान उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अतः अतिरिक्त अनाजों को परिवर्तित करने और कृषि बॉयोमास मूल्य स्थिरता में मदद कर सकते हैं। □

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2018

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उत्तम पुस्तकें

₹ 640/-



₹ 415/-



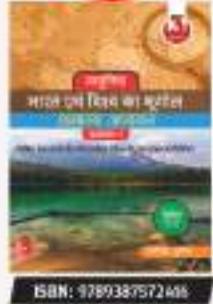
₹ 505/-



₹ 465/-



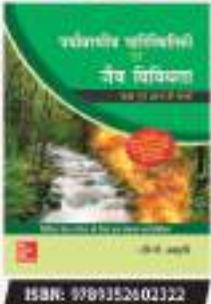
₹ 345/-



₹ 475/-



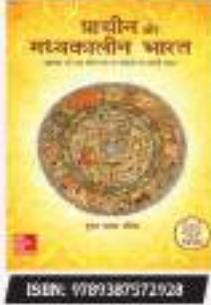
₹ 415/-



₹ 345/-



₹ 435/-



₹ 475/-



Prices are subject to change without prior notice.

### सामाजिक अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)

के निःशुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें  
[www.mheducation.co.in/upscsamplepapers](http://www.mheducation.co.in/upscsamplepapers)

मेक्स्ट्रो हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

टोल फ्रोन: 1800 103 5875 | ई-मेल: support.india@mheducation.com | सरोदे@www.mheducation.co.in

संपर्क करें: /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia



## ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट

**प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना** इस योजना के तहत मार्च, 2018 तक कुल 1,52,165 बसावटों को सङ्करण मार्ग से जोड़ा गया है जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है। पिछले चार वर्षों में बसावटों को सङ्करण मार्ग से जोड़ने के काम में 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013–14 में 75 कि.मी. प्रतिदिन के हिसाब से सङ्करण निर्माण हो रहा था जो 2017–18 में बढ़कर 134 कि.मी. प्रतिदिन हो गया। हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग से 6313 कि.मी. सङ्करणों का निर्माण हुआ है। सरकार ने वर्ष 2022 तक पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के अंतर्गत 1.07 लाख कि.मी. सङ्करण का लक्ष्य रखा है।



**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2019 तक 1 करोड़ और वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 2018 तक 51 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 44 लाख 53 हजार मकानों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा और मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज मिस्ट्रियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 12,500 को राजमिस्ट्री का प्रशिक्षण देकर प्रमाणपत्र सौंपे गए।

**मनरेगा—आजीविका सुरक्षा से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना**—‘मनरेगा’ में प्रत्येक परिसम्पत्ति की जियो टेगिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से पूरी पारदर्शिता आई है। इस योजना की इस आधार पर आलोचना की जाती थी कि इसके काम लंबे समय तक अधूरे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से खराब गुणवत्ता की परिसंपत्तियों का सृजन हो पाता है और आजीविका सुरक्षा भी संतोषजनक नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान कार्यों को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप वर्ष 2016–17 और 2017–18 में करीब 1 करोड़ 20 लाख परिसंपत्तियों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पहली सितंबर, 2016 से मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो टेगिंग शुरू की गई और अब दैनिक आधार पर लगभग 80 हजार परिसंपत्तियों की जियो टेगिंग की जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3 करोड़ 34 लाख परिसंपत्तियों में से 2 करोड़ 84 लाख से अधिक की जियो टेगिंग कर उन्हें पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर बल दिया जा रहा है। इस साल 40 से 50 लाख हेक्टेयर जमीन जल—संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के दायरे में लाई जा रही है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान हर साल करीब 5 लाख कृषि तालाबों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत सङ्करणों के किनारे वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिन का काम उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत जहां आवश्यक हो, और यह सुविधा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत मिलनी संभव नहीं हो, वहां प्रत्येक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए 12000 रुपये उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व समझते हुए मनरेगा की निधियों का इस्तेमाल आंगनवाड़ी केंद्र की इमारतों के निर्माण पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष के दौरान ऐसी लगभग 20,000 इमारतें बनाई गई हैं। मनरेगा के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्टिंग के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पिछले वित्तवर्ष के दौरान अब तक की सर्वाधिक 64,179 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग किया गया है। अब 86 प्रतिशत से अधिक भुगतान समय पर हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत 12 करोड़ 56 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 10 करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है और 6 करोड़ 58 लाख को बैंक खातों से लिंक कर दिया गया है। जॉब कार्ड का सत्यापन कराया गया है और 7 करोड़ 33 लाख जॉब कार्ड सक्रिय पाए गए हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान 1 करोड़ 43 लाख जॉब कार्ड जोड़े गए हैं और 1.62 करोड़ जॉब कार्ड निरस्त किए गए।

**दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** वर्ष 2011 में शुरूआत के बाद से योजना का विस्तार 29 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों तक कर दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वसहायता समूहों की संख्या लगभग 40 लाख हो गई है। इनमें लगभग 2 लाख 20 हजार ग्राम संगठन और 19 हजार क्लस्टर परिसंपत्ति हैं। वित्तीय समावेश के तहत मिशन ने महिला स्वसहायता समूहों को 1,51000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिलाने में मदद की है।

**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 से फरवरी, 2018 तक 5,70,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 3,48,000 लोगों को काम दिलाया गया है। वर्ष 2017–18 में 1,28,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 69,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए।

पिछले 4 वर्षों में केवल मनरेगा, आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है। □

## स्वच्छता सर्वेक्षण 2018

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तत्वाधान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आयोजन किया था। इसमें 4203 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया। 2700 मूल्यांकन—कर्मियों ने पूरे देश के 40 करोड़ लोगों से संबंधित स्थानीय निकायों का सर्वेक्षण किया। यह कार्यक्रम 4 जनवरी, 2018 से 10 मार्च, 2018 तक जारी रहा। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के दौरान 53.58 लाख स्वच्छता ऐप डाउनलोड किए गए तथा 37.66 लाख नागरिकों के फीडबैक का संग्रह किया गया। वर्ष 2016 में 73 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण का संचालन किया गया था। इसमें मैसूरु को सर्वाधिक स्वच्छ नगर होने का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण का संचालन किया गया और इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार दिया गया।

एक स्वतंत्र एजेंसी ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य किया है। इसके लिए 3 स्रोतों से आंकड़े जुटाए गए।

ए. सेवा—स्तर में हुई प्रगति

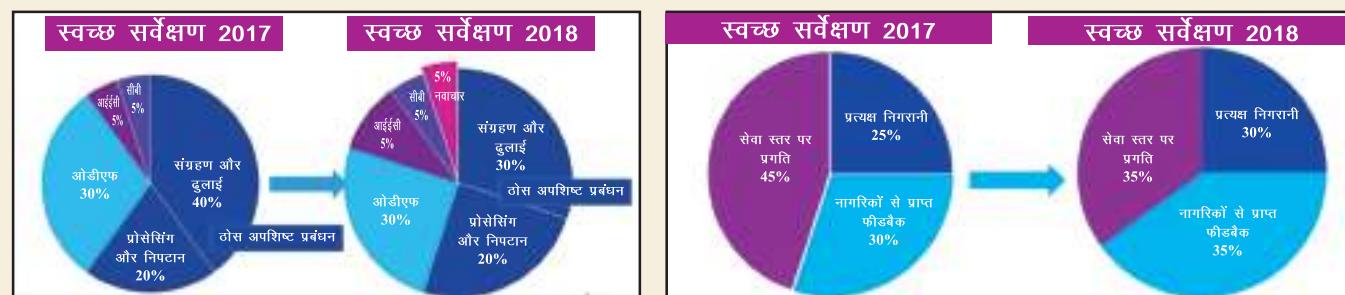
बी. प्रत्यक्ष निरीक्षण

सी. नागरिकों का फीडबैक

2017 की तुलना में स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की प्राथमिकता में बदलाव हुआ है जो निम्न है—

सेवा—स्तर प्रगति के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में एक और घटक जोड़ा गया है—नवोन्मेष और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली

इस सर्वेक्षण में नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों के फीडबैक तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का फोकस था— स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की पहलों के परिणाम, नवोन्मेष तथा सत्तता।



## स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण

स्वच्छ भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने तथा कैरियर लाभ अर्जित करने के लिए देश के युवाओं के लिए एक विशिष्ट योजना, स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र एवं एनवाईकेएस के सदस्य अब 15 जून, 2018 तक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई, 2018 थी। देश भर के युवकों को, विशेष रूप से उन महाविद्यालयों के छात्रों, जो शैक्षणिक मामलों एवं परीक्षाओं में व्यस्त होंगे, पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकरण की तारीख को बढ़ाया गया है।

छात्र एवं एनवाईकेएस के युवा अब पोर्टल ([www.sbsi.mygov.in](http://www.sbsi.mygov.in)) पर लॉग इन कर स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षितों को गांव में स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर कम से कम 100 घंटे व्यतीत करने की आवश्यकता है। इससे वे स्वच्छ भारत प्रमाणपत्र पाने के योग्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2018 को प्रसारित ‘मन की बात’ में स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण (एसबीएसआई) के लांच की घोषणा की थी।

## आगामी अंक

### जुलाई, 2018 : पंचायती राज